Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज Published from Ranchi
Ranchi ● Saturday, 17 May 2025 ● Year : 03 ● Issue : 121 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com
E-Paper : epaper.thephotonnews.com

सुविचार

बहुत कम यादें पछतावे से अछूती होती हैं।

–कृष्ण बलदेव वैद

Karisma Kapoor's Birthday Wish For...

SHARE

सेंसेक्स	:	82,330.59
निफ्टी	:	25,019.80

SARAFA

सोना	:	8,895
चांदी	:	108.0

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

24 मई को होगी नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक

NEW DELHI : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की शासी परिषद की 24 मई को होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि शासी परिषद की इस बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं,जबकि शासी परिषद नीति आयोग का शीर्ष निकाय है। सभी मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। आम तौर पर शासी परिषद की पूर्ण बैठक हर साल होती है। पिछले साल यह बैठक 27 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई थी।

माउंट एवरेस्ट शिखर से उतरते समय भारतीय पर्वतारोही की हुई मौत

KATHMANDU : विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर से उतरते समय ऊंचाई संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होने के बाद एक भारतीय पर्वतारोही की मौत हो गई। शुक्रवार को एक मीडिया रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है। हिमालयन टाइम्स अखबार की खबर के अनुसार, मृतक पर्वतारोही की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी सुब्रत घोष (45) के रूप में हुई है। घोष, 8,848.86 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट अभियान के दौरान दम तोड़ने वाले दूसरे विदेशी हैं। खबर के अनुसार, स्नोई होराइजन ट्रेक्स के प्रबंध निदेशक (एमडी) बोधराज भंडारी ने बताया कि घोष की मृत्यु माउंट एवरेस्ट के शिखर बिंदु के पास हिलेरी स्टैप के ठीक नीचे हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ नई याचिकाओं पर सुनवाई से किया इनकार

NEW DELHI : शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दो नई याचिकाओं की पड़ताल करने से मना करते हुए कहा, हर कोई अखबारों में अपना नाम देखना चाहता है। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि वह 20 मई को सुनवाई के लिए आने वाले लंबित विषय पर फैसला करेगी। इसके बाद, शीर्ष अदालत मामले में अंतरिम राहत के विषय पर सुनवाई करेगी। इनमें से एक याचिका शुक्रवार को सुनवाई के लिए आने पर, केंद्र की ओर से न्यायालय में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाएं अनंत काल तक दायर नहीं की जा सकतीं।

डिजिटल क्रांति से सशक्त हुईं राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाएं : हेमंत सोरेन

- प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने सेविकाओं को दिए स्मार्टफोन
- राज्य की 37,810 आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिला मोबाइल

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड राज्य डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जहां तकनीक विशेष रूप से मोबाइल स्मार्टफोन, महिला सशक्तीकरण और समाज कल्याण की दिशा में नई संभावनाएं खोल रही है। शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति से आंगनबाड़ी सेविकाएं सशक्त हुईं है। इसका परिणाम आने वाले दिनों में दिखेगा। बता दें कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा हाल ही में राज्य की 37,810 आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन प्रदान किए गए हैं। इसका उद्देश्य सेवा वितरण को पारदर्शी, प्रभावी और डाटा संचालित बनाना है।

स्मार्टफोन से बढ़ा आत्मविश्वास

काके प्रखंड की सरिता कुमारी सुकरुहुटू आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन मिलने से मेरे कार्यों में आत्मविश्वास आया है। अब मैं स्वयं लाभार्थियों की तस्वीरें खींच सकती हूं, आधार प्रमाणीकरण कर सकती हूं और टीएचआर जैसी सेवाएं समय पर दे सकती हूं।

योजनाओं की हो रही निगरानी

स्मार्टफोन के माध्यम से दर्ज किए गए आंकड़ों के आधार पर जिला और राज्य स्तर पर योजनाओं की प्रगति की निगरानी की जा रही है। यह न केवल सेवा वितरण में पारदर्शिता लाता है, बल्कि बुनियादी ढांचे के सुधार और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में भी मदद करता है।

कार्य निष्पादन में बनीं आत्मनिर्भर

स्मार्टफोन ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को न केवल तकनीकी रूप से सशक्त किया है, बल्कि उन्हें कार्य निष्पादन में आत्मनिर्भर भी बनाया है। पहले जहां सेविकाएं दूसरों के फोन पर निर्भर थीं, वहीं अब वे स्वयं लाभार्थियों का डेटा वास्तविक समय में अंकित कर रही हैं। इस तकनीकी पहल का प्रत्यक्ष प्रभाव राज्य में आईसीडीएस सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ा है। मार्च 2023 में आधार सत्यापित लाभार्थियों की संख्या 17,44,100 (48.03%) थी, जो मार्च 2025 तक बढ़कर 30,11,829 (97.22%) हो गई है।

12 गांवों में खुलेगा नया आंगनबाड़ी केंद्र

सरकार ने 1,200 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों की पहचान की है, जहां नए आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से जनजातीय समुदायों को पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा की सेवाएं दी जा रही हैं। जल्द ही इन केंद्रों में सेविका और सहायिका की नियुक्तियां भी की जाएंगी। झारखंड में आंगनबाड़ी केंद्र अब मात्र सेवा वितरण केंद्र नहीं, बल्कि सामुदायिक विकास और महिला सशक्तिकरण के केंद्र बन चुके हैं।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद आक्रामक राजनयिक अभियान को आगे बढ़ा रही सरकार

विदेश जाएंगे भारत के सांसद पाकिस्तान को करेंगे बेनकाब

कई देशों में जाएंगे विभिन्न दलों के एमपी, विस्तार से रखेंगे अपना पक्ष

- विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों या उनके सदस्यों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं
- भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, द्रमुक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी), जनता दल (यूनाइटेड), बीजू जनता दल, माकपा और कुछ अन्य दालों के सांसद प्रतिनिधिमंडल में होंगे शामिल
- 10 दिनों के लिए विभिन्न देशों का दौरा करेंगे प्रतिनिधिमंडल के सदस्य
- विदेश मंत्रालय इस राजनयिक मिशन के लिए रवाना होने से पहले सांसदों को देगा पूरी जानकारी

NEW DELHI @ PTI : मोदी सरकार पहलगाम में आतंकवादी हमले के प्रत्युत्तर में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद आक्रामक राजनयिक अभियान के तहत वैश्विक स्तर पर भारत के पक्ष को मजबूती से रखने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए अगले सप्ताह से विभिन्न देशों में कई बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। बता दें कि बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तथा पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। राजनयिक अभियान के लिए मुख्य विपक्षी कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से सरकार ने इसके लिए आह्वान किया है। कुछ दलों ने राजनयिक प्रयास के लिए अपने सदस्यों को भेजने की मंजूरी भी दे दी है। विदेश जाने वाले इन प्रतिनिधिमंडलों या उनके सदस्यों की संख्या को लेकर फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है, हालांकि कुछ नेताओं ने कहा कि 30 से अधिक सांसद हो सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल 10 दिनों की अवधि के लिए विभिन्न देशों का दौरा करेंगे। सांसद सरकार द्वारा निर्धारित देशों का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय इस राजनयिक मिशन के लिए रवाना होने से पहले सांसदों को पूरी जानकारी देगा। सूत्रों ने बताया कि जिन पार्टियों के सांसद प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे उनमें भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी), जनता दल (यूनाइटेड), बीजू जनता दल, माकपा और कुछ अन्य शामिल हैं।

कांग्रेस ने की प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने की पुष्टि

सूत्रों का कहना है कि सरकार की सूची में शामिल कांग्रेस सांसदों में शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और अमर सिंह शामिल हैं और पार्टी ने पुष्टि की है कि वह प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। सूत्रों ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, जद (यू) के संजय झा, बीजद के सस्मित पात्रा, राकांपा (एसपी) की सुप्रिया सुले, द्रमुक की के कनिमोझी, माकपा के जॉन ब्रिटास और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी को भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने के लिए कहा जा रहा है। इस मामले पर फिलहाल सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

भारत के रक्षा बजट में 50 हजार करोड़ की वृद्धि का प्रस्ताव

NEW DELHI : केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट में 50 हजार करोड़ रुपये बढ़ा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे संसद के नवंबर-दिसंबर के दौरान शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि इस फंड से नए हथियार, गोला-बारूद और तकनीक खरीदी जाएंगी। साथ ही सेना की दूसरी जरूरतें, रिसर्च और डेवलमेंट पर भी खर्च किया जाएगा। बढ़ोतरी के बाद रक्षा मंत्रालय का ओवरऑल बजट 7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए गए 2025-26 के बजट में सशस्त्र बलों के लिए रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया था। इस साल रक्षा बजट पिछले साल की तुलना में करीब 9.5% ज्यादा है। केंद्र ने 2024-25 में सशस्त्र बलों के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपये दिए थे। ढट मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के पहले बजट 2014-15 में रक्षा मंत्रालय को 2.29 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने सुनी पाकिस्तान में गिराई गई मिसाइलों की गूंज : राजनाथ

AGENCY NEW DELHI : ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को गुजरात के भुज में स्थित वायु सेना स्टेशन पर वीर वायु योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीं पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए भारतीय वायु सेना के लिए सिर्फ 23 मिनट काफी थे। हमारी एयर फोर्स एक ऐसी स्काइफोर्स है, जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को छू लिया है। जितनी देर में लोग नाश्ता-पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों का निपटारा कर दिया। आपने दुश्मन की सीमा के भीतर जाकर जो मिसाइल गिराई, उसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी।

श्रीनगर के बाद भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री ने वायु योद्धाओं का बढ़ाया हौसला

रक्षा मंत्री ने कहा कि अभी कल ही मैं श्रीनगर में सेना के अपने वीर जवानों से मिलकर लौटा हूं। कल मैं भारत के उत्तरी भाग में जवानों से मिला। आज मैं भारत के पश्चिमी भाग में वायु योद्धाओं और जवानों से मिल रहा हूं। दोनों ही मोर्चों पर हाई एनर्जी और हाई जोश देखकर आश्वस्त हो गया हूं कि भारत की सीमाएं आप सभी की मजबूत भुजाओं में पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा करने की हो रही कोशिश

राजनाथ सिंह ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मुरीदके और बहावलपुर स्थित आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने का एलान किया है। निश्चित रूप से आईएमएफ से आने वाले एक बिलियन डॉलर के बड़े हिस्से को इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। क्या यह अंतरराष्ट्रीय संस्था से अप्रत्यक्ष वित्तपोषण नहीं माना जाएगा। आपने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार, पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैश-ए- मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब चौदह करोड़ रुपये देने में खर्च करेगी।

वज्रपात की चपेट में आए सीआरपीएफ के कमांडेंट की मौत, तीन की हालत नाजुक

PHOTON NEWS CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सारंडा के बालिबा में गुरुवार शाम 5.30 बजे घने जंगल में बने सीआरपीएफ-26 बटालियन के कैंप पर वज्रपात हो गया था, जिसकी चपेट में आकर 4 जवान घायल हो गए थे। इनमें सीआरपीएफ के सेकेंड कमांडेंट एम प्रोबो सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि, तीन अन्य घायल जवानों की हालत भी नाजुक बनी हुई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची भेजा गया है। जिले के एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि नक्सली अभियान के दौरान सारंडा में वज्रपात हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी एम प्रोबो सिंह, सहायक कमांडेंट सुबीर कुमार मंडल, झारखंड जगुआर के एएसआई सुरेश भगत और एएसआई चंदलाल हांसदा को नोवामुंडी स्थित अनुमंडल अस्पताल व टाटा मेन हास्पिटल में भर्ती कराया गया था। हादसे की सूचना मिलते ही किरीबुरु-मेघाहातुबुरु जनरल अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर और प्राथमिक चिकित्सा सामग्री के साथ राहत टीम रवाना की गई थी।

बोधगया में बौद्ध भिक्षु बनकर रह रहा बांग्लादेशी नागरिक अरेस्ट

PATNA : बिहार के बोधगया में एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा गया है। वह अपनी असली पहचान छुपा कर चोरी छुपे बोधगया के स्लीपिंग बुद्धा मॉनेस्ट्री में बौद्ध भिक्षु बनकर रह रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार बोधगया थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह अपने दल-बल के साथ गश्ती कर रहे थे। यहां स्लीपिंग बुद्धा मॉनेस्ट्री में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांच की गई। बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन में रहने वाले लोगों का सत्यापन किया गया।

टीएसपीसी का सब-जोनल कमांडर दिवाकर गंझू अपने सहयोगी अक्षय गंझू के साथ अरेस्ट

- रांची पुलिस ने चैनगढ़ा गम्हरिया के जंगल से दोनों को किया गिरफ्तार

गिरफ्तारी की जानकारी देते पुलिस अधिकारी ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS RANCHI : प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के खिलाफ रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर चैनगढ़ा गम्हरिया के जंगल में चलाए गए छापामारी अभियान में संगठन के सब-जोनल कमांडर दिवाकर गंझू उर्फ प्रताप जी और उसके सहयोगी अक्षय गंझू उर्फ टीरू को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों किसी बड़ी नक्सली वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे और राहगीरों को रोककर मोबाइल की जांच कर मारपीट कर रहे थे।

पुलिस उपमहानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची और पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक खलारी और थाना प्रभारी बुढ़मू के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल गठित किया गया। टीम ने गम्हरिया जंगल की घेराबंदी कर दिवाकर और अक्षय को हथियार और नक्सली साहित्य के साथ दबोच लिया। उनके कई साथी जंगल का लाभ उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से 2 देसी पिस्तौल, 6 गोलियां, टीएसपीसी के पर्चे, 5 मोबाइल फोन, 4 जियो राउटर, 3 पावर बैंक, 4 चार्जर समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। दिवाकर गंझू करीब 15 वर्ष पूर्व टीएसपीसी में शामिल हुआ था।

अलर्ट नियम का उल्लंघन कर तेज गति से कार चलाने पर होगी कार्रवाई

वाहनों की स्पीड मापने के लिए अब रडार सिस्टम का होगा उपयोग

PHOTON NEWS RESEÔRCH DESK : लगभग रोजाना देखने और सुनने को मिलता हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में सड़क हादसे बड़ी संख्या में होते हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने की वजह से भी ये हादसे होते हैं और लोगों की जान चली जाती है। सड़क सुरक्षा और लोगों की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में बड़े परिवर्तन की घोषणा की है। वाहन चालन के समय इन नियमों का सख्ती से सभी को पालन करना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बहुत पहले से सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार की ओर से अब एक बड़ा कदम उठाया गया है। सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए और ट्रैफिक की दिक्कतों को कम करने के लिए एक नया उपकरण लाया गया है। वाहन की गति को मापने के लिए अब रडार सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। सरकार ने विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम 2011 के अंतर्गत वाहनों की गति मापने वाले रडार के लिए नियम नोटिफाई किए हैं। इसे एक जुलाई से लागू किया जाएगा।

नए उपायों से प्रौद्योगिकी, विश्वसनीयता व कानूनी जवाबदेही को मिलेगा बढ़ावा

- हादसों को रोकने या कम करने के लिए केंद्र सरकार ने की कारगर पहल
- विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन, एक जुलाई से लागू होंगे नए नियम
- सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए बनाया गया नया उपकरण
- तकनीकी और सभी सुरक्षा जरूरतों का पूरा करते हैं न्यू रूल्स

माइक्रोवेव डॉपलर रडार उपकरण

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बयान में कहा कि नए नियम लागू होने से उद्योगों और प्रवर्तन एजेंसियों को प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। ये सड़कों पर वाहनों की गति मापने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले माइक्रोवेव डॉपलर रडार उपकरण पर लागू होंगे। ये नियम विस्तृत तकनीकी और सुरक्षा जरूरतों का पूरा करते हैं। ऐसे उपायों से प्रौद्योगिकी विश्वसनीयता और कानूनी जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। उपकरणों को सत्यापन से गुजरना होगा और तैनाती से पहले आधिकारिक सत्यापन और मुहर हासिल करनी होगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य गति और दूरी माप के लिए सटीक आंकड़ों की गारंटी देना है, जो यातायात कानून लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन नियमों के कार्यान्वयन से सभी पक्षों को कई लाभ मिलेंगे।

- नए प्रावधानों के अनुपालन के लिए उद्योगों व प्रवर्तन एजेंसियों को मिलेगा पर्याप्त समय

रोका जा सकेगा अनुचित दंड

आम लोगों के लिए रडार आधारित गति माप उपकरणों का अनिवार्य सत्यापन और स्टाम्पिंग, गति सीमाओं के सटीक प्रवर्तन को सुनिश्चित करेगा, जिससे अनुचित दंड को रोका जा सकेगा और सड़क सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उद्योगों के लिए विशेष रूप से रडार आधारित गति मापन उपकरणों के विनिर्माण में शामिल उद्योगों के लिए नए नियम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक स्पष्ट तकनीकी और नियामकीय ढांचा स्थापित करते हैं।

मणिपुर में आठ उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और विस्फोटक बरामद

IMPHAL : मणिपुर में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए अलग-अलग अभियानों में आठ उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किया है। मणिपुर पुलिस के प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि सुरक्षाबलों ने थौबल जिले के हीरोक पार्ट-क्क्क के खेतलमानबी लाउकोन इलाके से प्रीपाक (प्रो) संगठन के कैडर लैशराम ननाओ सिंह उर्फ अचुल उर्फ रोगेन (39) को गिरफ्तार किया। उसके पास से .303 राइफल, चार संशोधित सिंगल बोर राइफल, 54.303 राउंड, 14 राउंड 7.62 मिमी सहित कई सामान बरामद हुआ।

43 डिग्री के पार पहुंचा पलामू का पारा

- मौसम के मिजाज में उतार-चढ़ाव जारी, आज से राहत की उम्मीद
- कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड में मौसम के मिजाज में उतार-चढ़ाव जारी है। दिन में चिलचिलाती धूप से तापमान बढ़कर 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। पलामू में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने 17 मई से गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार, 17 मई को राज्य के पश्चिमी जिलों को छोड़कर शेष हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बारिश होने के बाद तपमान में कमी आने की उम्मीद है।

राज्य के कुछ जिलों में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। राज्य के जिन जिलों में तापमान 41 डिग्री के करीब पहुंच गया है। इनमें गढ़वा 41.8, गोड्डा 41.6 और सरायकेला-खरसांवा में तापमान 41.9 डिग्री शामिल हैं। कुछ जिलों में तापमान 40 डिग्री के करीब है। इनमें जमशेदपुर में 39.5, चाईबासा 39.4, चतरा 39.2, हजारीबाग 39 डिग्री तथा जामताड़ा में अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बता दें कि मौसम विभाग ने पूर्व में ही मई के अंतिम हफ्ते में राज्य में प्रचंड गर्मी पड़ने की आशंका व्यक्त की थी।

BRIEF NEWS

भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा

KHUNTI : पहलगाम में बेकसूर पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले के विरोध में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश के वीर सैनिकों के सम्मान में शुक्रवार को खूंटी में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें राजनेता, समाजसेवी, व्यापारी, विद्यार्थी सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस संबंध में भाजपा के पूर्व विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से भाजपा न केवल ऑपरेशन की सफलता को जन-जन तक पहुंचाना चाहती है, बल्कि देशवासियों में राष्ट्रप्रेम और एकता की भावना को भी जगाना चाहती है। पार्टी ने सभी कार्यकताओं, सभी इकाइयों, देशभक्त नागरिकों सहित दानी पब्लिक स्कूल और स्पिरिंगडेल पब्लिक स्कूल प्रबंधन को इस तिरंगा यात्रा में सक्रिय भागीदारी के लिए बधाई दी है। तिरंगा यात्रा में राज्यसभा के पूर्व सांसद और अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, राज्य के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, पूर्व विधायक कोचे मुंडा, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य संतोष जायसवाल, भाजपा के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता, शशि पाण्डेय, राखी कश्यप, विमला देवी, विनोद जयसवाल, मुकेश जयसवाल सहित कई लोग शामिल थे।

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर 45 यूनिट रक्तदान

JAMSHEDPUR : टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच) ने शुक्रवार को धूमधाम से अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया। इस अवसर पर अस्पताल में एक सप्ताह तक कार्यक्रम हुए, जिनका उद्देश्य नर्सिंग स्टाफ की अटूट निष्ठा और सेवा भावना को सम्मानित करना था। इस वर्ष की थीम- हमारी नर्सें- हमारा भविष्य। इसी अवसर पर टीएमएच में रक्तदान शिविर लगा, जिसमें स्वास्थ्य सेवा के सभी वर्गों के कर्मी, विशेषकर नर्सिंग छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस शिविर में कुल 45 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। रक्तदाताओं में आधी हिस्सेदारी महिला रक्तदाताओं की थी, यह एक दुर्लभ और प्रेरणादायक उपलब्धि थी, जिसे उपस्थित अधिकारियों ने भी सराहा। सप्ताह भर चले कार्यक्रमों का मुख्य आकर्षण एक विशेष समारोह रहा, जिसकी अध्यक्षता डी. बी. सुंदरा रामम, वाइस प्रेसिडेंटइ्स कॉरपोरेट सर्विसेज, टाटा स्टील ने की। कार्यक्रम में टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी की भी उपस्थिति रही। इस आयोजन में टाटा मेन हॉस्पिटल की नर्सिंग स्टाफ, टाटा वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारीगण, विभिन्न विभागों के एचओडी तथा वरिष्ठ अधिकारियों सहित कुल 850 से अधिक लोगों ने सहभागिता की। यह समारोह नर्सिंग समुदाय की अदम्य सहनशक्ति, निष्ठा और करुणा को समर्पित एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि थी। अपने संबोधन में सुंदरा रामम ने नर्सों द्वारा निभाई जा रही अग्रिम पंक्ति की नेतृत्वकारी भूमिका और उनकी निःस्वार्थ सेवा की प्रशंसा की। वहीं संजीव चौधरी ने नर्सिंग स्टाफ के स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करते हुए उनके प्रति निरंतर समर्थन और सम्मान की आवश्यकता पर बल दिया।

गिरिडीह में नक्सलियों के डंप से मिला हथियारों का जखीरा

एसएलआर व इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर भी मिले

पत्रकारों को बरामद सामानों की जानकारी देते एसपी व सीआरपीएफ के अधिकारी ● फोटोन न्यूज

AGENCY GIRIDIH : नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सीआरपीएफ के जवान लगातार कार्रवाई कर रहे है। इसी क्रम मे शुक्रवार को जिले के नक्सल प्रभावित खुखरा थाना इलाके के चतरो के कानाडीह और गार्दी के घने जंगल मे छिपाकर पानी टंकी (डंप) में रखे विस्फोटक पदार्थ और हथियारों को पुलिस ने बरामद किया है। बरामद पानी टंकी से हथियार और कारतूस के साथ विस्फोटक पदार्थ जब्त किये गये। खुखरा थाना इलाके से मिले सफलता के बाद एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एएसपी सुरजीत कुमार और सीआरपीएफ 154 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट दलजीत सिंह भाटी ने प्रेसवार्ता कर कहा की सुरक्षाबलों ने छापेमारी कर जमीन के अंदर दबाकर रखी गई पानी टंकी को निकाला। जिसमे कई बंदूके, देशी कट्टा, सेमी आटोमेटिक कट्टा सहित कई हथियार और विस्फोटक पदार्थ जब्त किये गये । बरामद सामानों में 12 राइफल, एक डबल बैरल गन, एक एसएलआर, दो वायर कटर, तीन मैगजीन पाउच, आठ इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 14 बंडल कोडेक्स वायर, दो देसी कट्टा, एक सेमी राइफल सहित कई अन्य सामान शामिल है।

स्कॉर्पियो से हो रही थी नकली शराब की तस्करी 680 बोतल के साथ तस्कर किया गया गिरफ्तार

RAMGARH : झारखंड से नकली शराब की तस्करी बिहार राज्य में अक्सर होती रहती है। रामगढ़ पुलिस ने ऐसे ही एक नकली शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 680 बोतल नकली शराब बरामद हुआ है। इस मामले की जानकारी शुक्रवार को रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। एसपी अजय कुमार ने बताया कि एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो बी आर 01 पी बी 6620 से अवैध नकली शराब की तस्करी होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर रामगढ़ थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी शुरू की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान मायाटुंगरी मंदिर के सामने सफेद रंग का स्कॉर्पियो को आते देख रूकने का ईशारा किया तो वाहन का चालक पुलिस को देखकर वाहन खड़ा कर भागने लगा। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत सकरा थाना क्षेत्र निवासी अशोक कुमार से पुलिस ने पूछताछ की। उसने बताया कि वह नकली शराब की तस्करी अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई महीनो से कर रहा था।

पुलिस गिरफ्त में तस्कर व मामले की जानकारी देते एसपी अजय कुमार

बिहार आई बैंक ट्रस्ट का नाम बदलें : राज्यपाल

RANCHI : राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में शुक्रवार को बिहार आई बैंक ट्रस्ट की राज भवन में बैठक हुई। बैठक में ट्रस्ट की वर्तमान गतिविधियों, भावी योजनाओं और संगठनात्मक स्वरूप पर विस्तृत चर्चा की गई। राज्यपाल ने उक्त अवसर पर कहा कि झारखंड राज्य के गठन को दो दशक से अधिक समय बीत चुका है, इसके बावजूद ट्रस्ट का नाम अब भी 'बिहार आई बैंक ट्रस्ट' ही है। उन्होंने इसके नाम में शीघ्र परिवर्तन के लिए निर्देशित किया। राज्यपाल ने सभी ट्रस्टी से कहा कि यह ट्रस्ट लोगों को बेहतर नेत्र उपचार की सुविधा उपलब्ध कराकर समाज में एक विशिष्ट पहचान स्थापित करे। उन्होंने कहा कि बिहार आई बैंक ट्रस्ट नेत्र रोगों के उपचार एवं नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए जन-जागरूकता कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दें। राज्यपाल ने कहा कि उनके द्वारा बरेली में प्रतिवर्ष नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है और हजारों लोगों के नेत्र का निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाता है।

बहू ने ससुर पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, बुजुर्ग ने की खुदकुशी

AGENCY PALAMU : बहू की ओर से महिला थाने में शिकायत करने के बाद 55 वर्षीय ससुर ने फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। यह घटना जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के तेनुडीह गांव के धनीडीह टोला में हुई। महिला ने अपने ससुर पर प्रताड़ित और मारपीट करने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा दिया है। मृतक की पहचान लालमोहन विश्वकर्मा के रूप में हुई है। मृतक की बड़ी बहू शिवानी देवी, पति बीरेंद्र विश्वकर्मा ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि ससुर उसे लगातार प्रताड़ित करते हैं और मारते-पीटते हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने

लालमोहन को थाने में बुलाया और घंटों बैठाए रखा। लालमोहन से पूछताछ के बाद शाम को उन्हें पुत्र बीरेंद्र विश्वकर्मा के साथ घर भेज दिया। मृतक के पुत्र ने बताया कि उनके पिता रात को सामान्य रूप से घर पहुंचे और खाना खाकर सो गए। शुक्रवार सुबह देर तक कमरे से पिता के नहीं निकलने पर पुत्र ने दरवाजा खटखटाया। जब कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर लालमोहन का शव फंदे से लटका मिला। परिजनों ने तुरंत छतरपुर पुलिस को सूचना दी। सब इंस्पेक्टर अशोक टोप्पो दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि क्या मामला है हमलोग जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है।

झारखंड के 15 बाल वैज्ञानिक जाएंगे दिल्ली

RANCHI : स्कूली शिक्षा और एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान की ओर से राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी सह प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता इंस्पायर अवॉर्ड-मानक के अंतर्गत अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, जिला स्कूल में शुक्रवार को आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ 15 बाल वैज्ञानिकों के प्रदर्श को राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित किया गया। प्रतियोगिता में कुल 139 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इसके पूर्व विज्ञान प्रदर्शनी का उदघाटन मुख्य अतिथि निदेशक प्राथमिक शिक्षा शशि प्रकाश सिंह ने किया। वहीं नोडल पदाधिकारी सह आरडीडीइ नीलम आईलिन टोप्पो ने कार्यक्रम के उद्देश्य और झारखंड की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उन्होंने नये प्रयोग करने पर जोर दिया। इस अवसर पर उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा अलका जायसवाल, जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार सिंह, जैक सदस्य भरत बड़ाईक ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

महिला विवि ने मनमाने ढंग से बीएड छात्राओं को बांटे स्कूल

JAMSHEDPUR : शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत बीएड प्रशिक्षुओं के अभ्यास पाठ के लिए स्कूल आवंटन को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें बीएड कॉलेजों के प्रतिनिधि और विद्यालय आवंटन समिति के चार सदस्य शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य सत्र 2023-25 के प्रशिक्षुओं को स्कूल कैसे आवंटित किए जाएं, इस पर चर्चा करना था। बैठक में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब कुछ बीएड कॉलेजों ने जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के बीएड विभाग पर बिना समिति की स्वीकृति के स्कूल आवंटन करने का आरोप लगाया। कॉलेजों ने कहा कि जेसीईआरटी का आदेश सभी संस्थानों पर लागू होता है, लेकिन महिला विवि का बीएड विभाग मनमानी कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर महिला विवि अपनी मर्जी से स्कूल बांट सकता है, तो वे भी ऐसा क्यों न करें। इस पर उपायुक्त ने महिला विवि के प्रतिनिधियों से पूछा कि उन्होंने समिति की अनुमति के बिना स्कूल कैसे आवंटित कर दिए। डीसी ने यह भी आपत्ति जताई कि सभी छात्राओं को निजी स्कूलों में भेजा गया, जबकि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। डीईओ से जेसीईआरटी के निदेशों की कॉपी मंगाई गई। डीसी ने कहा कि पहले वे निदेशों का अध्ययन करेंगे, फिर संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर ही स्कूल आवंटन पर फैसला लिया जाएगा। जांच में यह बात सामने आई कि महिला विवि पिछले चार साल से डीईओ की मिलीभगत से बिना समिति की स्वीकृति के स्कूल आवंटन कर रहा है।

जरूरतमंदों को प्राथमिकता के साथ दें सरकारी योजनाओं का लाभ : उपायुक्त

डीसी की अध्यक्षता में कल्याण विभाग व आईटीडीए से संचालित विकास योजनाओं की हुई समीक्षा

PHOTON NEWS LATEHAR : उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को समेकित जनजाति विकास अभिकरण (आईटीडीए) एवं कल्याण विभाग से संचालित योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की कार्य प्रगति की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई।

उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग एवं आईटीडीए से संचालित योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करें, ताकि अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। आगे उन्होंने कहा कि निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप

समाहरणालय सभागार में बैठक करते उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता (दाएं)

योजनाओं का क्रियान्वयन हो, इसे सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि पदाधिकारी एवं कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता योजनाओं की गुणवत्ता की जांच करें। विशेष प्रमंडल से संचालित योजनाओं की समीक्षा एवं प्रगति की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, बिरसा आवास योजना, कब्रिस्तान, घेराबंदी, छात्रावास निर्माण समेत अन्य विभागीय योजनाओं में अधतन प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने अब तक हुए मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, छात्रवृत्ति भुगतान की जानकारी लेते हुए शत-प्रतिशत छात्र-छात्राओं को छात्रवृति से आच्छादित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने आवासीय विद्यालय, छात्रावास का निर्माण एवं जीर्णोद्धार की समीक्षा किया और जीर्णोद्धार कार्य को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया।

बैठक में आईटीडीए निदेशक प्रवीण कुमार गगराई, सिविल सर्जन डॉ. अवधेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल कमलेश कुमार एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे।

अभिजीत ग्रुप का टावर कटिंग कर वाहन में लोड करते पांच गिरफ्तार

RANCHI : रांची के मांडर थाना पुलिस ने सकरा में अभिजीत ग्रुप के हाईटेंशन तार के लोहे के पोल (टावर) कटिंग कर वाहन में लोड करते पांच अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में मांडर थाना क्षेत्र के सकरा निवासी हफीजुल अंसारी, साहिद अंसारी, लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के ब्रहमणी निवासी मो० रसीद अंसारी, बालूमाथ थाना क्षेत्र के मुरगांव निवासी सुनील गंझु और बुधु गंझू का नाम शामिल है। इनके पास से पिकअप (ओडी24जी 7126) उसपर लोड में 22 गैस सिलेन्डर, पिकअप (जेएच03के8542) पर लोड टावर का कटिंग किया हुआ एंगल, पिकअप (जेएच03वी 0347) पर टावर का कटिंग किया हुआ एंगल और पिकअप (जेएच01एफके3221) पर टावर का कटिंग किया हुआ एंगल लोड जब्त किया गया है। शुक्रवार को डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि शुक्रवार को करीब 1:40 बजे सूचना मिली कि माण्डर थाना क्षेत्र के ग्राम सकरा से दक्षिण दिशा स्थित खेत में अभिजीत ग्रुप के जरिये लगाया गया हाईटेंशन तार के लोहे के पॉल (टावर) को कुछ अज्ञात अपराधी काट कर बेचने के लिए पिकअप वाहन में लोड कर रहे है।

गिरिडीह में पुलिस ने दो साइबर अपराधियों को किया अरेस्ट

AGENCY GIRIDIH : पुलिस ने देश के विभिन्न राज्यो में 15 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले दो शातिर साईबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि एसपी डॉ बिमल कुमार को मिली गुप्त सूचना पर साइबर डीएसपी आबिद खान ने दोनों शातिरों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को डीएसपी आबिद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि एसपी को जानकारी मिली कि गांडेय थाना इलाके के पंदनाटाड़ निवासी रफाउल अंसारी और मो. समीर अंसारी के द्वारा कई राज्यों के लोगों को ठगा गया है और अभी भी दोनों यही काम कर रहे हैं। जानकारी के बाद टीम गठित करते हुए गिरिडीह के बेंगाबाद थाना अन्तर्गत बेरगी रेलवे ब्रिज (जामबाद, लालपुर टोला) के पास

पुलिस गिरफ्त में साइबर अपराधी

से दोनों को गिरफ्तार कर इनके पास से सात मोबाइल, 11 सिमकार्ड, तीन एटीएम और पैन कार्ड बरामद किया गया है। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद दोनों ने पूछताछ के क्रम में साइबर ठगी का जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि दोनों अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को फोन कर केवाईसी अपडेट करवाने के नाम पर ठगी करते है। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक एवं बंधन बैंक का एपीके फाइल भेज कर भी लोगों के साथ ठगी करते है। बताया गया कि दोनों को जेल भेज दिया गया। डीएसपी आबिद खान ने बताया कि दोनों के खिलाफ यूपी, बिहार, पंजाब, छतीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्य में 15, 16 मामले दर्ज है।

बॉर्डर पर वन भूमि में ईंट भट्ठे का हो रहा संचालन

इसी स्थान पर चलाया जा रहा भट्ठा ● फोटोन न्यूज

PALAMU : पलामू जिले के तरहसी और नावाजयपुर थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाके में स्थित कनौदी और सोनपुरवा गांव में वर्षों से अवैध रूप से ईंट भट्ठे का संचालन किया जा रहा है। इस भट्ठे का संचालन वन भूमि पर हो रहा हैं, लेकिन वन विभाग चुप्पी साधे हुए है। कनौदी गांव के संजय कुमार सिंह की ओर से 25 वर्ष से ईंट भट्ठे का संचालन करने की जानकारी सामने आयी है। इतने लंबे समय के बावजूद वन विभाग इस ईंट भट्ठे पर कार्रवाई नहीं कर क्षेत्र का आकलन करने में जुटा है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो विभागीय लापरवाही के कारण वन भूमि का दोहन लगातार जारी है और इसके पर्यावरणीय दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। जब इस संबंध में संजय सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिस भूमि पर भट्ठा संचालित हो रहा है, वह जीएम लैंड (सरकारी भूमि) है। यह भी दावा किया कि भूमि कनौदी निवासी झरी महतो और सकेंद्र साव के नाम पर बंदोबस्त है और उन्हीं की अनुमति से वह भट्ठा चला रहे हैं। नावाजयपुर क्षेत्र के प्रभारी वनपाल रामाशीष कुमार से शुक्रवार को बातचीत की गई, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि की प्रकृति को लेकर विभाग के पास कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं हैं। वन विभाग के सीमांकन पिलर मौजूद न होने के कारण अभी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि भूमि वन क्षेत्र की है या नहीं।

केंद्र सरकार ने दिया मानसून से पहले बांटने का आदेश, तीन माह का अग्रिम राशन करना है वितरित

धनबाद को मिला 2.70 लाख क्विंटल अनाज

PHOTON NEWS DHANBAD : मानसून आने से पहले राशन कार्डधारकों के लिए अच्छी खबर है। 15 जून तक सभी कार्डधारकों को तीन माह के अग्रिम राशन का वितरण होगा। इस दिशा में जिला आपूर्ति विभाग की ओर से वितरण कार्य शुरू भी कर दिया गया है। पहले चरण में 31 मई तक जून और जुलाई का अनाज वितरण होगा, जबकि 15 जून तक अगस्त का भी अनाज सभी कार्डधारकों को दिया जाएगा। इसे लेकर विभाग की ओर से सभी जनवितरण दुकानदारों का राशन उठाव करने और वितरण करने का आदेश दिया गया है। इसके तहत कुल 2.70 लाख क्विंटल राशन का वितरण किया जाना है।

18.70 लाख उपभोक्ता

धनबाद जिले में जन वितरण प्रणाली के तहत राशन प्राप्त करने वाले कुल कार्डधारक 4.40 लाख हैं और इस पर कुल 18.70 हजार सदस्यों तक राशन पहुंचता है। जबकि इनमें से करीब 98 हजार ऐसे कार्डधारक हैं जो छह माह से लेकर पांच साल से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं।

15 जून तक करना होगा वितरण

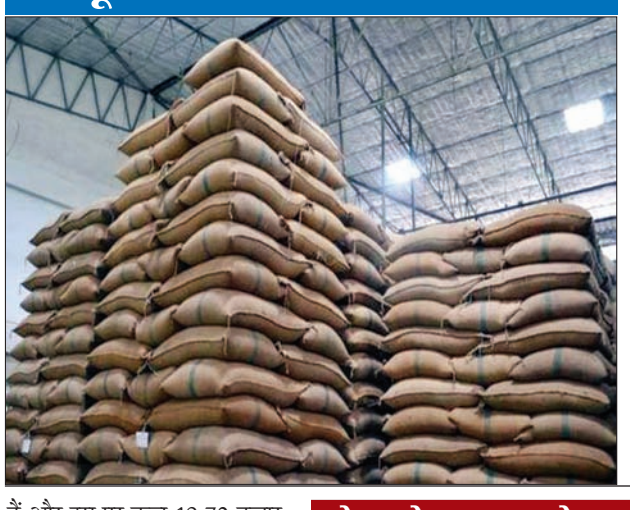

> विभागीय आदेश के अनुरूप खाद्यान्न के उठाव, भंडारण और वितरण को लेकर कार्य शुरू कर दिया गया है। सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों और जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को आदेश निर्गत किया जा चुका है। हर माह के राशन वितरण के लिए अलग-अलग बायोमीट्रिक लिया जाना है।
>
> – प्रदीप शुक्ला, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद

गोदाम के आसपास के भवनों में भी होगा भंडारण

आपूर्ति विभाग की ओर से राज्य खाद्य आपूर्ति निगम को यह आदेश दिया गया है कि अतिरिक्त अनाज के भंडारण के लिए सरकारी गोदामों के अलावा आसपास के सरकारी भवनों का चयन भी करना है। पैक्स के गोदामों को भी लिया जाना है।

पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा कल जमशेदपुर में बनाए गए 12 केंद्र

JAMSHEDPUR : झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (जेसीईसीईबी) द्वारा 18 मई को पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा होगी। इसके लिए जमशेदपुर में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 7507 परीक्षार्थियों के शामिल होने का अनुमान है। जमशेदपुर के साथ ही रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, चाईबासा, दुमका और पलामू सहित राज्य के आठ जिलों में भी आयोजित होगी। परीक्षा ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट पर सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक एक पाली में ली जाएगी। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक और गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग की जाएगी। परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित से कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया गया है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in से प्रवेशपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2025-26 में सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में इंजीनियरिंग-डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेशपत्र और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाएं।

इन सेंटरों पर होगी परीक्षा

केंद्र का नाम : परीक्षार्थियों की संख्या	
एलबीएसएम कॉलेज :	1080
करीम सिटी कॉलेज :	1068
कोआपरेटिव कॉलेज :	1056
दयानंद पब्लिक स्कूल :	727
ग्रेजुएट कॉलेज :	720
जेकेएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स :	552
आरकेएम लेडी इंदर सिंह हाईस्कूल :	552
गुरुनानक हाईस्कूल गोलमुरी :	456
आदिवासी हाईस्कूल सीतारामडेरा :	384
एबीएम कॉलेज गोलमुरी :	360
सिस्टर निवेदिता गर्ल्स हाईस्कूल :	288
शारदामणि गर्ल्स हाईस्कूल साकची :	264
कुल :	7507

BRIEF NEWS

फुटपाथ दुकानदारों के पक्ष में संजय सेठ ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

RANCHI : केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र के जरिये उन्होंने मोरहाबादी में सब्जी और फल बेचने वाले फुटपाथ दुकानदारों पर हुई अमानवीय कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय से यहां फुटपाथ पर सब्जी और फल की दुकान लगाई जा रही है, परंतु दो दिन पूर्व इन दुकानदारों पर की गई कार्रवाई मानवता को शर्मसार करने वाली है। वहां से सैकड़ों परिवारों का लालन-पालन होता है। लोग फल-सब्जी बेचकर अपना घर चलाते हैं। उन्हें स्थायित्व प्रदान करने के बजाय यह कार्रवाई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इन दुकानदारों में ज्यादातर संख्या ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोगों की रहती है। कई ग्रामीण किसान खुद की उपजाई सब्जी, फल और फसल बेचने के लिए यहां आते हैं।

भाजपा के नेता लगातार कर रहे सेना का अपमान : कांग्रेस

RANCHI : भाजपा के नेता लगातार देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने इसे लेकर एक अभियान छेड़ रखा है। यह बातें प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सोनाल शांति ने शुक्रवार को कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि देश की सेना और सैनिक मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। यह बात पूरी तरह बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने कहा कि सेना के शौर्य और विजय का श्रेय लूटने के फेर में प्रधानमंत्री की चापलूसी करने की सारी सीमाओं को भाजपा नेता लांघ चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि चापलूसी की ओलंपिक प्रतिस्पर्धा होती तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदकों के साथ भाजपा के चापलूसवीर पहले पायदान पर होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं का राजनीतिक और चारित्रिक संस्कार पूरे देश के सामने प्रतिदिन उजागर हो रहा है। पहले मंत्री विजय शाह ने सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया।

एनएसएपी के वार्षिक भौतिक सत्यापन को लेकर हुई बैठक

RANCHI : राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) एवं राज्य प्रायोजित पेंशन योजनाओं के लाभुकों के वार्षिक भौतिक सत्यापन को लेकर शुक्रवार को पंचायत सचिवालय बेड़ो में बैठक हुई। अध्यक्षता पंचायत की मुखिया सुशांति भगत ने की। प्राप्त निर्देश के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं राज्य सरकार की पेंशन योजनाओं के सभी लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन 30 मई तक अनिवार्य रूप से कर जिला समाज कल्याण कार्यालय को प्रतिवेदित करना है। इसी क्रम में पंचायत सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने पंचायत क्षेत्र के सभी लाभुकों का निर्धारित प्रपत्र पर सत्यापन कर संबंधित कार्यालय को समर्पित करें।

पीवीटीजी समुदाय की सेहत पर हेमंत सरकार कर रही स्पेशल फोकस

मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकृत किए 5.90 करोड़ रुपये

PHOTON NEWS RANCHI : हेमंत सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने में जुटी है। मरीज को अपने आसपास में ही बेहतर इलाज मिले इसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के लिए 5.90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इससे क्लिनिक का संचालन किया जाएगा। यह योजना राज्य के सभी 24 जिलों में लागू की जाएगी, जहां पीवीटीजी समुदायों की संख्या अधिक है।

दो हिस्से में बांटा गया बजट : इस योजना के तहत कुल दो हिस्सों में बजट को विभाजित किया गया है। पहले भाग में 11 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, साहिबगंज, लोहरदगा, खूंटी, गुमला और चाईबासा को कुल 2 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। वहीं दूसरे भाग में बचे हुए 13 जिलों बोकारो, सरायकेला-खरसावां, देवघर, पलामू, गिरिडीह, गोड्डा, गढ़वा, कोडरमा, पाकुड़, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और सिमडेगा को कुल 3.90 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

» सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले पीवीटीजी समुदायों को समय पर मिलेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं

» समुदाय के कुपोषण, बीमारी और मृत्यु दर को कम करना है लक्ष्य

इस कार्य में खर्च की जाएगी राशि

इस बजट के माध्यम से जिलों में चलंत स्वास्थ्य क्लिनिक के संचालन, मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति, आवश्यक उपकरणों की खरीद और आदिम जनजातियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिला स्तर पर संबंधित सिविल सर्जन को व्ययन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, जो राशि के उपयुक्त उपयोग और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले पीवीटीजी समुदायों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जिससे उनमें कुपोषण, बीमारी और मृत्यु दर को कम किया जा सके।

14 साइट्स पर डेंगू और चिकनगुनिया का हो रहा मुफ्त इलाज

RANCHI : राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर शुक्रवार को राज्य भर में डेंगू से बचाव को लेकर विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस वर्ष का थीम शीघ्र कार्रवाई करें, डेंगू को रोकें, स्वस्थ परिवेश, स्वस्थ जीवन है। इसका उद्देश्य लोगों को डेंगू से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करना और स्वच्छता की आदतें विकसित करना है। इस दौरान बताया गया कि राज्य में वर्तमान में 14 सेंटिनल साइट्स कार्यरत हैं, जहां डेंगू व चिकनगुनिया की मुफ्त जांच व उपचार की सुविधा उपलब्ध है। 2023 की तुलना में 2024 में डेंगू के मामलों में गिरावट आई है। 2023 में जहां 12.42% मरीज पाए गए थे, वहीं 2024 में यह घटकर 10.68% रह गया। पिछले वर्ष चार मौतें हुई थीं, लेकिन इस वर्ष कोई मौत दर्ज नहीं हुई है।

एडीस मच्छर से फैलता है डेंगू

डेंगू एडीस मच्छर के काटने से फैलने वाला वायरल रोग है, जो बरसात के मौसम में अधिक सक्रिय होता है। इसे रोकने के लिए टीकाकरण उपलब्ध नहीं है, इसलिए जन-सहभागिता और स्वच्छता ही प्रमुख बचाव हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में प्रभात फेरी, रैली, ग्राम गोष्ठी, क्विज व चित्रांकन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। स्वास्थ्य कार्यकताओं ने लोगों को मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने की जानकारी दी।

सदर में भी किया गया जागरूक

सदर में जागरूकता के दौरान सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए किसी प्रकार का टीका या दवा उपलब्ध नहीं है। डेंगू से बचाव हेतु जनजागरूकता और मच्छरों के प्रजनन स्थल को नष्ट करना आवश्यक है। जिले में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विभिन्न गांवों और स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि 2025 में अभी तक कुल 491 डेंगू के संभावित मरीजों की जांच की गई, जिसमें 14 डेंगू, 12 को-इन्फेक्शन और 5 चिकनगुनिया के रोगी पाये गये हैं, सभी स्वस्थ हो चुके हैं।

प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के हटाई दुकानें : बाबूलाल मरांडी

PHOTON NEWS RANCHI : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मोरहाबादी मैदान से बिना किसी पूर्व सूचना के दुकानों को हटाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यहां गरीब और आदिवासी समाज के सैकड़ों लोग दुकान लगाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं लेकिन देर रात नगर निगम और लालपुर थाना की टीम ने बगैर किसी पूर्व सूचना के सभी दुकानों को ध्वस्त कर दिया।

मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को लिखा कि यदि दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था तो उन्हें नोटिस देकर दुकान खाली करने का निर्देश दिया जा सकता था लेकिन आधी रात को की गयी कार्रवाई प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी रांची के ही मेन रोड में एकरा मस्जिद से डेली मार्केट तक सड़क पर हजारों दुकानें लगती हैं, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित होता है और आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री बताएं कि आपका प्रशासन इन जगहों पर अतिक्रमण हटाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाती?

उन्होंने कहा कि मोरहाबादी मैदान के पास प्रशासन द्वारा गैरकानूनी ढंग से गरीब, आदिवासियों की दुकानों को क्षति पहुंचाई गई है। डीसी रांची तत्काल नुकसान का आंकलन कर सभी दुकानदारों को उचित मुआवजा उपलब्ध कराते हुए उनके पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

चैंबर ने ईएसआईसी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा

PHOTON NEWS RANCHI : अध्यक्ष परेश गट्टानी के नेतृत्व में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को नामकुम स्थित 220 बेड के नवनिर्मित ईएसआईसी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अस्पताल में बीमितों के ईलाज की सुविधा, मरीजों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल की व्यवस्था को चैंबर ने संतोषजनक पाया। 220 बेड के नवनिर्मित अस्पताल के चालू होने से प्रदेश में बीमितों के लिए एक अतिरिक्त ईएसआईसी अस्पताल की सुविधा उपलब्ध होने पर प्रतिनिधिमंडल ने संतोष व्यक्त किया। इस क्रम में ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशक राजीव रंजन के साथ वार्ता भी की गई। मौके पर चेंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने अस्पताल से सटे हुए भूखंड पर 50 सीट वाले मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस भूखंड का उपयोग मेडिकल कॉलेज खोलने में करना चाहिए। इससे बीमितों के ईलाज की सुविधा में बढोत्तरी के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षा में प्राथमिकता मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन भी होगा।

अस्पताल में बातचीत करते चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी व अन्य ● फोटोन न्यूज

छात्रों को खुद के अंदर सफलता की भूख जगाने की जरूरत : शिल्पी नेहा तिर्की

एसएस प्लस टू उच्च विद्यालय बेड़ो में 62 लाख रुपये की लागत से 10 कमरे वाले भवन का कृषि मंत्री ने किया शिलान्यास

PHOTON NEWS RANCHI : रांची के बेड़ो एस एस प्लस टू उच्च विद्यालय में अब भवन के अभाव में छात्रों का नामांकन नहीं रुकेगा। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 10 कमरों वाले भवन निर्माण योजना की सौगात छात्रों को दी है। प्रांगण में करीब 62 लाख रुपये की लागत से तैयार होने वाले भवन का शिलान्यास मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। बता दें कि ये वहीं एस एस प्लस टू उच्च विद्यालय है जिसके छात्रों ने भवन, पानी और शौचालय के अभाव में प्रखंड कार्यालय का घेराव किया था। परिसर में पानी और शौचालय की समस्या का समाधान पहले ही किया जा चुका है। शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि शिक्षा जीवन का आधार है। अनुशासन। धैर्य और त्याग की बदौलत सफलता को हासिल किया जा सकता है। इसके लिए छात्रों को खुद के अंदर सफलता की भूख को पैदा करना होगा।

फोन के बजाय किताबों से करें दोस्ती

कृषि मंत्री ने कहा कि क्लास रूम एजुकेशन छात्रों के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए विद्यालय में छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में कमरा होना चाहिए। बदलते हुए दौर में आज गांव के अंदर शिक्षित छात्रों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब शिक्षा विशेष वर्ग तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि शिक्षा हर वर्ग की जरूरत बन गई है। उन्होंने छात्रों से मोबाइल फोन के बजाय किताबों से दोस्ती करने की सलाह दी। शिलान्यास कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य बेरोनिका उरांव, उप प्रमुख मुदसिर हक, सुशांति भगत, बीडीओ राहुल उरांव, सीओ प्रताप मिंज, प्रखंड अध्यक्ष करमा उरांव, नवल सिंह, मीर मुस्लिम आदि मौजूद थे।

गुरुजी के विचारों से भटक गया झामुमो : सुदेश

PHOTON NEWS RANCHI : आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि गुरुजी शिबू सोरेन के मूल सोच और विचारधारा से झामुमो भटक चुका है। गुरुजी शराब को समाज के लिए घातक मानते थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि खनिज संसाधनों से भरेझपूरे राज्य में शराब बेचकर राज्य का खजाना भरने की बात हेमंत सरकार कर रही है। सुदेश ने यह बातें शुक्रवार को पार्टी के हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कथनी और करनी में भेद दिख रहा है। पेसा कानून के संबंध में भी राज्य सरकार का रवैया स्पष्ट नहीं है। सुदेश ने कहा कि पेसा कानून को हुबहू लागू किया जाना चाहिए ताकि जनता की भावनाओं का सम्मान हो सके। उन्होंने कहा कि जेपीएससी को पटरी पर लाने में सरकार विफल रही है। इससे राज्य के युवाओं में आक्रोश है।

इससे पूर्व आजसू पार्टी के मिलन समारोह में कई बुद्धिजीवी और युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। सुदेश महतो और झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर ने पार्टी का पट्टा पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। पार्टी में शामिल होने वालों में संजय साहू, डॉ अमित कुमार साहू, डॉ अभिषेक झा, डॉ अंबुज मिश्रा, मोहित गोप, रोहित प्रजापति, सुभाष गोप, देवेंद्र साहू, अमित साहू सहित अन्य शामिल हैं।

देशवासियों को अपनी बहादुर सेना पर गर्व : सुप्रियो

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भटटाचार्य ने भाजपा पर देश की सेना को अमर्यादित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हम सभी देशवासियों को अपनी बहादुर सेना पर गर्व है, लेकिन भाजपा के नेता बार-बार सेना का अपमान कर रहे हैं, जिसे भाजपा का शीर्ष नेतृत्व संरक्षण दे रहा है। सुप्रियो शुक्रवार को पार्टी के हरमू स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रेदश के मंत्री बिजय शाह की ओर से की गई सेना पर टिप्पणी पर भाजपा की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनपर मुकदमा दर्ज करना तो दूर उन्हें मंत्रीपरिषद से बर्खास्त? तक नहीं किया गया। सुप्रियो ने कहा कि भाजपा देश की महिला, किसान और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलने के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा नौ किसानों को अपनी गाडी से कुचल देता है, लेकिन उसपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। वहीं भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों पर अत्याचार किया, लेकिन सांसद पर भी भाजपा की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम को धूमिल कर दिया। पाकिस्तासन तीन टुकडों में बंट जाता। यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने राष्ट्रपति से इन मामलों पर हस्तटक्षेप करते हुए कार्रवाई की मांग की।

मारवाड़ी समाज ने फोर्ब्स मैग्जीन सूची में शामिल साक्षी को दी बधाई

PHOTON NEWS RANCHI : रांची की साक्षी जैन को प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन की 30 अंडर- 30 एशिया सूची में शामिल किए जाने पर रांची जिला मारवाड़ी सम्मेलन के पदाधिकारी और सदस्यों ने बधाई दी है। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र अग्रवाल ने साक्षी जैन को बधाई देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एडवरटाइजिंग कैटिगरी-2025 में साक्षी का चयन होना पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि साक्षी ने पूरे विश्व में परचम लहराते हुए पूरे समाज को गौरवान्वित किया है। इस कैटेगरी में 30 नामों मे से दो भारतीय शामिल हैं, जिसमें एक नाम साक्षी जैन का है। उन्होंने कहा कि साक्षी जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंटेंट क्रिएटर हैं। रांची जिला मारवाड़ी सम्मेलन के जिलाध्यक्ष ललित कुमार पोद्दार, महामंत्री विनोद कुमार जैन और संयुक्त महामंत्री सह प्रवक्ता संजय सर्राफ ने बधाई देते हुए कहा है कि साक्षी जैन का फोर्ब्स थर्टी अंडर- 30 एशिया में चयन होना पूरे देश में मारवाड़ी समाज की मान बढ़ा है।

अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प शुरू

रांची-हटिया सहित कई स्टेशनों को बनाया जा रहा हाईटेक

PHOTON NEWS RANCHI : केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पूरे देश में अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत 554 से ज्यादा स्टेशनों के पुनर्विकास का काम शुरू करवाया गया है, जो अब अंतिम चरण पर है। इसी कड़ी में झारखंड के विभिन्न रेल मंडल के 57 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास भी शुरू है। इसमें रांची रेल मंडल के रांची, हटिया, रेलवे स्टेशन समेत कुल 15 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने की दिशा में कदम बढ़ाएं गए हैं। बताते चलें कि रांची रेल मंडल में कुछ 55 रेलवे स्टेशन हैं। इन स्टेशनों को ई, एफ और जी हॉल्ट स्टेशन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस श्रेणी में कुल 20 स्टेशन हैं, ई श्रेणी में 20 स्टेशन, एफ श्रेणी में 9 और जी हॉल्ट स्टेशन श्रेणी में अन्य स्टेशन हैं।

अमृत भारत रेलवे स्टेशन के रूप में 15 स्टेशनों का चयन हुआ है। जिसका काम युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्य रूप से लोहरदगा, बालसिरिंग, गोविंदपुर रोड, बानो, पोरका, नामकुम, गंगाघाट, मुरी, सिल्ली, रामगढ़ कैंट को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन रेलवे स्टेशनों में एस्केलेटर, यात्रियों को बैठने की एसी, नॉन-एसी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, फुटपाथ, कैंटीन, बाजार, सुरक्षा और पार्किंग के अलावा तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। दूसरी ओर रांची और हटिया रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए गए हैं। इन रेलवे स्टेशनों पर वह तमाम सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं, जो सुविधा एयरपोर्ट पर दी जाती है। फ्री वाई-फाई की सुविधा जल्द ही रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

रांची रेलवे स्टेशन पर चल रहा विकास का कार्य ● फोटोन न्यूज

रेल परियोजनाओं के लिए बजट निर्धारित

रांची रेलवे स्टेशन को हाईटेक और वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। बता दें कि झारखंड राज्य के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 7302 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। झारखंड में रेल परियोजनाओं के लिए 52 हजार 885 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसी बजट में पूर्व से चल रही रेल परियोजनाओं का विस्तार होगा 1000 करोड़ रुपए से गोयलकेरा-मनोहरपुर थर्ड लाइन का 40 किलोमीटर का विस्तारीकरण किया जाना है। वहीं ढाई सौ करोड़ रुपये से बंडा मुंडा रांची रेल लाइन के 58 किलोमीटर का विस्तार करने में खर्च किए जा रहे हैं। जबकि 9.50 करोड़ रुपये में रांची लोहरदगा टोरी लाइन की 113 किलोमीटर का विस्तार कार्य लगभग पूरा होने को है। वहीं मुरी-बड़काखाना 58 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण समेत 15 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प भी किया जाना है।

एसआर डीएवी ने ताइक्वांडो में जीते 12 पदक

PHOTON NEWS RANCHI : जिला ताइक्वांडो संघ की ओर से आयोजित एक दिवसीय रांची जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता में एसआर डीएवी पब्लिक स्कूल पुंदाग के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन स्वर्ण पदक, चार रजत पदक तथा पांच कांस्य पदक सहित कुल 12 पदकों पर अपना कब्जा जमाया।

विद्यालय में शुक्रवार को विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को प्राचार्य डॉक्टर तापस घोष की ओर से मेडल पहनाकर सम्मान किया गया। विद्यालय की खिलाड़ी सिमरन रानी, जैना फारुकी, आदित्य तिवारी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं अम्मार अनवर, लक्षिका राज, सीना कुमारी, नंदिनी भारती ने रजत पदक, जबकि आयुर्धा बनर्जी, वर्तिका रानी, प्रियंका बॉयपाई, आकृति सिन्हा और अनुष्का राय ने कांस्य पदक प्राप्त किया।

खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धि पर विद्यालय के प्राचार्य ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि खेल-कूद जीवन का अभिन्न अंग है। वर्तमान समय में इसका महत्त्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके अभ्यास से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहा जा सकता है। प्राचार्य ने कहा कि खेल - कूद के क्षेत्र में सुनहरे भविष्य की संभावनाएं हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्कूल के सभी खिलाड़ी आगे चल कर राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी विद्यालय का नाम रौशन करेंगे।

मां की ममता और समर्पण से संवरता है जीवन : प्रेम रंजन

RANCHI : भारतीय रिजर्व बैंक, रांची क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से मातृ दिवस के उपलक्ष्य में होटल कैपिटल हिल में शुक्रवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुस्तक माई रे पर परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें डॉ रविभूषण, प्रकाश देवकुलिश, प्रमोद कुमार झा, अनिता रश्मि, राकेश कुमार सिंह, पंकज मित्र, उर्वशी, नियति कल्प और अंशुप्रिया ने अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय रिजर्व बैंक, रांची के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन प्रसाद सिंह के उद्घाटन वक्तव्य से हुआ। इस अवसर पर उन्होंने मातृ दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे समाज में मातृत्व के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अनोखा अवसर बताया।

समाचार सार

पुतरु गांव में बनेगी 1.6 किमी. लंबी सड़क

GHATSILA : पुतरु गांव में एनएच-18 से बजीडांगा गांव तक 1.6 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। इसका शिलान्यास शिक्षा मंत्री सह घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने शुक्रवार को किया। मंत्री ने बताया कि सड़क का निर्माण एक करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से होगा। सड़क काफी दिनों से जर्जर थी। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि जसवंत महतो, विधायक प्रतिनिधि जगदीश भकत, प्रखंड अध्यक्ष दुर्गा मुर्मू, काजल डॉन, कालीपदो गोराई, रतन महतो, बाबूलाल मुर्मू, राघवेंद्र शर्मा आदि भी उपस्थित थे।

महाप्रभु जगन्नाथ की देव स्नान यात्रा की तैयारी

GHATSILA : जगन्नाथ सेवा समिति ट्रस्ट, मऊभंडार की ओर से महाप्रभु जगन्नाथ की देव स्नान (कलश) यात्रा 11 जून को होगी। जगन्नाथ सेवा समिति ट्रस्ट, मऊभंडार के पदाधिकारी ने बताया कि इसमें जो भी माताएं-बहनें कलश यात्रा में भाग लेना चाहती हैं, वे मऊभंडार जगन्नाथ मंदिर परिसर में आकर 21 रुपये सहयोग राशि के साथ कूपन ले सकती हैं।

एनसीसी कैडेट बना निर्वाचन आयोग का वॉलंटियर

GHATSILA : संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर के एनसीसी कैडेट जगतराम महतो को निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा मतदाताओं की सहायता करने की वॉलंटियर की जिम्मेदारी मिली है। इसके लिए 19 व 20 मई को आईआईआईडीईएम कैंपस, नई दिल्ली में झारखंड राज्य के वॉलंटियर्स व बीएजी मेंबर्स को दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।

समर कैंप में बच्चों ने खूब की मस्ती

GHATSILA : घाटशिला प्रखंड के कालापाथर स्थित ऐंजल्स गॉर्डन स्कूल में दो दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने खूब मस्ती की। बच्चों ने क्राफ्ट व चित्रकला में भाग लिया, तो फूड स्टॉल और कला प्रदर्शनी का आनंद भी उठाया। इसमें बच्चों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प व कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर प्राचार्य नंदिता अधिकारी, महिमा सरकार, झुमा रानी सीट, गीता सिंह, निशा सिन्हा, प्रियंका सिंकु, अभिषेक राउल, श्याम किशोर बख्शी आदि सक्रिय रहे।

सरायकेला में खुला सांसद कार्यालय

SERAIKELA : सरायकेला स्थित जिला परिषद कार्यालय में शुक्रवार को सांसद जोबा मांझी ने सांसद कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद ने बताया कि वह महीने में दो बार कार्यालय में जनता दरबार लगाएंगी। इससे पूर्व चाईबासा में सांसद कार्यालय खुल चुका है, जबकि जल्द ही गम्हरिया व आदित्यपुर में भी कार्यालय खोला जाएगा। इस अवसर पर झामुमो के जिलाध्यक्ष डॉ. शुभेंदु महतो, गणेश महाली, गणेश चौधरी, कृष्णा बास्के, नगर अध्यक्ष शंभू हाजरा, जॉनी हाजरा, कांग्रेस नेता कालीपद सोरेन समेत काफी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे।

बिजली से हुई दुर्घटना में दो साल बाद मिला मुआवजा

GOILKERA : गोइलकेरा प्रखंड के ग्राम कदमडीहा, टोला इचाहातु में 14 जुलाई 2022 को चुड़ी सुरीन तथा उसकी पत्नी सोमवारी सुरीन की बिजली के तार की चपेट में आकर मौत हो गई थी। दो साल बाद मृतक दंपती की पुत्री लागुरी सुरीन को विधायक जगत माझी ने पांच-पांच लाख रुपये का चेक प्रदान किया। गोइलकेरा प्रखंड कार्यालय में विधायक के साथ विद्युत विभाग के सहायक अभियंता जितेंद्र कुमार भी उपस्थित थे।

क्षत्रिय संघ ने मनाई पृथ्वीराज चौहान की जयंती

JAMSHEDPUR : झारखंड क्षत्रिय संघ की गोविंदपुर इकाई ने शुक्रवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोविंदपुर इकाई के अध्यक्ष अशोक सिंह ने की। इसमें संघ के केंद्रीय अध्यक्ष शंभूनाथ सिंह, महिला इकाई की केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. कविता परमार, केंद्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, बिष्टुपुर अध्यक्ष बीबी सिंह, जुगसलाई अध्यक्ष वाईके सिंह, गोलमुरी अध्यक्ष बच्चा सिंह, टेल्को अध्यक्ष संजय सिंह हितैषी, इकाई के पूर्व अध्यक्ष श्यामकिशोर सिंह, रामनवमी सिंह, आशनंदन सिंह, जलविंदर सिंह, रमन सिंह, जयकुमार सिंह, रंजन सिंह, इंद्रजीत सिंह, मंटू सिंह, बबलू सिंह, जितेंद्र सिंह, चंद्रभान सिंह, सुधीर सिंह, अविनाश सिंह, विकास सिंह आदि भी उपस्थित थे। स्वागत भाषण जिला परिषद के सदस्य डॉ. परितोष सिंह व धन्यवाद ज्ञापन युवा इकाई के अध्यक्ष संतोष सिंह ने किया। इस अवसर पर शंभू सिंह ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को हराया था।

नवविवाहिता ने शादी के 16 दिन बाद ही कर ली खुदकुशी

दहेज प्रताड़ना का लगाया गया आरोप

PHOTON NEWS JSR : सोनारी थाना क्षेत्र स्थित एमपी रोड मकान नंबर आठ में रहने वाली नवविवाहिता ने दहेज की मांग से प्रताड़ित होकर शुक्रवार को खुदकुशी कर ली। महज 16 दिन पहले रिता कुमारी शादी के बंधन में बंधी थी। पुलिस ने मामले में पति, सास और ससुर के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। गम्हरिया चित्रगुप्त नगर निवासी वैद्यनाथ महतो की बेटी रिता की शादी 29 अप्रैल को सोनारी निवासी चंदन महतो से हुई थी। शादी के बाद से ही रिता को उसके ससुरालवालों द्वारा नई बाइक की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। पीड़िता ने इसकी जानकारी कई बार अपने मायके वालों को भी दी थी।

मृतका की फाइल फोटो

रिता के पिता वैद्यनाथ महतो ने थाना में दर्ज कराए बयान में कहा कि दहेज में बाइक न मिलने के कारण उनकी बेटी की हत्या की गई है और बाद में उसे खुदकुशी का रूप देने के लिए फंदे से लटका दिया गया। घटना के समय रिता का पति चंदन काम पर गया हुआ था। इस बीच उसकी मां सावित्री महतो ने फोन कर चंदन को बताया कि रिता ने खुदकुशी कर ली है। सूचना मिलते ही चंदन घर पहुंचा और ससुराल पक्ष की मदद से रिता को फंदे से उतारकर तत्काल टाटा मुख्य अस्पताल (टीएमएच) ले गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद सोनारी थाना पुलिस ने रिता के पिता के लिखित बयान के आधार पर पति चंदन महतो, सास सावित्री महतो और ससुर देवेन महतो के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मेस के रसोइया ने दो छात्राओं के साथ किया दुष्कर्म, गिरफ्तार

SONUA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुवा थाना क्षेत्र में एक निजी मेस में रसोइया ने मेस की दो नाबालिग छात्राओं से दुष्कर्म किया था। मामले का खुलासा होने के बाद सोनुवा में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार, सोनुवा थाना अंतर्गत धोलाबनी गांव में संचालित एक निजी मेस में गुदड़ी थाना के गिरु गांव निवासी विश्वनाथ गोप रसोइया के रूप में काम करता था। इसी दौरान वह मेस में रहने वाली दो नाबालिग छात्राओं के साथ लगातार दुष्कर्म करता था। आरोपी ने दोनों नाबालिग को काफी डरा कर रखा था। बताया जाता है कि रसोइया ने 14 मई को भी दोनों छात्राओं के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद किसी तरह हिम्मत कर नाबालिगों ने 14 मई की शाम को सोनुवा थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस बीच पुलिस ने दोनों नाबालिगों की मेडिकल जांच कराई।

पुलिस गिरफ्त में आरोपी

जमशेदपुर में सिविल डिफेंस 12 जगहों पर लगाएगा सायरन

JAMSHEDPUR : जिला उपायुक्त सह नागरिक सुरक्षा विभाग, जमशेदपुर के नियंत्रक अनन्य मित्तल के निर्देश पर जमशेदपुर शहर में 12 जगहों पर सायरन (खतरा घंटी) लगाया जाएगा। सिविल डिफेंस जमशेदपुर के प्रधान सहायक सुरेश प्रसाद ने बताया कि एयर रेड वार्निंग मैसेज प्राप्त होने होने के पश्चात यह सायरन बजाकर युद्ध की स्थिति में जनता को सावधान करने के लिए बजाया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर 2 मिनट तक लगातार सायरन बजता है, तो सामान्य स्थिति का संकेत होता है। वहीं अगर यह सायरन 2 मिनट तक रुक-रुक कर बजता है, तो यह खतरे का संकेत देता है। इसे बजाकर जनता को सावधान किया जाता है , ताकि युद्ध की स्थिति में जनता पहले से चौकस एवं सुरक्षित रह सके। सुरेश प्रसाद ने कहा कि 17 मई को बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में पूर्व सैनिकों एवं युवाओं को सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक के रूप में जोड़ने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उक्त कार्यक्रम 17 मई को शाम 4 बजे से शाम 7.30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक के रूप में जुड़ने के लिए युवाओं की उम्र सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष तक निर्धारित किया गया है।

हर प्रखंड में सरकार खोलेगी सीबीएसई स्कूल : शिक्षा मंत्री

PHOTON NEWS GHATSILA : झारखंड सरकार सीबीएसई पैटर्न के 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का संचालन कर रही है। इसमें से 64 विद्यालय के विद्यार्थियों ने इस बार मैट्रिक तथा इंटर की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी तरह के स्कूल हर प्रखंड में खोले जाएंगे। ये बातें शुक्रवार को गालूडीह के होटल में राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पत्रकारों से कहीं। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही सीबीएसई पैटर्न का एक स्कूल प्रत्येक प्रखंड में खोलने की योजना बना रही है। जल्द ही इस पर भी काम शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार शिक्षा को लेकर काफी गंभीर है। मंत्री ने कहा कि रघुवर सरकार ने राज्य के लगभग 7000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिया था। हेमंत सरकार ने वैसे विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने की अनुमति दी है। जल्द ही उन विद्यालय को चिह्नित कर खोला जाएगा। झारखंड के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रारंभिक स्तर से मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है। जाति जनगणना के संबंध में मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की यह घोषणा स्वागत योग्य है, परंतु जनगणना के दौरान सरना धर्म कोड का भी कॉलम होना चाहिए, तब जाकर ही झारखंड में जाति जनगणना की जाए। यह भाजपा सरकार की सोची समझी चाल है, ताकि सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन आसानी से हो सके। इस मौके पर झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष दुर्गा मुर्मू, जगदीश भकत, काजल डॉन, कालीपदो गोराई, वकील हेंब्रम सब्यसाची चौधरी, सत्यजीत कुंडू, निर्मल चक्रवर्ती आदि भी उपस्थित थे।

गालूडीह में पत्रकारों को जानकारी देते मंत्री रामदास सोरेन ● फोटोन न्यूज

केयू में 21 को होगी सिंडिकेट की बैठक फाइनेंस कमेटी की आज

JAMSHEDPUR : कोल्हान विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक 21 मई को होगी। यह बैठक करीब 8 महीने बाद हो रही है। इसमें परीक्षा समिति, एकेडमिक काउंसिल और फाइनांस कमेटी की पिछली बैठकों में लिए गए फैसलों पर चर्चा होगी। जिन प्रस्तावों को सिंडिकेट मंजूरी देगा, उन्हें लागू किया जाएगा। बैठक में स्नातक 2017 से 2019 के बीच दाखिला लेने वाले छात्रों के जेनरिक पेपर-2 की विशेष परीक्षा पर भी मुहर लगेगी। इससे छात्रों को राहत मिलेगी।

बैठक से पहले 17 मई को फाइनांस कमेटी की बैठक होगी। इसमें फंड आवंटन समेत कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। करीब 20 महीने तक कुलपति नहीं होने के कारण विवि में कई फैसले अटके रहे। अब सिंडिकेट की बैठक के बाद विवि के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। बैठक में दीक्षांत समारोह आयोजित करने पर भी निर्णय लिया जाएगा। इसकी तिथि भी तय हो सकती है। छात्र, शिक्षक और कॉलेज लंबे समय से इस बैठक का इंतजार कर रहे थे।

कार सवार अपराधियों ने महिला से की चेन छिनतई

JAMSHEDPUR : टेल्को कॉलोनी में शुक्रवार को पूर्व सैनिक योगेश्वर नंद सिंह की पत्नी के गले से सोने की चेन छिनतई हो गई। भुक्तभोगी श्वेता सिंह ने बताया कि के बदमाश कार से घूम रहे थे। उन्होंने सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और फरार हो गए। श्वेता सिंह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थीं, तभी टेल्को कॉलोनी के जीई हॉस्टल से लुपिटा चर्च के रास्ते में सुबह करीब 6 बजे यह घटना हुई। ऐसा लग रहा था कि अपराधी घात लगाए बैठे थे। इसके बाद श्वेता सिंह फरियाद लेकर टेल्को थाना पहुंचीं और घटना की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चलती कार में बैठे बदमाशों ने पिछली खिड़की से पीछे से चेन खींच लिया और धक्का देकर लिटिल फ्लावर स्कूल वाले डाउन रास्ते से भाग गए। झपटमारी के दौरान उनकी गर्दन के पिछले हिस्से पर खरोंच भी आई। धक्का देने से हाथ में काफी चोट लगी है। श्वेता सिंह ने बताया कि चेन की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये है। उन्होंने बताया कि वह रोज मॉर्निंग वॉक करने जाती हैं। शुक्रवार को भी रोज की तरह ही टेल्को के राधिका नगर, खड़गाझार स्थित अपने घर से निकली थीं। उस वक्त पुलिस की पेट्रोलिंग टीम भी गश्त लगा रही थी। हालांकि, घटना के वक्त वहां पुलिस की पेट्रोलिंग टीम नहीं थी।

भुक्तभोगी महिला

मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री का कांग्रेस ने फूंका पुतला

मानगो में पुतला दहन से पहले नारेबाजी करते कार्यकर्ता ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा सेना पर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। मानगो प्रखंड के तत्वाधान में डिमना चौक पर पुतला दहन ओमप्रकाश सिंह व प्रखंड अध्यक्ष ईश्वर सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि भाजपा के लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ज्यादा अच्छा होता कि जगदीश देवड़ा को पार्टी और उपमुख्यमंत्री पद से निकाल देते। विडंबना है कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की और अब उनके उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है।

पूरे देश की जनता सेना के शौर्य पर गौरवान्वित है, लेकिन बीजेपी अपने इन नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। हम कभी भी देश के सैनिकों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।

जीएसटी दिवस पर कल निकलेगा साइकिल मैराथन

प्रतीकात्मक तस्वीर

JAMSHEDPUR : जीएसटी दिवस पर फिट इंडिया कैंपेन के सहयोग से बिष्टुपुर स्थित सीजीएसटी आयुक्तालय भवन से 18 मई को सुबह 6 बजे साइकिल मैराथन निकलेगा। यह मैराथन गोपाल मैदान गोलचक्कर से होते हुए मॉन्यूमेंट रोड, बिष्टुपुर थाना, वोल्टास बिल्डिंग, पी एंड एम मॉल होते हुए जीएसटी भवन बिष्टुपुर में समाप्त होगा।

इसका उद्देश्य फिटनेस, कल्याण, कार्यबल के बीच एकता की भावना और देश में जीएसटी के कार्यान्वयन के महत्व को स्मरण दिलाना है।

चाईबासा में वंदेमातरम... से गूंजा शहर, वीरों को दी गई श्रद्धांजलि

ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा के साथ पश्चिमी सिंहभूम में निकली भव्य तिरंगा यात्रा

PHOTON NEWS CHAIBASA : ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित लोगों ने शुक्रवार को सुपलसाईं चौक से पोस्टऑफिस चौक तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा की शुरूआत धरतीआबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। राष्ट्रप्रेमियों ने हाथों में तिरंगा थामे देशभक्ति के नारों से वातावरण को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया। चिलचिलाती धूप में भी जनसैलाब उमड़ा रहा, जिसमें हर आयु वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा के समापन स्थल पोस्टऑफिस चौक पर वीर सैनिकों का सम्मान किया गया और शहीद राम भगवान केरकेट्टा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबिद, जिला अध्यक्ष संजय पांडे, गीता बलमुचू, सतीश पुरी, काबू दत्ता, अनूप सुल्तानिया, चंद्रमोहन तिऊ, दिनेशचंद्र नंदी, हेमंत केशरी, पवन शर्मा, राकेश पोद्दार, जयगिरि गोस्वामी, संजू तिर्की, लालु कुजुर, नवीन गुप्ता आदि के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मारवाड़ी समाज, चैंबर ऑफ कॉमर्स, मारवाड़ी सम्मेलन, हिंदू जागरण मंच, जायंट्स ग्रुप, मारवाड़ी युवा मंच विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, उरांव समाज, बंगाली सेवा समिति, लायंस क्लब चाईबासा विश्वकर्मा समाज, तुरी समाज, निषाद समाज, वीरांगना वाहिनी समेत काफी संख्या में नागरिक शामिल थे।

तिरंगा यात्रा में शामिल भाजपा कार्यकर्ता व अन्य ● फोटोन न्यूज

सीएसआईआर-एनएमएल ने स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप मनाया स्वच्छता पखवाड़ा-2025

महिला सफाई कर्मियों ने किया नृत्य, नाट्य मंचन ने भी बटोरी तालियां

PHOTON NEWS JSR : भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप, सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनएमएल), जमशेदपुर ने 1 से 15 मई तक स्वच्छता पखवाड़ा-2025 मनाया। समापन समारोह के सांस्कृतिक भाग में प्रयोगशाला की महिला सफाई कर्मचारियों द्वारा जीवंत नृत्य प्रस्तुति दी गई, जिसे दर्शकों ने दिल से सराहा। इसके बाद सीएसआईआर-एनएमएल के कर्मचारियों द्वारा एक आकर्षक नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक भागीदारी जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया।

समारोह के एक भाग के रूप में, गणमान्य व्यक्तियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं-जैसे निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी, आशु भाषण और कला प्रतियोगिता-के विजेताओं को उनकी भागीदारी और उपलब्धियों के सम्मान में पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान करके सम्मानित किया। यह पहल सीएसआईआर-एनएमएल के निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधरी के मार्गदर्शन में संचालित की गई और इसका समन्वयन डॉ. शर्मिष्ठा सागर, मुख्य वैज्ञानिक के साथ-साथ जयशंकर शरण, विप्लव विशाल, पंकज कुमार, भोला आजाद, विश्वजीत भौमिक, उदय भास्कर राव और कई अन्य कर्मचारियों की समर्पित टीम द्वारा किया गया।

समापन समारोह के दौरान, डॉ. संदीप घोष चौधरी ने स्वागत भाषण में स्वच्छता पखवाड़ा के महत्व और भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के साथ इसके संरेखण पर जोर दिया। उन्होंने इस तरह की पहलों के दीर्घकालिक सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों के तहत, विशेषकर भावी पीढ़ियों की भलाई पर प्रकाश डाला। डॉ. चौधरी ने स्वच्छ और अधिक जिम्मेदार समाज के निर्माण में स्थिरता और पुनर्चक्रण की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम की समन्वयक और मुख्य वैज्ञानिक, डॉ. शर्मिष्ठा सागर ने प्रयोगशाला के विभिन्न परिसरों में पखवाड़े के दौरान आयोजित गतिविधियों का विस्तृत सारांश प्रस्तुत किया। उन्होंने आगे की राह भी बताई और पखवाड़े के बाद भी दैनिक व्यवहार में स्वच्छता और स्थिरता को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम का समापन सीएसआईआर-एनएमएल के प्रशासन नियंत्रक जयशंकर शरण द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ, जिसके बाद राष्ट्रगान की प्रस्तुति हुई और इसके साथ ही स्वच्छता पखवाड़ा-2025 समारोह का औपचारिक समापन सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम में नृत्य करतीं एनएमएल की महिला सफाईकर्मी ● फोटोन न्यूज

उत्पादकता भी बढ़ाता स्वच्छता : दीपांकर चौधरी

अपने संबोधन में मुख्य अतिथि दीपांकर चौधरी, आईएएस, परियोजना निदेशक, एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी, पूर्वी सिंहभूम ने कार्यस्थल पर दक्षता बढ़ाने हेतु स्वच्छता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण न केवल बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देता है, बल्कि कर्मचारियों के मनोबल, एकाग्रता और उत्पादकता को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। चौधरी ने बताया कि स्वच्छता को महज एक नियमित कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक मौलिक मूल्य के रूप में देखा जाना चाहिए, जो किसी भी संगठन के समग्र अनुशासन और व्यावसायिकता में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

गितिलपी टोली का चापाकल भी सूखने की कगार पर

डीसी ऑफिस पहुंची महिलाएं ● फोटोन न्यूज

CHAIBASA : भीषण गर्मी में पानी की विकराल होती समस्या को लेकर गितिलपी टोली सरजोमगुटू (पंचायत हरिला, थाना मुफस्सिल) के ग्रामीणों ने शुक्रवार को उपायुक्त से मिलकर डीप बोरिंग कराने की मांग रखी। जनहित में इस मांग का समर्थन करने पूर्व सांसद गीता कोड़ा व भाजपा नेत्री गीता बलमुचू भी पहुंचीं। बताया गया कि गांव की आबादी लगभग 200 है, लेकिन पूरे क्षेत्र में मात्र एक सरकारी चापाकल है, वह भी अब सूखने की कगार पर है। ग्रामीणों को दूरदराज के इलाकों से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस मौके पर कृष्णचंद्र सवैयां, वीना रानी करजी, सुशांति बानरा, रानी सवैयां, मनोहर तामसोय, जगन्नाथ करजी, सविता करजी, जानकी गोप, राधिका करजी, जेमा करजी, सुखमति बिरुवा, मालती सवैया समेत दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे।

ग्रीष्मकालीन भिंडी उत्पादन की उन्नत तकनीक

ग्रीष्मकालीन सब्जियों में भिंडी का प्रमुख स्थान है। ग्रीष्मकाल में भिंडी की अगेती फसल लगाकर किसान भाई अधिक लाभ अर्जित कर सकते है। मुख्य रुप से भिंडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट खनिज लवणों के अतिरिक्त विटामिन 'ए', 'सी' थाईमीन एवं रिबोफ्लेविन भी पाया जाता है। भिंडी के फल में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। भिंडी का फल कब्ज रोगी के लिए विशेष गुणकारी होता है। इस लेख में ग्रीष्मकालीन भिंडी की उत्पादन तकनीक की विवेचना की गयी है:-

जलवायु एवं भूमि की तैयारी:- भिंडी के उत्पादन हेतु गर्म मौसम अनुकुल होता है। बीजों के अंकुरण हेतु 20 सेंटीग्रेड से कम का तापमान प्रतिकूल होता है। 42 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर फूल का परागण नहीं होता है एवं फूल गिर जाते है।

सामान्यतः भिंडी की खेती सभी प्रकार की भूमियों पर की जा सकती है परन्तु हल्की दोमट मिट्टी जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश उपलब्ध हो एवं उचित जल निकास की सुविधा हो, भिंडी की खेती हेतु श्रेष्ठ होती हैं। भूमि की दो-तीन बार जुताई कर भूरभूरा कर तथा पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए।

उन्नत किस्में- अर्का अभय, अर्का अनामिका, परभणी क्रांति, पूसा-ए-4, वर्षा उपहार,

बीज एवं बीजोपचार:- ग्रीष्मकालीन फसल हेतु 18-20 कि.ग्रा. बीज एक हेक्टर बुवाई के लिए पर्याप्त होता है जबकि वर्षाकालीन फसल में अधिक बढ़वार की कारण 12-15 कि.ग्रा. बीज प्रति हेक्टर उपयोग करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन भिंडी के बीजों को बुवाई के पूर्व 12-24 घंटे तक पानी में डुबाकर रखने से अच्छा अंकुरण होता है। बुवाई के पूर्व भिंडी के बीजों को 3 ग्राम थायरम या कार्बेन्डाजिम प्रति किलो बीजदर से उपचारित करना चाहिए। संकर किस्मों के लिए 5 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर की बीजदर पर्याप्त होती है।

बुवाई:- ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुवाई फरवरी-मार्च में की जाती है। फिर भी अगेती फसल हेतु छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 15 जनवरी के बाद भी बुवाई की जा सकती हे। यदि भिंडी की फसल लगातार लेनी है तो तीन सप्ताह के अंतराल पर फरवरी से जुलाई के मध्य अलग-अलग खेतों में भिंडी की बुवाई की जा सकती है।

ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुवाई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार दूरी 25-30 सें.मी. एवं कतार में पौधे की मध्य दूरी 15-20 से.मी. रखनी चाहिए। वर्षाकालीन भिंडी के लिए कतार से कतार दूरी 40-45 सें.मी. एवं कतारों में पौधे की बीच 25-30 सें.मी. का अंतर रखना उचित रहता है।

पोषण प्रबंधन:- भिंडी की बुवाई के दो सप्ताह पूर्व 250-300 क्विंटल सड़ा हुआ गोबर खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। प्रमुख तत्वों में नत्रजन, स्फुर एवं पोटाश क्रमशः 60 कि.ग्रा., 30 कि.ग्रा. एवं 50 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर की दर से मिट्टी में देना चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा स्फुर एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई के पूर्व भूमि में देना चाहिए। नत्रजन की शेष मात्रा को दो भागों में 30-40 दिनों के अंतराल पर देना चाहिए।

जलप्रबंधन:- यदि भूमि में पर्याप्त नमी न हो तो बुवाई के पूर्व एक सिंचाई करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में प्रत्येक पांच से सात दिन के अंतराल पर सिंचाई आवश्यक होती है। बरसात में आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए तथा अतिवृष्टि के समय उचित जलनिकास प्रबंध करना चाहिए।

निदाई-गुड़ाई:- नियमित निंदाई-गुड़ाई कर खेत को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। बोने के 15-20 दिन बाद प्रथम निंदाई-गुड़ाई करना जरुरी रहता है। खरपतवार नियंत्रण हेतु रासायनिक नींदानाशकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। बासालिन को 1.2 कि.ग्रा. सक्रिय तत्व को प्रति हेक्टर की दर से पर्याप्त नम खेत में बीज बोने के पूर्व मिलाने से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।

फल की तोड़ाई एवं उपजः- किस्म की गुणता के अनुसार 45-60 दिनों में फलों की तुड़ाई प्रारंभ की जाती है एवं 4 से 5 दिनों के अंतराल पर नियमित तुड़ाई की जानी चाहिए। ग्रीष्मकालीन भिंडी फसल में उत्पादन 60-70 क्विंटल प्रति हेक्टर तक होता है।

पौध संरक्षण:- भिंडी के प्रमुख रोग पीत शिरा मौजक एवं चूर्णिल आसिता एवं नुकसानदायक कीट प्ररोह एवं फल छेदक तथा जैसिड है।

पीत शिरा रोगः- यह भिंडी की फसल में नुकसान पहुचाने वाला प्रमुख रोग है। इस रोग के प्रकोप से सर्वप्रथम पत्तियों की शिराएं पीली पड़ने लगती है। तत्पश्चात पूरी पत्तियाँ एवं फल भी पीले रंग के हो जाते है पौधे की बढ़वार रुक जाती है। वर्षा ऋतु में इस रोग का संक्रमण अधिक होता है।

सर्वप्रथम इस रोग के लक्षण वाले पौधे दिखाई देते ही उन्हें उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। यह विषाणु जनित रोग सफेद मक्खी कीट द्वारा स्वस्थ पौधों में फैलाया जाता है। अतः रोग संवाहक कीट के नियंत्रण हेतु आक्सी मिथाइल डेमेटान 1 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से रोग का प्रसारण कम होता है। पीतशिरा रोग प्रतिरोधी किस्मों जैसे अर्का अभय, अर्का अनामिका, परभणी क्रांति इत्यादि का चुनाव करना चाहिए। फसल के चारों ओर 2-3 कतार मक्का बोने से भी रोग का फैलाव नियंत्रित किया जा सकता है।

चूर्णिल आसिताः- इस रोग में भिंडी की पुरानी निचली पत्तियों पर सफेद चूर्ण युक्त हल्के पीले धब्बे पड़ने लगते है। ये सफेद चूर्ण वाले धब्बे काफी तेजी से फैलते है। इस रोग का नियंत्रण न करने पर पैदावार 30 प्रतिशत तक कम हो सकती है। इस रोग के नियंत्रण हेतु घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 या 3 बार 12-15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए।

प्ररोह एवं फल छेदकः- इस कीट का प्रकोप वर्षा ऋतु में अधिक होता है। प्रारंभिक अवस्था में इल्ली कोमल तने में छेद करती है जिससे तना सूख जाता है। फूलों पर इसके आक्रमण से फल लगने के पूर्व फूल गिर जाते है। फल लगने पर इल्ली छेदकर उनको खाती है जिससे फल मुड़ जाते हैं एवं खाने योग्य नहीं रहते है।

जैसिडः- ये सुक्ष्म आकार के कीट पत्तियों, कोमल तने एवं फल से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते है।

फल छेदक के द्वारा आक्रमण किये गये फलों एवं तने को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। क्विनॉलफास 25 ई.सी. 1.5 मिली लीटर या इंडोसल्फान 1.5 मिली लीटर प्रति लीटर पानी की दर से कीट प्रकोप की मात्रा के अनुसार 2-3 बार छिड़काव करने से जैसिड एवं फल प्ररोह छेदक कीटों का प्रभावी नियंत्रण होता है। फल बनने के उपरांत कीट प्रकोप होने पर 'फेनवेलरेट' 0.5 मिली प्रति लीटर पानी में घोलकर उपर्युक्त बनाये कीटनाशक के साथ अदल-बदल कर प्रयोग करें।

कैसे करें संरक्षित खेती

संरक्षित खेती का मुख्य उद्देश्य सब्जी फसलों को मुख्य जैविक या अजैविक कारकों से बचाकर उगाना होता है। इसमें फसल को किसी एक कारक या कई कारकों से बचाकर उगाया जा सकता है।

संरक्षित सब्जी उत्पादन के लिए सब्जी उत्पादकों को संरक्षित खेती व विभिन्न संरक्षित संरचनाओं की पूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद ही उत्पादक तय कर सकता है कि वह किस प्रकार की संरक्षित तकनीक अपनाकर बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करे। कौन कौन सी संरक्षित प्रौद्योगिकीयॉ हैं जिनमे वह सब्जियों को वर्ष भर उगा सकता है। संरक्षित संरचनाओं को बनाने के बाद में रख रखाव में क्या व्यय होगा तथा उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों को वह किस बाजार में बेचकर अधिक लाभ कमा सकता है। इन सभी विषयों की जानकारी आवश्यक है।

मुख्यतः सब्जी उत्पादन हेतू उचित व उपयुक्त संरक्षित प्रौद्योगिकी की आवश्यकता उस क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करती है। लेकिन इसके अलावा किसान की आर्थिक दशा, टिकाऊ व उच्च बाजारकी उपलब्धता व बिजली की उपलब्ध्ता आदि कारक भी इसको निर्धारित करते है। सब्जीयों के बेमौसमी उत्पादन हेतू मुख्यत : वातावरण अनुकूलित ग्रीनहाउस, प्राकृतिक वायु संचारित ग्रीनहाउस, कम लागत वाले पॉलीहाउस, वाक-इन-टनल, कीट अवरोधी नेटहाउस तथा लो प्लास्टिक टनल आदि संरचनाओं का उपयोग किया जाता है।

बेमौसमी सब्जियों की संरक्षित खेती के लिए सबजियों की पौध प्लग ट्रे पद्धती से ग्रीनहाउस मे तैयार की जाती है। तथा उसके बाद पौधो को उपयुक्त संरक्षित संरचना में रोपाई करते है।

वाक-इन- टनल तकनीक

वाक-इन- टनल एक प्रकार की अस्थाई संरक्षित संरचना है जो आधा इंच मोटाई के जंग रोधी पाईपों को अर्धगोलाकार आकार मे मोडकर तथा इन्हे सरियों के टुकडो के सहारे खेत में खडा करके उसके उपर पारदर्शी प्लास्टिक की चादर से ढककर बनाया जाता है। इसके मध्य में ऊंचाई लगभग 6 से 6.5 फुट तथा जमीन पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक चौडाई 4 मीटर तक होती है।

इस प्रकार की संरक्षित संरचनाओं को सर्दी के मौसम में बेमोसमी सब्जी जैसे लोकी, खरबूजा, तरबूज, खीरा, चप्पनकद्दू , तथा अन्य कद्दू वर्गीय सब्जीयां उगाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की संरक्षित संरचनाओं में दिन के समय जब सूर्य की रोशनी प्लास्टिक पर मडती है तो टनल के अन्दर का तापमान काफी (लगभग 10 से 12 डि.ग्री से.) बढ जाता है । जिससे कद्दू वर्गीय सब्जीयों को कम तापमान के दिनो में भी बढवार करने में सफलता मिल जाती है।

वाक-इन- टनल की लम्बाई आवश्यकता अनुसार बढाई जा सकती है। लेकिन सामान्यत- इनकी लम्बाई 25 से 30 मीटर होती है। इसके तीन प्रमुख कारण हैं- प्लास्टिक की चादर की उपलब्ध माप, टनल में हवा का आदान प्रदान, तथा इस लम्बाई के टनल में मधुमक्खीयों को भी परागण कार्य करने में कोई असुविधा नही होती। इन संरचनाओं को बनाने में लागत भी बहुत कम ही आती है। तथा अस्थाई होने के कारण इनकी देखभाल भी सरलता पूर्वक की जा सकती है।

इन संरचनाओं का उपयोग केवल सर्दी के मौसम (दिसम्बर जनवरी व फरवरी माह) में ही फसल उत्पादन के लिए किया जा सकता है। क्योकि सर्दी के बाद इसके अंदर का तापमान बहुत अधिक बढ जाता है तथा हवा का अधिक आदान प्रदान न होने के कारण तब इनमे फसल उगाना संभव नही होता है। यही नही इनका उपयोग पहाडी क्षेत्रों मे और भी लम्बे समय तक सब्जी उत्पादन के लिए किया जाता है। इसी प्रकार इन संरचनाओं को ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों मे भी सब्जी उत्पादन के लिए उपयोग मे लाना सम्भव है।

छतरपुर के गांधी आश्रम में जैविक खेती का अद्भुत प्रयोग

यहां जैविक, परंपरागत और टिकाऊ खेती की किताबी बातें नहीं की जातीं बल्कि जमीन पर नजर भी आती हैं। कड़कड़ाती ठंड और पाला भी इस इलाके में लगी दलहनी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। पेड़-पौधों की रंगत देखकर ही लगता है कि यहां की मिट्टी ने अपनी खोयी ताकत और ऊर्जा फिर पा ली है। यह कोई वर्षों की मेहनत नहीं बल्कि केवल चार साल की लगन का नतीजा है। मिसाल पेश करने वाले हैं - संजय और दमयंती। जिस बुदेलखंड में पिछले पांच सालों में भयंकर सूखे से किसानों की कमर टूट गई है, उसी धरती पर एक जगह ऐसी भी है, जहां खुशियों की खेती लहलहा रही है। विदर्भ के बाद मध्यप्रदेश में किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं के बीच खेती का यह प्रयोग एक मिसाल पेश करता है। यहां जैविक, परंपरागत और टिकाऊ खेती की किताबी बातें नहीं की जातीं बल्कि जमीन पर नजर भी आती हैं। कड़कड़ाती ठंड और पाला भी इस इलाके में लगी दलहनी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। पेड़-पौधों की रंगत देखकर ही लगता है कि यहां की मिट्टी ने अपनी खोयी ताकत और ऊर्जा फिर पा ली है। यह कोई वर्षों की मेहनत नहीं बल्कि केवल चार साल की लगन का नतीजा है। मिसाल पेश करने वाले है संजय और दमयंती और जगह है छतरपुर।

टिकाऊ खेती की बात से पहले आपको थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी होगा। गांधी आश्रम छतरपुर ऐतिहासिक महत्व की जगह है। अंग्रेजी शासन काल के बाद दीवान साहब के बंगले से यह जगह गांधी विचारों को आगे ले जाने का एक केन्द्र बनी। तत्कालीन दीवान ने विनोबा के भूदान आंदोलन से प्रेरित होकर इस बंगले और बंगले से लगी जमीन को गांधी विचारों के लिए समर्पित कर दिया। उसके बाद इसे गांधी आश्रम के नाम से विकसित किया गया। सांस्कृतिक-साहित्यिक-सामाजिक गतिविधियों को यहां से संचालित किया जाता रहा। सत्तर के दशक में जब चंबल में डाकुओं का आतंक अपने चरम पर पहुंचकर आत्मसमर्पण की ओर बढ़ा तब इस प्रक्रिया की बुनियाद इसी आश्रम के पुस्तकालय से पड़ी। जयप्रकाश नारायण के साथ यहां डाकुओं की बातचीत हुई और इसके बाद डाकुओं ने आत्मसमर्पण भी किए। गांधी का ग्रामस्वराज, बुनियादी तालीम और टिकाऊ विकास की अवधारणाओं की झलक इस छोटे से आश्रम में दिखाई देती है। बीच में एक लंबा दौर ऐसा भी आया जब यह आश्रम भूमाफियों और सामाजिक गतिविधियों के केन्द्र में तब्दील हो गया।

2006 में गांधी विचारों से जुड़े संजय और दमयंती जब इस जगह आए तो उन्होंने ठान लिया कि यहां की तस्वीर को बदलने के लिए वह कठिन परिश्रम करेंगे। खेती-किसानी और प्रकृत्ति प्रेमी भाई ने इस आश्रम से लगे लगभग चालीस एकड़ खेत में जैविक खेती के प्रयोग को शुरू करने की योजना बनाई। एक ओर जहां नकद फसलों ने फसलों की विविधता को खत्म कर दिया है वहीं इस आश्रम में उन्होंने अलग-अलग फसलों को अपनाया। इस छोटी सी जमीन पर गेहूं, चना, सरसों, अरहर, ज्वार, मक्का, जौं सहित ऐसी फसलें लीं जो सीधे-सीधे किसान अपने खाने के लिए भी उपयोग करते हैं। दरअसल खेती का परंपरागत तरीका था भी यहीं कि किसान ज्यादातर खाद्यान्न और मसाले अपने खेतों में पैदा किया करते थे और उन्हें हर चीज के लिए बाजार की ओर मुंह नहीं देखना पड़ता था, अब किसान गेहूं-सोयाबीन पैदा तो खूब कर रहे हैं, लेकिन दाल-मसालों के लिए वह बाजार पर निर्भर है। खेती की इस विविधता से आश्रम की व्यवस्थाएं भी स्वतः संचालित होती है। यहां तक की सब्जी और फलों का उत्पादन भी आश्रम से ही हो जाता है। इस खेती की सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले चार सालों से यहां रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। वर्मी कम्पोस्ट और गोमूत्र के जरिए यहां की फसलों को जान मिलती है। 40 एकड़ के इस क्षेत्र को आश्रम के केवल सात कार्यकर्ता अंजाम देते हैं। संजय भाई बताते हैं कि आज के इस दौर में जैविक खेती करना थोड़ा कठिन जरूर लग सकता है पर यह असंभव कतई नहीं है। हम अपने खेतों में उतना ही समय खर्च करते हैं जितना दूसरे किसान। पर यहां आपको यह समझना होगा कि जमीन क्या चाहती है। किस तरह की जमीन पर किस तरह के फसल ठीक रहेगी यह समझना होगा।इस आश्रम की एक खास बात यह है कि आप यहां पूरी तरह जैविक भोजन का आनंद ले सकते हैं। यहां तक की दाल-मसाले और तेल भी खुद की उगाई गई तिल का। इस आश्रम में चल रही खेती के प्रयोग को समझने फ्रांस के निकोलस आए हैं। निकोलस कहते हैं कि 'वह भारत में जैविक खेती के अलग-अलग प्रयोगों को उन्होंने देखा, लेकिन यह प्रयोग सबसे अद्भुत है। इसलिए भी क्योंकि यह गांधी के विचारों से जुड़ा हुआ है। गांधी ग्राम स्वराज की बात करते थे और गांव की अर्थव्यवस्था के एक मॉडल की बात करते थे जहां कि ग्रामवासी आपसी व्यवहार में अपने साझा जीवन को अंजाम देते थे। यह प्रयोग अपने आप में दिलचस्प है।' यही कारण है कि वह न केवल इस खेती पर अध्ययन कर रहे हैं बल्कि इस प्रयोग के साथ इतना रम गए हैं कि वह खुद खेतों में पसीना बहाते हैं। बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता भावेश भी इस प्रयोग के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। वह कहते हैं कि कम लागत की इस खेती को जीवन के साथ जोड़कर भी देखा जाना जरूरी है।

भारत में जहरीली शराब रोकने ऑपरेशन सिंदूर-2 की सख़्त जरूरत!

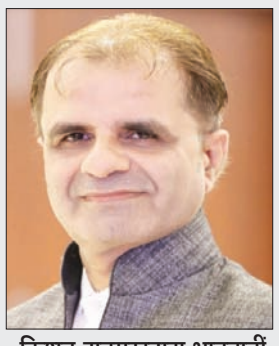

किशन सनमुखदास भावनानीं

भारत में जहरीली शराब से नरसंहार कब तक?- मृतकों के घर के चूल्हे उजड़ बन रहे मातमगाह-कब जागेगी सरकारें?भारत में जहरीली शराब रोकने ऑपरेशन सिंदूर- 2 की सख़्त जरूरत ! नकली जहरीली शराब से मृतक के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान,आरोपियों की गिरफ्तारी, जमानत निचली से ऊपरी कोर्ट तक की प्रक्रिया-पीड़ित परिवारों की जिंदगी समाप्त?

वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के हर देश के शौकीनों के लिए शराब को एक अमृत रस के रूप में टॉनिक की उपमा दी जाती है। खुशी के अनेकों मौकों पर शराब दावत को देखा जा सकता है। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखा हूं कि, नाम मात्र की परमिशन जरूर होती है परंतु नियमों विनिमयमों कानूनों की धज्जियां जवाबदेही रखने वालों के नाक के नीचे उड़ती है, बंद लिफाफा होटों पर टेप और आखों पर पट्टी का काम करता है, यह तो हाई प्रोफाइल समिति का उदाहरण है,ठीक वैसे हीबॉटम स्तर पर दारू भट्ठियों, मोहल्ला चौकों,में नंबर दो की तथाकथित नकली एथोनल का उपयोग कर बनाई गई शराब का सेवन मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग करते हैं, यहां भी इन्हीं जवाबदेहों के होटों पर लिफाफे की टेप और आँखों पर पट्टी लगा दी जाती है, जिनके परिणाम स्वरुप पंजाब में बटाला तरनतारन संगरूर जैसे कांड तथा भारत के अनेकों राज्यों में अनेकों केस होते रहते हैं जिनकी चर्चा हम नीचे पैराग्राफ में करेंगे। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहेहैं,क्योंकि दिनांक 13 मई 2025 को पंजाब अमृतसर के पास मजीठा गांव में जहरीली शराब पीने से देर रात्रि 12 तक मेरी जानकारी के अनुसार 21 लोगों की मृत्यु की खबर मीडिया मेंआ चुकी थी। सीएम साहब ने मृत्को के परिवार वालों को 10 लाख रुपयों के मुआवजे की घोषणा की है,व घटना से जुड़े 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) व 105 (गैरइरादतन हत्या) के साथ आबकारी अधिनियम,अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम संबंधी धाराएं लगाई गई है। परंतु मैं एक अधिवक्ता होने के नाते देखता रहा हूं कि नकली जहरीली शराब से जुड़े परिवार वालों के लिए मुआवजे की घोषणा, आरोपियों की गिरफ्तारी, जमानत, निचली अदालत से ऊपरी कोर्ट तक प्रक्रिया चलती है, तबतक पीड़ित परिवार वालों की जिंदगी शायद समाप्त हो जाती होगी? चूँकि भारत में जहरीली शराब रोकने ऑपरेशन सिंदूर-2 की सख़्त जरूरत है, तथा सभी राज्यों में एक कॉमन बात कि,नकली शराब से जुड़े परिवार वालों के लिए मुआवजे की घोषणा, आरोपियों की गिरफ्तारी,जमानत बॉटम से ऊपरी कोर्ट तक वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया चलती है तब तक पीड़ित परिवार वालों की जिंदगी शायद समाप्त हो जाती है? इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, भारत में जहरीली शराब का नरसंहार आखिर कब तक? मृतकों के घर के चूल्हे उजड़ बन रहे मातमगाह, कब जागेगी सरकार? बता दें इस आर्टिकल में दी गई जानकारी की सटीकता का प्रमाण नहीं है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उठाई गई है।

साथियों बात अगर हम दिनांक 13 मई 2025 को जहरीली

शराब सेवन कांड की करें तो, अमृतसरःपंजाब के अमृतसर जिले के मजीठा ब्लॉक में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई है, जिससे इलाके में मातम छा गया है, यह घटना ब्लॉक के भंगाली कलां,थारीवाल संघा और मरारी कलां जैसे गांवों में हुई। जिला प्रशासन ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है।पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं और 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है जो सप्लायरों से शराब खरीदकर गांवों में बेच रहे थे, इस घटना को लेकर पंजाब पुलिस के महानिदेशक(डीजीपी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया कि,दुर्भाग्यपूर्ण घटना में नकली शराब के कारण हुई दुखद मौतों के बाद पंजाब पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, जिनमें मुख्य सरगना और कई स्थानीय विक्रेता शामिल हैं, ऑनलाइन खरीदे गए मेथनॉल का इस्तेमाल नकली शराब बनाने में किया गया था। पूरे मामले की जांच चल रहीहै, ताकि कार्य प्रणाली का पता लगाया जाए और सभी दोषियों को न्याय के कठघरे में लाया जाए।

साथियों बात अगर हम भारत में जहरीली शराब के कहरः की करें तो,2014 से 2022 तक किस साल कितनी मौतें हुई, (1) 2014ः अवैध शराब के सेवन से 1,699 मौतें हुईं। (2) 2015ः 1,624 घटनाओं में 1,522 लोगों की जान गई. महाराष्ट्र (278), पुडुचेरी (149) और मध्य प्रदेश (246) में सबसे ज्यादा मौतें हुईं। (3) 2016ः 1,073 घटनाओं में 1,054 मौतें दर्ज की गईं. मध्य प्रदेश (184) और हरियाणा (169) में सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। (4) 2017ः 1,497 घटनाओं में 1,510 मौतें हुईं. कर्नाटक (256), मध्य प्रदेश (216) और आंध्र प्रदेश (183) में हालात गंभीर रहे। (5) 2018ः 1,346 घटनाओं में 1,365 लोगों की जान गई,मध्य प्रदेश (410) और कर्नाटक (218) में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। (6) 2019ः 1,141 घटनाओं में 1,296 मौतें हुईं. मध्य प्रदेश (410) और कर्नाटक (268) में स्थिति चिंताजनक बनी रही। (7) 2020ः 931 घटनाओं में 947 लोगों की जान गई. मध्य प्रदेश (214) और झारखंड (139) में सबसे ज्यादा मौतें हुईं। (8) 2021ः 708 घटनाओं में 782 मौतें हुईं। उत्तर प्रदेश (137) और पंजाब (127) में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। (9) 2022ः 507 घटनाओं में 617 मौतें हुईं। बिहार (134) और कर्नाटक (98) में अवैध शराब का कहर जारी रहा।

साथियों बात अगर हम मजीठा कांड में लगाई गई भारतीय न्याय संहिता की धाराओं को समझने की करें तो,भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में धारा 103 हत्या के लिए सजा का प्रावधान करती है, जबकि धारा 105 गैर- इरादतन हत्या के लिए सजा का प्रावधान करती है। धारा 103 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है, तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुमार्ना लगाया जा सकता है। धारा 105 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति हत्या की श्रेणी में न आने वाला गैर-इरादतन हत्या करता है, तो उसे आजीवन कारावास या 5 से 10 वर्ष का कारावास और जुमार्ना लगाया जा सकता है। धारा 103ः हत्या के लिए सजा (1) यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है, तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और वह जुमार्ने से भी दंडनीय होगा। (2) यदि पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्यको मृत्युदंड या आजीवनकारावास की सजा दी जाएगी और जुमार्ना भी देना होगा।

साथियों बात अगर हम अवैध शराब बनने को समझने की करें तो, कैसे बनती है अवैध शराब?कच्ची शराब बनाने के लिए मुख्य रूप से गुड़, पानी और यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कई खतरनाक केमिकल भी मिलाए जाते हैं, गुड़ को सड़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जाता है, अधिक नशा लाने के लिए नौसादर और यूरिया भी मिलाया जाता है, ये सभी चीजें मानव शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। यूरिया,ऑक्सी टोसिन, गुड़ और पानी को मिलाकर जब फर्मेंटेशन किया जाता है तो इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल बन जाता है,मिथाइल अल्कोहल बनने का एक कारण शराब बनाने की प्रक्रिया के दौरान तापमान का सही ध्यान न रखना भी है, इसी मिथाइल अल्कोहल के कारण शराब जहरीली हो जाती है,इसे पीने से होती है मौत-विशेषज्ञों के अनुसार, मिथाइल अल्कोहल शरीर में जाकर फार्मेल्डिहाइड (फॉर्मिक एसिड) बनाता है, यह एक ऐसा जहर है जो आंखों की रोशनी छीन सकता है या मौत का कारण बन सकता है, यह शराब पीने वाले के दिमाग के लिए भी बेहद हानिकारक है, यदि शराब में मिथाइल अल्कोहल की मात्रा 90 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तो वह जहरीली बन जाती है, इतनी मात्रा में मिथाइल अल्कोहल का सेवन नर्वस ब्रेकडाउन का कारण बनता है। 13 मई को बटाला में हुए शराब कांड में पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि नकली शराब बनाने के लिए इस्तेमाल 'मेथेनॉल' थोक में ऑनलाइन खरीदा गया था। मेथनॉल' एक हल्का, रंगहीन कार्बनिक रासायनिक यौगिक है, जिसे अकसर अवैध रूप से मादक पेय पदार्थों में 'इथेनॉल' के सस्ते विकल्प के रूप में ही मिलाया जाता है।

साथियों बात अगर हम शराब पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध के बारे में समझने की करें तो,शराब पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध के बारे में क्या? क्या यह सैद्धांतिक रूप से संभव है? यदि ऐसा है, तो केंद्र सरकार शराबबंदी कैसे लागू कर सकती है? खैर, यह देखते हुए कि संविधान संघ को शराब को विनियमित करने की अनुमति नहीं देता है, (केंद्र) सरकार को दो-चरणीय प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होगी। तत्काल कदम संविधान में संशोधन करना और शराब को राज्य सूची से संघ सूची में स्थानांतरित करना होगा। इस तरह के संशोधन के लिए प्रत्येक सदन में एक विधेयक पारित करने कीआवश्यकता होगी, जिसे सदन के अधिकांश सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जिसमें कम से कम 2/3 सदस्य उपस्थित और मतदान करेंगे। यह देखते हुए कि यह संशोधन राज्य की शक्तियों को प्रभावित करता है, इस विधेयक को कम से कम 15 राज्यों (कुल 29 राज्यों में से आधे से कम नहीं) की राज्य विधानसभाओं द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। क्या यह आज संभव है? इसका जवाब साफ है हां। भाजपा के पास लोकसभा में बहुमत है और 15 राज्यों में उसकी सरकार है। राज्यसभा में अभी उसके पास जरूरी संख्या नहीं है, लेकिन शराबबंदी जैसे मुद्दे पर समर्थकों का एक समूह तैयार हो सकता है।

संपादकीय

तुर्किये का सपना

भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के चलते अब तुर्किये और अजरबैजान के साथ हमारे संबंधों में तनाव और ठहराव आने की आशंका बढ़ गई है। इन दोनों देशों ने हाल के संघर्ष में पाकिस्तान का समर्थन किया है और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सैनिकों के हमले की निंदा की थी। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों पर जिस ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया था वे तुर्किये के थे। इसके चलते भारत के व्यापारिक संगठनों, ट्रेवल एजेंसियों और शिक्षण संस्थान (जेएनयू) ने इन दोनों देशों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। भारतीयों के गुस्से को देखकर भारत इन दोनों देशों से व्यापारिक संबंध खत्म भी कर सकता है। कश्मीर मुद्दे पर अलग-अलग पड़े पाकिस्तान को तुर्की और अजरबैजान के रूप में ढ़ांढ़स बढ़ाने वाला मित्र देश मिल गया है। 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब ईदोगन पाकिस्तान की यात्रा पर आए थे। पहलगाम हमले के कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने इसी तरह का विचार व्यक्त किया था। ईदोगन ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले को भारत का एकतरफा कदम बताया था। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने कश्मीर की तुलना प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान गैलीपोली में हुए संघर्ष से की थी। इस युद्ध में तुर्की के समर्थन में भारतीय उपमहाद्वीप में खिलाफत आंदोलन चला था। कांग्रेस पार्टी इसके साथ जुड़ गई थी। ईदोगन ने इसकी चर्चा करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों द्वारा तुर्की को दिए गए समर्थन के प्रति आभार व्यक्त किया था। प्रकारांतर से उन्होंने पाकिस्तान को भरोसा दिलाया था कि भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों ने जिस तरीके से खिलाफत आंदोलन के जरिए तुर्की के समर्थन दिया था वैसा ही समर्थन तुर्किये भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को देगा वास्तव में ईदोगन पिछले कुछ वर्षों के दौरान दुनिया के विभिन्न देशों में मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद करते रहते हैं। वह तुर्किये को इस्लामिक दुनिया का नेता बनने की फिराक में हैं। लेकिन उन्हें केवल पाकिस्तान और मलयेशिया का साथ मिला है। ईदोगन की समस्या यह है कि एक ओर वह देश में इस्लामीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ना चाहते हैं और दूसरी और यूरोपीय समुदाय का हिस्सा भी बनना चाहते हैं।

चिंतन-मनन

आत्मज्ञान के लिए पात्रता

एक बार की बात है। एक धनिक सेठ एक पहुंचे हुए संत के पास पहुंचा और उनसे बोला, महाराज, मैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना का प्रयास करता हूं। परंतु मेरा मन ध्यान में एकाग्र ही नहीं हो पाता। आप मुझे मेरे मन को एकाग्र करने का कोई मंत्र बताएं। धनिक सेठ की बात सुनकर संत बोले, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और वहां पर तुम्हें एकाग्रता का मंत्र प्रदान करूंगा। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ कि एक पहुंचे हुए संत उसके घर पधारेंगे। उसने अपनी हवेली की सफाई करवाई और संत के लिए अच्छे-अच्छे पकवान तैयार करवाए। नियत समय पर संत उसकी हवेली पर पधारे। सेठ ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। सेठ की पत्नी ने मेवों व शुद्ध घी से स्वादिष्ट हलवा तैयार किया था। चांदी के पात्र में हलवा सजाकर संत को दिया गया तो संत ने फौरन अपना कमंडल आगे कर दिया और बोले, यह हलवा इस कमंडल में डाल दो। सेठ ने देखा कि कमंडल में पहले ही कूड़ा-करकट भरा हुआ है। यह देखकर वह बोला, महाराज, यह हलवा मैं इसमें कैसे डाल सकता हूं। कमंडल में तो कूड़ा-करकट भरा हुआ है। इसमें हलवा डालने पर भला वह खाने योग्य कहां रह जाएगा, अपितु वह भी कूड़े-करकट के साथ मिलकर दूषित हो जाएगा। यह सुनकर संत मुस्कराते हुए बोले, वत्स, तुम ठीक कहते हो। सबसे पहले पात्रता विकसित करो, तभी तो आत्मज्ञान के योग्य बन पाओगे। यदि मन-मस्तिष्क में विकार तथा कुसंस्कार भरे हैं, तो वे आत्मज्ञान को आत्मसात कैसे कर पाएंगे? एकाग्रता भी तभी बनती है, जब व्यक्ति शुद्धता से कार्य करने का संकल्प करता है। संत की बातें सुनकर धनिक सेठ ने उसी समय संकल्प लिया कि वह शुद्ध आचरण से तथा परोपकार के द्वारा पहले अपने को सुपात्र बनाएगा, ताकि उसे आत्मज्ञान सहजता से प्राप्त हो सके।

अरुणाचली चाल है पाक के हक में चीन की बौखलाहट

ललित गर्ग

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सफल 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद चीन बौखला गया है। पाकिस्तान की करारी हार एवं उसे दिये गये सबक को चीन पचा नहीं पा रहा है। चीन-पाक की सदाबहार दोस्ती के उदाहरण बार-बार सामने आते रहे हैं, हाल ही में सैन्य टकराव के दौरान चीन ने प्रत्यक्ष व परोक्ष तौर पर पाकिस्तान का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि सैन्य व आर्थिक मदद भी की। ऐसे ही संवेदनशील समय पर चीन ने भारतीय जमीन पर दावेदारी जताने एवं अरुणाचल के 27 स्थानों को चीनी नाम देने की कुचेष्टा की है। उसकी यह नापाक कोशिश भी पाक के साथ खड़े होने का ही प्रयास है। यह ध्यान रहे कि वह अरुणाचल एवं उसके अनेक क्षेत्रों, इनमें आवासीय क्षेत्रों के साथ पहाड़ और नदियां भी हैं, इनको पहले ही चीनी नाम दे चुका है। भारत सरकार ने अरुणाचल के भीतरी स्थानों को नए नाम देने के चीन के निराधार और बेतुके प्रयासों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए इसकी निन्दा की है। चीन अपनी दोगली नीति, षडयंत्रकारी हरकतों एवं विस्तारवादी मंशा से कभी बाज नहीं आता। वह हमेशा कोई ऐसी कुचेष्टा करता ही रहता है जिससे भारत चीन बॉर्डर पर अक्सर तनाव रहता है। हालांकि भारत ने दो टूक जवाब देते हुए साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और यह चीनी दुष्प्रचार के सिवाय कुछ नहीं है। चीन की इस हरकत ने यह साफ कर दिया है कि उससे संबंध सुधारने की भारत की तरफ से कितनी ही पहल हो जाए, वह सुधरने वाला नहीं है।

निश्चित ही चीन की ये दकियानूसी हरकतें पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं, यह उसके दुस्साहस एवं उच्छृंखलता का द्योतक है। नाम बदलने से इस स्पष्ट और निर्विवाद वास्तविकता को नहीं बदला जा सकता कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। इस तरह की करतूतों, बचकानी एवं बेतूकी हरकतों से भारत को उकसाना चाहता है। इसी नीति के तहत वह भारत के पड़ोसी देशों में अपनी पैठ बना कर पुलों, सड़कों, व्यावसायिक केंद्रों आदि का निर्माण कर भारत की सीमा पर तनाव पैदा करने की भी कोशिश करता रहा है। शायद उसने यह मुगालता पाल लिया है कि ताजा घटनाक्रम से भारत दबाव में आ जाएगा लेकिन भारत अब ऐसे किसी दबाव में न तो आयेगा, बल्कि इनका सक्षम एवं तीक्ष्ण तरीके से जबाव देने में भारत सक्षम है। चीन का अधिक बौखलाहट एवं खीज का बड़ा कारण भारत ने उसके एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, मिसाइल आदि की इस कदर पोल खोल कर रख दी कि अब उसके लिए दुनिया के निर्धन देशों को अपने दोयम दर्जे एवं घटिसा किस्म के चीनी हथियार बेचना कठिन होगा। पाकिस्तान ने जिस चीनी मिसाइल का इस्तेमाल किया था, उसे भारत ने नाकाम कर दिया।

चीन यह तो चाहता है कि भारत उसके हितों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरते, लेकिन खुद उसकी ओर से भारत के प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता को लगातार नजरअंदाज करता है। चीन भरोसे लायक देश नहीं है, चीन के प्रति कठोर रवैया जरूरी है। निस्संदेह नाम बदलने जैसी घटनाएं हमें सतर्क करती हैं कि चीन के साथ मैत्री संबंधों के निर्धारण के दौरान हमें सजग, सावधान व सचेत रहना चाहिए। अन्यथा चीन पीठ पर वार करने से नहीं चूकने वाला है। भारत को चीन के साथ अपनी तिब्बत नीति पर भी नए सिरे से विचार करना होगा। पिछले तीसरे साल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अनेक स्थानों के नाम बदले हैं। चीन अरुणाचल को जांगनान के नाम से दशार्ता है। वहीं इसे तिब्बत के दक्षिणी हिस्से के रूप में होने का दावा करता है। चीन किये गये वायदों एवं समझौतों से पीछे हटता रहा है, चीनी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच 1993, 1996, 2005 और 2013 में परस्पर भरोसा पैदा करने वाले समझौतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपनी सेना को भारतीय दावे वाले इलाकों में अतिक्रमण करने का आदेश दिया। इसी का अंजाम रही जून 2020 में गलवान घाटी जैसी घटना। जिसमें उसके सैनिक गलवान घाटी में घुस आए थे, जिन्हें रोकने में खूनी संघर्ष हुआ। तबसे दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत के हिस्से की जमीन पर कब्जा करने के इरादे से वह चोरी-छिपे और चालबाजी से घुसपैठ करने की कोशिशें करता रहता है। चीन की विस्तारवादी नीति भारत सहित सम्पूर्ण एशिया के लिये ही नहीं, पूरे विश्व के लिए बड़ा खतरा है।

चीन भारत की बढ़ती ताकत एवं रूतबे से परेशान है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत चीन को चुभती रही है, इसलिए वह चोरी, चालाकी और चालबाजी से भारत को कमजोर करने की चालें चलता रहता है। दरअसल, सीमाओं को लेकर नित नए विवादास्पद तथ्य लाना चीन की फितरत में शामिल है। अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, अक्साई चिन, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर पर भी चीन अपना दावा जताता रहा है। शातिर और चालबाज चीन अरुणाचल के किसी दस्तावेज पर भारत का नाम स्वीकार नहीं करता। कुछ मौकों पर तो वह अरुणाचल को अपने नक्शे में शामिल कर दुनिया के सामने साबित करने की कोशिश कर चुका है कि वह उसका इलाका है। मगर भारत की तरफ से मिले सख्त प्रतिरोध की वजह, सामरिक शक्ति और रणनीतिक सूझ-बूझ से उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है।

भारत को अनेक मोर्चों पर चीन को आडे हाथ लेना होगा, सबसे जरूरी है चीन सामान का बहिष्कार, इस पर सरकार के साथ हमारे उद्योग जगत एवं आम जनता को भी गंभीरता से सोचना होगा। ऐसा करके ही चीन की कमर को तोड़ा जा सकता है, आज दुनिया के अनेक देश चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, हमें भी कठोर कदम उठाने होंगे। भारत ने जब भी पाकिस्तान में पनाह पाए आर्तकियों को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में डलवाने का प्रयास किया, चीन संयुक्त राष्ट्र में अपने वीटो का प्रयोग कर उसे रोकने की कोशिश करता रहा है, जबकि पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का समर्थन करती रही है। जिससे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाने तथा व्यापार-कारोबार बढ़ाने की बात करने वाला चीन भारत के प्रति कैसी दुर्भावना रखता है। वह वैश्विक संगठनों व मंचों पर भारत के साथ खड़ा होने का दावा एवं ढोंग ही करता है। भारत एवं चीन दोनों देशों के बीच संबंधों में आने वाली तल्खी की बड़ी वजह भी चीन की नीयत में खोट, उच्छृंखलता एवं अनुशासनहीनता ही है।

प्राइवेट स्कूल : मनमानी को मात देनी ही होगी

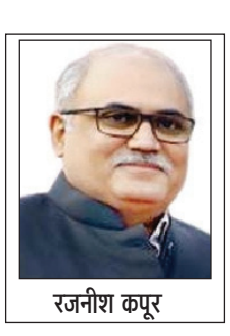

रजनीश कपूर

जो विद्यालय ज्ञान प्राप्त करने का केंद्र होते थे आज व्यापारिक दुकान बन कर रह गए हैं। 2025 में, दिल्ली के कई प्रमुख प्राइवेट स्कूलों ने बिना उचित अनुमति के फीस में भारी वृद्धि की, जिसके परिणामस्वरूप अभिभावकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। एक सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में भारत भर में 44प्र. अभिभावकों ने स्कूल फीस में 50 से 80प्र. तक की वृद्धि की शिकायत की, जबकि 8प्र. ने इसे 80प्र. से अधिक बताया। दिल्ली में कुछ स्कूलों ने 2020 से 2025 तक 7प्र. से 45प्र. तक की वृद्धि की, जिससे वार्षिक फीस 1.4 लाख रुपये तक पहुंच गई। दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस वृद्धि की समस्या ने अभिभावकों, छात्रों और नीति निमार्ताओं के बीच चिंता का विषय बन गया है। स्कूलों का यह रवैया न केवल आर्थिक बोझ को बढ़ाता हैङ्क बल्कि शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता पर भी सवाल उठाता है।

यह वृद्धि विशेष रूप से उन स्कूलों में देखी गई जो दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा रियायती दरों पर दी गई जमीन पर संचालित होते हैं। इन स्कूलों को गैर-लाभकारी मॉडल पर काम करना चाहिए, लेकिन कई स्कूलों ने इस नियम का उल्लंघन किया। अप्रैल 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश ने शिक्षा निदेशालय (डीओई) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें इन स्कूलों को फीस वृद्धि के लिए पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता थी। इस फैसले ने स्कूलों को मनमानी वृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे अभिभावकों का गुस्सा भड़क उठा। स्कूल प्रशासन अक्सर फीस वृद्धि को उचित ठहराने के लिए परिचालन घाटे, शिक्षकों के वेतन, बुनियादी ढांचे के उन्नयन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों के लिए सरकारी प्रतिपूर्ति में देरी का हवाला देता है। हालांकि अभिभावक और कार्यकर्ता इस तर्क को पारदर्शिता की कमी के कारण खारिज करते हैं। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम (डीएसईएआर), 1973 के तहत सरकारी जमीन पर संचालित स्कूलों को फीस वृद्धि के लिए डीओई से अनुमति लेनी होती है। हालांकि कई स्कूलों ने उच्च न्यायालय के आदेशों का लाभ उठाकर इस आवश्यकता को दरकिनार किया। इसके अलावा डीओई की ओर से स्कूलों के वित्तीय रिकॉर्ड की नियमित जांच में देरी और लापरवाही ने समस्या को और जटिल किया। फीस वृद्धि का मुद्दा राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक-दूसरे पर निष्क्रियता और निजी स्कूलों के साथ साठगांठ का आरोप लगाते हैं। दिल्ली के एक अभिभावक के अनुसार उसकी दो बेटियों की स्कूल फीस हर महीने 34,000 रुपये है, जो उसकी मासिक आय का लगभग आधा हिस्सा है। इस तरह की वृद्धि ने ज्यादातर परिवारों को वित्तीय तनाव में डाल दिया है। इसके अलावा, स्कूलों ने उन छात्रों को परेशान करना शुरू कर दिया, जिनके अभिभावकों ने बढ़ी हुई फीस का भुगतान करने से इनकार किया। कुछ स्कूलों में तो बच्चों को लाइब्रेरी में अलग-थलग कर दिया गया। कैंटीन तक पहुंच से वंचित कर दिया गया और सहपाठियों के साथ बातचीत करने से भी रोका गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे 'अमानवीय और शर्मनाक' करार दिया और स्कूलों को शिक्षा को 'पैसे कमाने की मशीन' के रूप में उपयोग करने के लिए स्कूल संचालकों को फटकार भी लगाई। अप्रैल 2025 में, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फीस वृद्धि की शिकायतों की जांच के लिए 600 से अधिक स्कूलों का ऑडिट शुरू किया और 11 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सरकार ने डीओई के तहत जिला-स्तरीय समितियों का गठन किया, जिन्हें उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के नेतृत्व में स्कूलों की जांच करने और 18-सूत्रीय प्रश्नावली के आधार पर अनुपालन की जांच करने का निर्देश दिया गया।

यह कितना प्रभावशाली होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। सरकार को डीएसईएआर, 1973 को और सख्त करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी स्कूल, चाहे वे सरकारी या निजी

जमीन पर हों, फीस वृद्धि से पहले डीओई से अनुमति लें। नियमित ऑडिट और पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग अनिवार्यहोनी चाहिए। फीस निर्धारण समितियों में अभिभावकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र जैसे राज्यों के मॉडल, जहां दो साल में 15प्र. से अधिक वृद्धि के लिए तीन-चौथाई अभिभावकों की सहमति आवश्यक है, को लागू किया जा सकता है। फीस वृद्धि को राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय, सभी दलों को एकजुट होकर दीर्घकालिक समाधान खोजने चाहिए। अन्य राज्यों, जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश, में लागू उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित समायोजन को दिल्ली में भी लागू किया जा सकता है। दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस वृद्धि की समस्या केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है। यह शिक्षा के मौलिक अधिकार को कमजोर करती है और मध्यम वर्ग के परिवारों पर अनुचित बोझ डालती है।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

Op Sindoor takeaway: No going back from the new normal

ON May 12, Prime Minister Narendra Modi briefed the nation on the outcome of Operation Sindoor. Even more important, he laid out a robust doctrine to give effect to his long-standing vision of "zero tolerance" for terrorism. That the PM chose Buddha Jayanti or Vesakh for his speech was a message that India was not a reckless war-mongering country, but wanted to secure her people and live in peace.Amidst the information warfare, the military briefings over the past three days — restrained, shorn of hyperbole and backed by evidence — have helped convey the correct picture. No military campaign is open-ended. Each has a set of objectives. The PM's address was an unambiguous statement on the achievement of Operation Sindoor's political and military objectives.A categorical assertion of success is not just a need for reassuring the nation. It is also an important element of deterrence. Any ambiguity on the assessment of the military outcome in Pakistan, as we have seen in the past, leads to the pursuit of higher and dangerously risky ambitions on both terrorism and Jammu and Kashmir.The Prime Minister has laid out three pillars of deterrence — continuation of Operation Sindoor, a new doctrine, and conditions relating to talks, trade and water. The operation has not ended, just paused. This involves a force posture and a state of readiness that gives credibility to India's position.

In the age of modern warfare, with reliance on drones, missiles and layered air defence systems, combined with sophisticated image and technical intelligence, this can be done at a relatively lower cost than was incurred during Operation Parakram in 2002. Similarly, this operation has shown vast improvement in the military's capacity for rapid mobilisation and a sharp reduction in response time.The central pillar is the new doctrine with three elements. The first is the evolution of a robust strategy since the Uri attack in 2016. There will be a strong response to each terrorist attack. If Pakistan responds militarily, India will maintain escalation dominance and prevail in the conflict. There will be strategic ambiguity on the scale, nature and impact of a terrorist attack that will trigger a response. Equally, there will always be an element of surprise, without repetition, on the timing, pattern and instrument of India's retaliation.Our response after Pulwama and Pahalgam drew a distinction between terrorists and the military. The doctrine erases the differences between terrorists and Pakistan state sponsors after a brazen participation of senior military leaders in the funeral of slain internationally recognised terrorists. This element places the responsibility on Pakistan's state and military for any act of terrorism against India.The element that made the headlines is the rejection of nuclear blackmail. After India and Pakistan declared themselves nuclear weapons states in 1998, Pakistan has intensified cross-border terrorism in the belief that India will desist from conventional military retaliation to avoid the prospects of escalation into a nuclear conflict — thus giving Pakistan the space to pursue a low-intensity conflict with India under the nuclear shield. In this it also drew lessons from some of the war games played out by experts in the West, which demonstrated a high probability of a conventional war escalating into a nuclear exchange.Unlike India, which declared its nuclear doctrine soon after becoming a nuclear weapons state, Pakistan has had no official doctrine. There are declaratory statements with differing thresholds at various points of time for the use of nuclear weapons, which, although not officially stated, also includes the possibility of the first use, starting with Lt Gen Khalid Kidwai, then Director General of Pakistan's Strategic Plans Division, in January 2002. By 2011, Pakistan also changed its doctrine from credible minimum deterrence to full-spectrum deterrence and began diversifying its weapons and delivery systems to include strategic, tactical and operational weapons.While this may suggest a lower threshold of use for tactical and operational weapons against our conventional forces, it is also not clear if Pakistan has operationalised it and achieved the required level of integration of nuclear and conventional forces.

Plugging the chinks in India's cyber armoury necessary

The Computer Emergency Response Team (CERT-In), India's cybersecurity agency, detected a surge in cyberthreats in the form of ransomware attacks during the India-Pak stand-off .

EVEN as missiles were being fired and drones flying towards strategic locations brought down during the India-Pakistan face-off last week, attempts were being made to disrupt key operations far away from border areas. The Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), India's cybersecurity agency, detected a surge in cyberthreats in the form of ransomware attacks, distributed denial of service (DDoS) incidents as well as defacement of websites of some defence entities, data breaches and malware infections.Such attacks are considered a significant risk to the integrity, confidentiality and availability of systems and services. The agency released an advisory on cyberattacks with a high severity rating. Based on the advisory, the Bombay Stock Exchange and other financial agencies alerted their members and market participants. Necessary measures were advised to review cybersecurity frameworks and take steps for the protection of critical digital infrastructure.

The security of digital services such as banking, stock markets, financial services, benefit transfer and e-education depends on the security of the backbone — telecom and Internet infrastructure. This, in turn, depends on the security of hardware, software and networks. A breach at any level in the backbone can potentially affect millions of people, as nearly 1.15 billion Indians use telecom networks and services riding on them. Minimising the risk of security breach would mean making every part of hardware and software safe — from telecom networks and cloud servers to mobile phones and security cameras.

In recent years, the import of critical telecom network equipment like switches, routers, repeaters and gateways, either directly from Chinese companies like ZTE and Huawei or with components sourced from them, has raised the alarm in many countries, including India. Such hardware comes with onboard software, factory settings and default passwords and poses a grave security risk.Realising this hazard, the Joe Biden administration launched the 'Rip-and-Replace' initiative in 2021 to remove and replace Chinese equipment from operational telecom networks. Some EU member states have also taken steps to limit or exclude Chinese players from participating in their 5G networks. Experts have suggested a similar initiative in India because, despite government restrictions on Chinese equipment, many suppliers continue to source telecom equipment from Chinese companies.A study conducted last year by the Voice of Indian Communication Technology Enterprises (VoICE), an industry group, warned that many Chinese-origin products, including security-sensitive ones, were allowed to be included in government and PSU procurement. Government agencies are supposed to procure their requirements from the Government e-Marketplace (GEM) portal. Unscrupulous traders source equipment from China, route it through Singapore or Thailand, integrate it locally and then list them as 'Made in India' products on GEM. It was noticed that government agencies, including defence units, were procuring drones from the GEM portal, and some of them were of Chinese origin.

Unmanned aircraft systems or drones involve complex interactions between hardware, software, communications systems and operational procedures — each of which may have vulnerabilities that can be exploited by malicious actors, according to an analysis done by CERT-In. For instance, a malicious code could be installed on a drone's firmware systems, leading to persistent malware injection, unauthorised access, data theft or disruption of operations. Malware can be injected through compromised updates or remote service access. Therefore, access to the source code is important for any sensitive equipment, and this is possible when the supplier is based in India.Suppliers also take advantage of gaps in standards and regulations. For instance, some 450 companies were found selling security cameras on the GEM portal in the absence of any national standard. After quality, safety and cybersecurity standards were developed under the STQC (Standardisation Testing and Quality Certification) system and enforced, only 13 companies qualified.Even the smallest piece of the telecom system, such as a subscriber identity module (SIM) card, may be vulnerable because it has embedded software or operating systems (other than the operating system of the mobile phone). Mobile phone companies procure chipsets used in SIMs from different sources, including China.A large number of SIM cards currently in use in India have not passed through the 'trusted source approval' mandated by the office of the National Cybersecurity Coordinator in the National Security Council. Some of these SIMs may be in the phones used by people in sensitive positions and locations, posing a significant risk. Only recently, the government began addressing this issue. The way out would be to replace millions of such SIM cards and mandate the use of an Indian operating system. The memory of paging and walkie-talkie devices exploding in Lebanon is still fresh.In the past, we have had instances of free email services, Chinese scanning software CamScanner (now banned) and video-conferencing software with security risk used in sensitive government offices. Now, India is likely to approve high-speed satellite Internet service offered by Elon Musk's Starlink. It was held up so far due to security concerns.In November last year, Indian agencies that made a huge drug seizure in the Andamans found that the fishing vessel involved in the operation was using a Starlink Internet device. In Manipur, too, security agencies seized a Starlink device along with weapons in a raid on an armed ethnic group. These incidents, occurring in the absence of Starlink officially providing its services in India, show how rogue users can bypass any regulation relating to Internet access. Concerns relating to cross-border espionage as well as industrial espionage have also been raised in many countries.All communication services are vital national infrastructure that should not be allowed to be operated by foreign entities or be dependent on foreign equipment with embedded operating systems without full safeguards. For operating systems and embedded software in hardware like drones or satellite terminals, we should demand access to the source code. Domestic solutions should be procured wherever available. Cybersecurity of all civilian as well as strategic communication systems is as vital as the 'iron dome' to protect the Indian airspace.

Express View on MP minister's comments on Colonel Qureshi: Fire the minister

The government must send this much-needed message given the abuse machine. Colonel Qureshi deserves better

Since the terrorist attack at Pahalgam on April 22, through the days of collective anger, grief and sympathy for the victims and their families, to the destruction of terrorist camps and training grounds by Operation Sindoor — India has been united as it sought justice. In his address to the nation after the ceasefire, Prime Minister Narendra Modi pointed out that "the heinous attempt to break the harmony and unity of this country" failed as "every citizen, every community, every class, every political party, unitedly spoke in one voice for strong action against terrorism". The PM's address echoed the sentiments of the country, including leaders across the political spectrum. There are some, though, who mask prejudice and hate and empty bluster as patriotism.Less than a day after the PM's address, BJP MLA and Madhya Pradesh Tribal Affairs Minister Vijay Shah said at a public meeting that terrorists in Pakistan had been taught a lesson "using their own sister". He was referring to Colonel Sofiya Qureshi, prominent in the media briefings during Operation Sindoor. The MP High Court did the right thing — it took cognisance of his remarks, called them "cancerous" and "dangerous", and ordered an FIR against him. The ruling party must take action against its minister because setting an example at this level is crucial. For, Shah's voice is a prominent one but it is not the only one of its ilk. Earlier this week, Foreign Secretary Vikram Misri and his daughter were attacked and abused online because India's top diplomat did his job and articulated the government's position on pausing hostilities.

The current pause is a moment to reflect on how to press India's advantage diplomatically and strategically, ensure that the economic gains that underpin its progress and power are built on. The space for diplomacy, post Op Sindoor, be it on the river waters or on military de-escalation, needs to be secure and expansive. When TV studio warriors — at a comfortable remove from those facing blackouts and vulnerable to shelling — call for "eradication", "dismembering" and "total victory", when they peddle outright falsehood to whip up public opinion, they constrain the room for manoeuvre for India's diplomacy. Even Congress, which has admirably avoided partisan politics on the operation, needs to rethink before it invokes Indira Gandhi and 1971. In the fact-free world of social media, where the abuse machine hums 24 by 7, this isn't a valuable history lesson but a call for dialing up the machine. Comparisons of April 22, 2025, with 26/11 or 1971 are loose, and fraught. Operation Sindoor was a necessary attempt to secure citizens against terror, and raise the costs of a proxy war for Rawalpindi — much work needs to be done in its wake.

New rules of escalation: To win the war before the war

The message in our response to Pakistan is that we will not start wars. But we will define when they begin, and when they end.

THE abrupt end to Operation Sindoor was a bolt from the blue — actually, like an 'out of syllabus' event! It is good that full-scale war was avoided and one hopes no ceasefire violations take place. Even as the armed forces keep a wary eye on our borders, there are some takeaways that can be deduced as a hot debrief.The latest provocations from Pakistan's leadership were not strategic — they were symptomatic. Delivered in familiar tones, the speech was less policy and more performance, recycling tropes of grievance, historical injustice and ideological threat. But something fundamental has changed: the world has stopped listening.India, too, didn't respond. Not with outrage. Not with frenzy. And that silence spoke louder than rebuttal. For New Delhi, this wasn't a moment to react — it was one to reveal. That Pakistan, once a state, is now a league. A league of the delusional, where the few who speak of chaos and confrontation drown out the many who yearn for stability and dignity.

Spark that failed: Kashmir answers back

If the intent was to ignite unrest in Kashmir, the response was sobering. In Pahalgam, and across the Valley, there were no flames of discontent, no angry mobs, no choreographed outrage. Instead, daily life continued in defiance of incitement. The people chose quiet resolve over performative rage.That was India's first and deepest answer. Not from podiums, but from pavements. Not with speeches, but with stillness.The strength of India lies in the coherence of its diversity. In Kashmir — as in Kanyakumari or Kohima — the Constitution guarantees belonging. The armed forces reflect it. The people uphold it. India's unity in diversity, far from fragile, is now strategic doctrine. The call to divide was answered not by rhetoric, but by an enduring truth: India is many, and yet one.

Precision without spectacle

While words echoed across microphones, India acted —quietly, precisely and without theatrics. Strikes on terrorist infrastructure across the LoC and beyond were not announced with fanfare. They were calibrated, effective and purposeful.

Yet, the international response was telling: silence.

There was no outrage at Pakistan hosting UN-listed terrorists, draping them in military colours, giving them state funerals. No press conferences questioned why globally designated murderers were being honoured with honour guards. Once again, the global order failed its own test.India, however, did not seek applause. The target was not moral high ground; it was deterrence. And, the message was clear: the Indian threshold has shifted. Responses now come without noise, but with weight.Escalation, then de-escalation — on India's termsPakistan reacted with its usual reflex: missiles, drones, alerts. Most were deflected, others neutralised. This triggered the second response - measured, but unmistakable. Not just terror camps, but airfields were targeted Not indiscriminately, but deliberately.This wasn't escalation for escalation's sake. It was doctrine in action. Precision that communicated capability, intent and restraint. It hurt.

And it worked.

Pakistan's Director General of Military Operations reached out — not with bluster, but with a call for de-escalation. India accepted — not as concession, but as control. The choreography of this moment was profound: no sabre-rattling, just calibrated consequence.

This is always an area of discussion, and debate, should we, shouldn't we. Conflict termination is never an easy choice. Often times, observers are not into the loop on the political objectives. Hence, a debate ensues as it should.In that response, India drew new red lines. No need to declare them — they were evident in action. The message: India will not start wars. But it will define when they begin, and when they end.

Strategic maturity is the real deterrent

This was not a flare-up. It was a test. And, India calibrated its response with telling effect.

Gone is the era of reactive rage. In its place is a posture of calibrated strength. Strike when needed. Stop when the hurt is acknowledged. Do not dramatise; operationalise.

What enabled this shift?

Capability, yes — India today has real-time options. But more importantly, clarity. There is no space for false dualities. Dialogue and terror do not coexist. There is no "moral equivalence" between an open democracy and a state-run terror league.This maturity is not accidental. It is the product of institutional reform, civil-military coherence and national clarity. India does not seek war.

But it no longer fears escalation. It is called calibrated deterrence.By contrast, Pakistan's internal decay has become externalised. Its nuclear blackmail is now just that — blackmail, not deterrent. The world sees it. Even if it doesn't say so, the Indian PM has called out the blackmail, and declared a terrorist strike is an act of war.

A league that consumes its own

The tragedy of Pakistan is not its military — it is its people's silence, coerced and helpless. A nation where moderate voices are silenced, dissent criminalised and truth becomes treason. The sane suffer. The insane strategise. And the international community, through its financial institutions and rhetorical platitudes, sustains this dysfunction.India understands the difference. Our response has never been to punish the people of Pakistan. It has always been to isolate the machinery that holds them hostage.But make no mistake: as our PM has stated, we will not allow that machinery to harm us. Nor to define the rules of engagement. Nuclear blackmail is now passe.

The world's blind spot — and India's moral burden

Here lies the core contradiction: terrorism is treated as a problem only when it hurts the West. For decades, India has pleaded for a global definition of terror. But institutions — paralysed by power politics and commercial interests — have equivocated.

Meanwhile, IMF loans go to states that bankroll terror. Innocents die while resolutions remain unsigned. Democracies are hijacked through open platforms and borderless networks. Mule routes are now strategy.India has waited long enough. It now offers a pathway — not of dominance, but of design.Not by exporting ideology, but by embodying a civilisational idea: the coexistence of difference within a shared destiny.

The new order: We will call it when it happens

Unity in diversity is not just India's civilisational inheritance — it is its geopolitical offering. The only antidote to engineered division and identity weaponisation.India will no longer wait for the world to define terrorism or its response. It will collaborate with those who call it out when it happens — not only when it hurts.The price of silence is paid by the innocent, not the indifferent.The future belongs to those who collaborate, not those who coerce.The characteristics of conflict are changing. 'To win the war before the war' is part of the new escalatory ladder. It has, I presume, many more rungs. Time will tell.

India Remains Fastest-Growing Economy At 'Precarious Moment' For World: UN

The UN's mid-year update of the World Economic Situation and Prospects (WESP) report said India's economy is projected to grow a tad faster next year at 6.4 per cent, even though it is also 0.3 per cent lower than the January projection.

United Nations. India remains the fastest-growing large economy and is expected to record a 6.3 per cent growth this fiscal year, while the global economy faces a "precarious moment," according to the UN. "India remains one of the fastest growing large economies driven by strong private consumption and public investment, even as growth projections have been lowered to 6.3 per cent in 2025" from the 6.6 per cent made in January, Ingo Pitterle, a senior economic affairs officer, said on Thursday.The UN's mid-year update of the World Economic Situation and Prospects (WESP) report said India's economy is projected to grow a tad faster next year at 6.4 per cent, even though it is also 0.3 per cent lower than the January projection.The world economy is at a precarious moment," the report warned."Heightened trade tensions, along with policy uncertainty, have significantly weakened the global economic outlook for 2025.""It's been a nervous, time for the global economy," Shantanu Mukherjee, the director of the Economic Analysis and Policy Division, said at the release of the WESP."In January this year, we were expecting two years of stable, if subpar growth, and since then, prospects have diminished," he added.Against this picture, the growth of the world's fifth-largest economy, India, contrasts with the global rate of 2.4 per cent this year, and that of other major economies, according to the WESP.

The projection for China is 4.6 per cent, for the US 1.6 per cent, Germany (negative) -0.1 per cent, Japan 0.7 per cent, and the European Union 1 per cent."Resilient private consumption and strong public investment, alongside robust services exports, will support economic growth" for India, the report said.On inflation and employment, the WESP saw positive trends for India.

"Inflation is projected to slow from 4.9 per cent in 2024 to 4.3 per cent in 2025, staying within the central bank's target range," it said."Unemployment remains largely stable amid steady economic conditions," it said, but added a note of caution that "persistent gender disparities in employment underscore the need for greater inclusivity in workforce participation".The WESP drew attention to the risks to the export sector from the US tariff threats."While looming US tariffs weigh on merchandise exports, currently exempt sectors -- such as pharmaceuticals, electronics, semiconductors, energy, and copper -- could limit the economic impact, though these exemptions may not be permanent," it said.The International Monetary Fund last month projected India's economy to grow by 6.2 per cent this year and 6.3 per cent next year.

Singtel offloads 1.2% stake in Bharti Airtel in $1.54 billion deal

New Delhi. Singapore Telecommunications said on Friday it had sold around 1.2% of its stake in India's Bharti Airtel for S$2 billion ($1.54 billion), netting an estimated gain of S$1.4 billion.Pastel, a unit of Singtel, sold 71 million shares in Airtel at 1,814 rupees apiece, reflecting a 2.85% discount to the closing price of Airtel's stock on Thursday.Singtel, which has been an investor in Airtel for over 20 years, said its stake would drop to 28.3%, valued at around S$48 billion, from 29.5% previously.Singtel has been selling shares in Airtel -- a 3.3% stake to Bharti Telecom in 2022 and 0.8% to GQG Partners in March 2024. However, after the sale to GQG, the last one it reported, Singtel had said it had a 29% stake in Airtel.Since a "strategic reset" in 2021, the Singapore-based firm has sought to effectively use its capital and also improve shareholder returns.

"This transaction allows us to crystalise value at an attractive valuation ... and underscores Singtel's commitment to disciplined capital allocation and sustained value realisation for shareholders," CFO Arthur Lang said in a statement.Singtel also said it has been working with Bharti Enterprises -- an Indian conglomerate run by Sunil Bharti Mittal and whose telecom arm is Airtel -- "to equalise its effective stake in Airtel in the medium term".While Singtel did not specify that it was looking to match Mittal's stake in Airtel, Lang had, in 2023, said this was the target.Singtel and Airtel did not respond to a Reuters email seeking comment.CLSA analyst Daxin Lin estimates Mittal's stake in Airtel to be about 23%.The sale was in line with Singtel's capital recycling plan and should not come as a surprise, given the aim to match Mittal's stake, Lin said in a note after media reports broke the news of the sale on Thursday.Singtel's shares were up 1.1% at S$3.79 in Singapore, while Airtel's shares were down 2.8% at 1816.3 rupees in Mumbai. ($1 = 1.2950 Singapore dollars).

Blaming NRIs won't solve India's housing problem, says investor. Here's why

Imagine wanting to buy a house in your hometown, only to find out it's already been snapped up by someone living abroad. That's exactly what many Indians are facing today. A common belief is that NRI investments are pushing real estate prices beyond the reach of the average Indian.

However, Akshat Shrivastava, Founder of Wisdom Hatch, strongly disagrees with blaming NRIs. He wrote on X, "General junta is getting fooled: that oh NRI's are the problem for rising property prices. Goa is my home. I see NRIs buying properties: left, right and center. You know why? Because they can afford to, while an average Indian cannot."

He added, "Now whose fault is it? NRIs? If you think that, then you are an idiot. If the salaries are bad in India, whose fault do you think it is? Answer) it is our fault that we are unable to attract high-quality businesses that pay well."Akshat Shrivastava explained that the real problem lies elsewhere, in India's low domestic salaries and lack of high-paying jobs.He pointed out that a senior officer earning Rs 1.5 lakh monthly would save just Rs 1.6 crore over 30 years, still not enough to buy a decent villa in Goa. So, can NRIs really be blamed?According to Shrivastava, the root problem is India's struggle to attract high-quality, wealth-creating businesses. "We have become a socialist state, that despises wealth. Tagging NRI's as your new enemy is not the answer," he said.

WHY ARE NRIs BUYING HOMES IN INDIA?

NRIs earn in strong currencies like US dollars, pounds, or euros. So when they convert that money to rupees, they can afford much more. A house that seems expensive to someone in India may feel quite reasonable to someone earning abroad.

Take Goa, for example. Many NRIs are buying villas and apartments there. It's not because they're trying to push up prices, it's because they can afford to buy, while locals often can't.

THE BIGGER PICTURE

While NRI property purchases might make headlines, the real issue lies in the Indian economy's structure. The gap between income levels in India and abroad is wide — and that's why NRIs can afford homes here more easily.

Infosys Distributes Performance Bonus Letters -- Check Payout, Eligible Employee Band

New Delhi. Infosys, India's second-largest IT services firm, has announced an average employee bonus of 65 per cent for the fourth quarter of FY25, Moneycontrol reported on Thursday. The latest payout has disappointed some employees, with one saying this was the lowest bonus he had received so far.The IT giant had announced an 80 percent bonus for the last quarter (Q3FY25). The average was 90 percent in the second quarter of FY25, the report said. The quarterly bonus will be paid out with the May salary. Employees who get the bonus

Employees in Band 6 and below are eligible for the bonus. Junior to mid-level employees who earn quarterly variable payouts would be the primary recipients of the bonus. The actual payout percentage varies by performance rating, with those tagged Needs Improvement receiving 0 percent and those marked Outstanding Performers receiving a high of 83 percent, the report saidEmployees disappointed with the bonus

The latest bonus announced by the company has come as a disappointment to many. A senior employee of the company has told The Economic Times that this is the lowest bonus he has ever received in his ten years of employment with the firm.

Company says things are in response to market needs

According to media reports, the IT giant had earlier informed some employees that their performance bonuses for the fourth quarter of the financial year 2024-25 would be reduced, amid dwindling profits.

ITR filing 2025: Is digital Form 16 a game-changer for salaried taxpayers

New Delhi. Filing your income tax return (ITR) doesn't have to be stressful, especially now that Digital Form 16 is here to make things simpler. Issued by your employer, this digital document contains all the necessary salary and tax deduction information, ready to go straight into tax-filing platforms.

WHAT IS DIGITAL FORM 16?

Digital Form 16 is an electronic version of the traditional Form 16. It's generated directly from the TRACES portal, which is managed by the Income Tax Department. This means all your salary details, TDS, and tax-saving deductions are recorded accurately and match what the government sees.WHY IS IT USEFUL?

Digital Form 16 makes tax filing easier and more accurate. Since it's pulled directly from official records, there's

less chance of errors or mismatches in your return.You can simply upload it to most of the tax-filing websites, and the system fills in key details like your salary, TDS, and deductions automatically.This not only saves time but also speeds up refund processing, as the information is already in the correct format. Additionally, it's safe as Digital Form 16s are usually password-protected and stored securely using globally recognised data protection standards.

HANDY FOR JOB HOPPERS

If you've switched jobs in a financial year and received more than one Form 16, digital versions make it easy. You can just upload both, and the system will merge the details automatically, no need to manually add them up.

GOING GREEN

There's also a small but important environmental benefit. By using digital forms instead of printed ones, we save paper and reduce waste, thereby helping the planet, one step at a time.

Government clears 187 startups for tax relief. Here's what it means

New Delhi. In a welcome move for budding businesses, the Indian government has approved 187 start-ups for income tax exemption under the updated rules of Section 80-IAC of the Income Tax Act. This aims to give financial support to start-ups, helping them grow, create jobs, and bring in fresh ideas.According to a statement from the Commerce Ministry, the decision was taken during the 79th and 80th meetings of the Inter-Ministerial Board (IMB), held on April 30. A total of 75 start-ups were approved in the 79th meeting and 112 in the 80th. So far, over 3,700 start-ups have benefited from this scheme.

WHAT'S THE BENEFIT?

Under this scheme, eligible start-ups can enjoy a 100% income tax break on their profits for any three years of their choice within the first ten years from the time they were set up. The Union Budget 2025–26 has also extended the eligibility period. Now, start-ups registered by April 1, 2030 can apply for this tax relief.Finance Minister, Nirmala Sitharaman, in her Budget 2025 speech said, "It is proposed to extend the benefit provided under Section 80-IAC to startups for another period of five years, i.e. the benefit will be available to eligible start-ups incorporated before April 1, 2030."To qualify, the start-up must be recognised by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT). It should be a private limited company or a limited liability partnership and its turnover should not cross Rs 100 crore in any year since incorporation.

ADVERTISEMENT

The DPIIT has also made the application process easier and quicker. If your application is complete, it will be reviewed within 120 days. Start-ups that didn't make the cut this time are encouraged to improve their pitch, especially by highlighting their innovation, market potential, scalability, and ability to generate jobs.

SUPPORT BEYOND TAX RELIEF

Earlier, on May 9, the government also announced an update to its Credit Guarantee Scheme for Start-ups (CGSS). It doubled the credit guarantee per borrower from Rs 10 crore to Rs 20 crore. Now, loans up to Rs 10 crore come with 85% guarantee cover, while loans above that get 75%.This change is aimed at helping start-ups get easier access to funds, whether for day-to-day operations, long-term projects, or product development.

Defence stocks extend rally on possible budget boost. What should investors do

New Delhi. A blistering rally is underway in defence stocks. Cochin Shipyard, Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE), Mazagon Dock Shipbuilders, Bharat Electronics, Bharat Dynamics, Paras Defence, and Hindustan Aeronautics are all in the green. The NSE Nifty India Defence index surged over 5% intraday on Friday. Cochin Shipyard and GRSE have been leading the charge, with the latter gaining a stunning 30% since May 13.What's propelling this boom? A potent mix of strategic success, powerful earnings, and patriotic policy signals. India's recent cross-border military action, Operation Sindoor, was more than just a tactical victory and showcased India's advancement in defence technologies."The war unmistakably demonstrated the massive might of the Indian military powered by home-grown weapons and cutting-edge domestic technologies," says Dr. Manoranjan Sharma, Chief Economist at Infomerics Valuation and Ratings.That confidence is visible on Dalal Street. Cochin Shipyard jumped over 12% during the trading session and is up 33% in the past five trading sessions. GRSE wasn't far behind, soaring over 11% after doubling its Q4 net profit to Rs 224 crore and declaring a 138.5% dividend payout. Cochin Shipyard also delivered a 27% jump in profits with a healthy final dividend.WHAT SHOULD INVESTORS DO?Analysts believe this is no flash in the pan.

According to Antique Stock Broking, the combined order books of Cochin Shipyard, GRSE, and Mazagon Dock are expected to more than triple by FY27, citing a strong government push for indigenisation, rising export potential, and recently cleared contracts worth Rs 54,000 crore.Adding further fuel to the rally is a powerful budget proposal. Sources indicate the defence budget is likely to get more firepower, with increased spending directed towards weapons, ammunition, and technology following Operation Sindoor. A supplementary budget proposal of Rs 50,000 crore is on the table, expected to receive approval in the Winter session of Parliament. This additional provision signals strong policy support for continued defence sector growth.

"This seamless integration of indigenous hi-tech systems across the development spectrum was done in a telling manner—and the rest is history," Dr. Sharma added.But it's not just the war or policy winds driving the rally. Strong earnings are at play as well. GRSE posted 62% revenue growth, while Mazagon Dock and Paras Defence have seen substantial upticks. Bharat Dynamics and BEL also rode the wave with intraday gains between 4% and 8%.Despite the euphoria, some voices call for measured optimism. Dr. V.K. Vijayakumar, Chief Investment Strategist at Geojit Financial Services, warns,"The medium to long-term prospects of defence companies, particularly exporters, look bright. However, the valuations of these stocks are high and, therefore, investors have to be cautious."

What Pakistan can and can't do with IMF loan

The International Monetary Fund (IMF) has approved a fresh loan package for Pakistan, agreeing to release USD 1 billion under its Extended Fund Facility (EFF).

Every time Pakistan's economy catches fire, the IMF shows up like a firefighter with a big hose of dollars. For decades, it's been a lifeline, quietly stitching up Pakistan's collapsing economy.The IMF's recent bailout decision has drawn criticism, with observers pointing out that it came shortly after a deadly terror attack in Pahalgam, Kashmir. At the time, tensions between India and Pakistan were still running high, though the situation has since calmed following a ceasefire agreement.The International Monetary Fund (IMF) has approved a fresh loan package for Pakistan, agreeing to release USD 1 billion under its Extended Fund Facility (EFF).

This brings the total amount released under this programme to USD 2.1 billion.

Alongside this, the IMF has also given the go-ahead for another USD 1.4 billion under the Resilience and Sustainability Facility (RSF), which is meant to help Pakistan deal with problems linked to climate change.The decision was made at the IMF Executive Board meeting earlier this month. India did not support the move and chose to abstain from voting.

After the vote, the Indian Finance Ministry said the IMF's process lacked proper safeguards. It warned that such money flows could be redirected towards military or terrorist activities.

HOW PAKISTAN CAN USE THE IMF LOAN?

The money given to Pakistan is meant to keep its economy stable and prevent it from collapsing completely. The country is facing high levels of debt, a falling rupee, and severe pressure on its foreign exchange reserves.Dr. Manoranjan Sharma, Infomerics Valuation and Ratings aid that this bailout is ostensibly intended to keep Pakistan's economy from collapsing, subject to conditions: cut subsidies, tax the untaxed, stop the rupee's freefall, and most importantly, close the war."But the proof of the pudding is in the eating. Given Pakistan's abysmal track record in using previous financial aid responsibly and concerns about the misuse of IMF funds, India opposed this bailout," he added.

HISTORY OF BAILOUTS AND DEBT

Pakistan has received financial help from the IMF many times. Since 1958, the country has taken 24 bailouts. Yet, its economic problems continue. Experts say this is due to long-standing structural problems in the economy and weak governance."The IMF's own report reveals that continued bailouts have pushed Pakistan into a vicious circle of debt, essentially turning it into a massive defaulter for the IMF," said Sharma.

"Pakistan's complete economic mess and the saga of diversion of funds necessitate a close and careful monitoring and evaluation of the IMF's funds on an ongoing real-time basis. This assumes greater significance because of Pakistan's past track record of flagrantly violating the IMF's conditionalities with impunity," he added.While the IMF might have come to Pakistan's aid again, the world will be keeping an eye on whether the money disbursed is used to indirectly support Pakistan's military and terrorist groups like Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed.

Defence budget may get Rs 50,000-crore push amid Operation Sindoor: Sources

The additional spending will be directed towards the purchase of weapons and ammunition, as well as technology, following Operation Sindoor.

New Delhi. The defence budget is likely to get more firepower, with spending directed towards the purchase of weapons and ammunition, as well as technology, following Operation Sindoor, sources said. A proposal has been made for an additional provision of Rs 50,000 crore through a supplementary budget.

It may receive approval in the Winter session of Parliament.With the extra allocation, provisions are likely to be made for the armed forces' requirements, essential procurements, and research and development.This year, a record Rs 6.81 lakh crore was allocated in the Union Budget for defence, an increase of 9.53% from the previous financial year.

Since the NDA government came to power, the defence budget has seen an almost threefold increase over the past 10 years.

In 2014-15, the defence budget was Rs 2.29 lakh crore. This year, Rs 6.81 lakh crore has been allocated, which is 13.45% of the total budget.

Operation Sindoor, where India destroyed nine terror camps deep inside Pakistan without crossing the border, showcased the superiority of India's defence capabilities over Pakistan.

During the hostilities with Pakistan, India's multi-layered air defence system, including its indigenous technology, neutralised almost every incoming missile and drone.Apart from the long-range Russian S-400 'Triumf' system, India deployed the Barak-8 medium-range SAM system and the indigenous Akash system to thwart Pakistani drones and missiles. Battle-proven air defence systems like the Pechora, OSA-AK and LLAD guns (low-level air defence guns) were also used.

With Operation Sindoor demonstrating the capabilities of India's own advanced weapons, Prime Minister Narendra Modi praised the achievement in his address on May 12.

"During this operation, the credibility of our Made-in-India weapons was firmly established. The world now recognises that the time for Made-in-India defence equipment in 21st-century warfare has arrived," PM Modi said.

Ex-Chief Justice DY Chandrachud joins Law University as Distinguished Professor

New Delhi. Former Chief Justice of India DY Chandrachud has now assumed a new role where he will be mentoring young law aspirants as he has joined the National Law University (NLU) in Delhi as a Distinguished Professor, the institute said in a statement on Thursday.DY Chandrachud served as the Chief Justice of India for two years from November 2022 to November 2024 and was succeeded by Justice Sanjiv Khanna.

"This historic association marks a transformative chapter in Indian Legal education, bringing one of our most progressive jurists to mentor the next generation of legal minds," the statement said.

"This marks a pivotal moment in legal academia as one of India's most visionary jurists joins us to shape future generations of lawyers, scholars, and changemakers," it added.Professor GS Bajpai, NLU Vice Chancellor, expressed optimism, saying that the collaboration will see the establishment of a dedicated Centre for Constitutional Studies, where Justice Chandrachud will guide pioneering research.

The university further said that it was going to launch "In the Spirit of Justice: The DYC Distinguished Lecture Series" in order to create a platform for engaging with contemporary legal challenges through Justice Chandrachud's experience and insights about the legal workspace.

The law institution said that it seeks to learn from Justice DY Chandrchud's landmark judgments on privacy, LGBTQ+ rights, and gender justice to his work on digital freedoms and judicial reforms."His presence will profoundly enrich our academic ecosystem. Now, his wisdom will directly fuel NLU Delhi's mission to build a more just and equitable legal system," it said.NLU Delhi said it was commitment to fostering legal scholarship that bridges theory with social transformation following the visionary association of Justice Chandhrachud.

Frivolity has its limits: Delhi HC tells man over plea calling BNS 'criminal act'

NEW DELHI. The Delhi HC on Wednesday found itself dealing with a curious case involving a self-represented litigant, an internet-inspired theory and a dramatic accusation that the Union government had committed a "criminal act" by updating the country's penal laws.

The case was brought by one Upendra Nath Dalai, a native of Odisha, who filed a public interest litigation (PIL) challenging the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), the law that recently replaced the Indian Penal Code of 1860.According to Dalai, this legislative move was similar to the government "killing its parents" while referring, rather dramatically, to the Constitution and the basic structure of Indian democracy.

The Division Bench, comprising Chief Justice DK Upadhyaya and Justice Tushar Rao Gedela, appeared visibly unimpressed and puzzled."What sort of language is this? What exactly are you asking for?" the judges asked, clearly struggling to make sense of the plea.

Delhi Metro joins ONDC, users can now book tickets through popular apps

NEW DELHI. The Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has become the first large-scale urban transit system in India to join the Open Network for Digital Commerce (ONDC).This step ushers in a new era of commuter convenience, transforming how millions of Delhiites access metro services every day.

Soft-launched in November 2024, DMRC's presence on the ONDC Network is now fully operational, enabling commuters to book metro tickets through more than 10 popular consumer apps.These include platforms like Google Maps, Redbus, EaseMyTrip, Rapido, NammaYatri, and even a Telegram-based bot from Miles & Kilometres. With this integration, DMRC has eliminated a major pain point for users: the need to download a separate metro app.

Now, booking a metro ticket is as seamless as ordering a cab or planning a trip—done right from the apps commuters already use.

Whether it's Google Maps for navigation, Rapido for last-mile transport, or Redbus for intercity travel, Delhi Metro tickets are now just a tap away. For example, an intercity traveller arriving in Delhi from Jaipur via Redbus can book a connecting metro ticket from ISBT Kashmere Gate to any destination in the city without leaving the app.

Rs 50L tender for reconstruction of Dilli Haat shops damaged in fire

NEW DELHI. The Delhi government has approved a tender of Rs 49.83 lakh for the reconstruction of shops at Dilli Haat INA that were gutted in a massive fire last month, officials said on Thursday.

On the night of April 30, a major fire broke out at Dilli Haat, one of the national capital's most popular open-air markets located opposite INA Market in South Delhi destroying around 25 to 30 shops and causing extensive damage to semi-permanent structures.The Delhi Tourism and Transportation Development Corporation has issued the tender for rebuilding the damaged shops and carrying out necessary alterations to minimise the risk of future fire incidents, officials said. Among the total sanctioned amount of Rs 49,83,055, Rs 40,85,763 has been earmarked for civil work and Rs 8,97,292 for electrical instalations, they added.According to the tender document, the reconstruction will include wiring for lighting, fans, exhausts, call bells and other essential electrical components. The civil work will include laying cement concrete for structural elements such as retaining walls, return walls, vertical supports and pilasters. It will also include installation of aluminum doors and windows, fire-check doors, stainless steel doors, waterproofing treatments, textured paint, and safety railings, the officials said.An official from Delhi Tourism said that shops destroyed in the fire will be rebuilt, while those with iron grilles will now be enclosed with brick walls to enhance fire safety and durability.

ED seizes cash, assets worth Rs 32 crore in Vasai-Virar civic body land scam

New Delhi. The Enforcement Directorate (ED) has recovered cash worth Rs 9.04 crore and diamond jewellery, bullion and documents valued at Rs 23.25 crore in the search operation conducted in the Vasai-Virar Municipal Corporation (VVMC) scam case, officials said on Thursday. The seizure was made in the raids conducted at 13 different locations belonging to various accused across Mumbai and Hyderabad on May 14 and 15.The raids, carried out as per the provisions of the Prevention of Money Laundering Act, 2002, were part of an investigation which was launched by the financial probe agency based on multiple FIRs registered by the Mira Bhayandar Police Commissionerate.

The case pertains to the illegal construction of 41 residential-cum-commercial buildings on the land reserved for Sewage Treatment Plant and Dumping Ground as per the approved development plan of Vasai-Virar City, falling under the jurisdiction of the VVMC.

During the investigation, the ED found that the accused allegedly acquired 30 acres of land from private owners and an additional 30 acres reserved for government projects, including a dumping ground and a Sewage Treatment Plant (STP) through forged documents.To bolster their claim, the accused created an elaborate trail of handing over these land parcels in the names of dead persons. Ultimately, they sold the land to various builders using fake ownership documents.The accused builders and developers, in close connivance with VVMC officials, started constructing illegal residential-cum-commercial buildings from the year 2009 onwards without obtaining Construction Permits (CC) or Occupancy Certificates (OC), ED officials said.They then deceived and cheated the public at large by constructing illegal buildings and subsequently selling it to them by fabricating approval documents.The Bombay High Court, in its July 2024 ruling, ordered the demolition of all 41 buildings. Thereafter, a Special Leave Petition was filed before the Supreme Court by the families residing in 41 illegal buildings, which was dismissed. The demolition of all 41 buildings was completed by VVMC on February 20, 2025.

INDIA alliance is frayed: P Chidambaram expresses concerns over bloc's future

New Delhi. Senior Congress leader P Chidambaram on Thursday voiced concerns about the INDIA bloc, saying he was not sure if the opposition alliance was still intact.Speaking at the launch of Salman Khurshid and Mritunjay Singh Yadav's book "Contesting Democratic Deficit", Chidambaram also said he felt that it showed at the seams that the alliance was frayed."The future (of INDIA bloc) is not so bright, as Mritunjay Singh Yadav said. He seems to feel that the alliance is still intact, but I am not sure. It is only Salman (Khurshid) who can answer because he was part of the negotiating team for the INDIA bloc. If the alliance is totally intact, I will be very happy. But it shows at the seams that it is frayed," Chidambaram, a Rajya Sabha MP, said.

He also hoped that the alliance can "still be put together, there's still time".The former Union finance minister warned that the INDIA bloc was fighting against a "formidable machinery", which must be fought on all fronts."In my experience and my reading of history, there has been no political party so formidably organised as the BJP. It's not just another political party. It's a machine behind a machine and the two machines control all the machineries in India.

"From the Election Commission to the lowest police station in the country, they (BJP) are able to control and sometimes capture these institutions. It is a formidable machinery, as much as can be allowed in a democracy," Chidambaram said.In the book, Khurshid and Yadav reflect on the Congress' revival efforts ahead of last year's Lok Sabha elections -- from the emotionally-charged "Bharat Jodo Yatra" to the "historic" formation of the INDIA bloc comprising diverse political forces.Khurshid and Yadav recount how the opposition parties rallied "to defend the idea of an inclusive, pluralistic India".

Samajwadi leader's 'casteist' remark on Vyomika Singh sparks row. What he said

New Delhi. Samajwadi Party leader Ramgopal Yadav has triggered a political storm by alleging that a BJP Minister targeted Army officer Colonel Sofiya Qureshi because she is Muslim, while sparing Wing Commander Vyomika Singh, assuming she was Rajput.Yadav made the controversial remarks at a programme in Moradabad, referring to the previous remark by Madhya Pradesh BJP minister Vijay Shah — who allegedly made an insulting remark against Colonel Qureshi. Yadav said, "One of their ministers abused Colonel Qureshi. The high court has ordered a case against him again. But he didn't know who Vyomika Singh or Air Marshal AK Bharti were. Otherwise, they'd have targeted them too".The Samajwadi Party leader then identified Singh and Bharti by caste, saying Singh is a Jatav from Haryana and Bharti is a Yadav from Purnia."All three were from PDA (Picchda, Dalit, Alpsankhyak — backwards, Dalits, minorities). One was abused because she was Muslim, another was spared thinking she was Rajput, and the third was not known. Now that it's in the papers, they're thinking about what to do".Yadav also accused the BJP of prioritising self-glorification over acknowledging the armed forces' contributions. "When the mentality is bad, instead of speaking about the Army's achievements, they highlight their own".Operation Sindoor, India's strike on terror camps in Pakistan and Pakistan-Occupied-Kashmir (POK) in response to the deadly Pahalgam attack, featured briefings from Wing Commander Vyomika Singh, Colonel Sofiya Qureshi, and Foreign Secretary Vikram Misri earlier this month.

Yadav also questioned the BJP's Tiranga Yatra campaign and said, "They do everything for elections. Why take out a Tiranga Yatra now? Were the people fighting in Operation Sindoor BJP people?" news agency PTI quoted Yadav as saying.Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath came down heavily on Yadav's remarks, calling them a grave insult to the armed forces.

Airports end agreement with Turkish aviation firm after India revokes clearance

Delhi, Mumbai, and Ahmedabad airports have terminated contracts with Turkish aviation company Celebi after the Indian government revoked its security clearance, citing national security concerns.

New Delhi. Mumbai, Delhi and Ahmedabad Airports have severed ties with Turkish aviation ground-handling company Celebi following the Indian government's decision to revoke its security clearance in the interest of national security.Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (CSMIA) and Ahmedabad's Sardar Vallabhbhai Patel International Airport (SVPIA) have both terminated ground handling concession agreements with Celebi. Delhi International Airport Ltd (DIAL) also formally ended its association with Celebi following the Bureau of Civil Aviation Security's (BCAS) decision.

"Following the Government of India's decision to revoke Celebi's security clearance, we have terminated the ground handling concession agreements with Celebi at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (CSMIA) and Ahmedabad's Sardar Vallabhbhai Patel International Airport (SVPIA). Accordingly, Celebi has been directed to immediately hand over to us all ground handling facilities to ensure uninterrupted operations," said spokespersons of the Mumbai and Ahmedabad airports.Similarly, DIAL also issued a statement saying, "In compliance with the BCAS directive, [DIAL] has formally ended its association with Celebi entities responsible for ground handling and cargo operations at Indira Gandhi International Airport (IGIA). Following the termination, DIAL is working closely with existing service providers to ensure uninterrupted operations while safeguarding employee welfare,"

The BCAS revoked the company's security clearance through an order dated May 15, citing national security concerns. The action follows increasing diplomatic tensions with Turkey after it publicly supported Pakistan and criticised India's military operation in Operation Sindoor — which was launched in response to the April 22 Pahalgam terror attack.Celebi NAS Airport Services, a Turkish firm, plays a crucial role in airport operations across India, including at major hubs such as Delhi, Mumbai, and Chennai. It manages vital services such as ground handling, cargo, and airside operations — areas considered highly sensitive under aviation regulations.In response to the government's move, Celebi Aviation India issued a statement rejecting what it described as "misleading and factually incorrect allegations" about the company's ownership and operations.

NEWS BOX

Sikh Man, 78, Arrested In Canada For Alleged Sexual Assault

Ottawa. A 78-year-old Sikh man was arrested and charged for allegedly sexually assaulting a minor thrice earlier this month in Canada's Brampton, police said on Thursday.Harmohinder Singh was arrested on May 8 by the Special Victims Unit, Peels Police said is a statement.Singh approached a female victim under the age of 12 and sexually assaulted her on three separate occasions at a park in Brampton, it said.He was charged with three counts of sexual assault of a female under 17 and three counts of sexual interference.Singh was held in custody pending a bail hearing at the Ontario Court of Justice in Brampton, the statement added."Investigators believe there may be additional victims and witnesses," it said, urging anyone with information to contact authorities.

Pakistan PM Shehbaz Sharif Offers Dialogue With India "For Peace"

Islamabad. Prime Minister Shehbaz Sharif on Thursday extended an offer of talks to India, saying Pakistan is ready to engage "for peace".

Shehbaz made the comments during a visit to the Kamra air base in the country's Punjab province where he interacted with officers and soldiers involved in the recent military confrontation with India."We are ready to talk with it (India) for peace," he said.The prime minister added that the "conditions for peace" include the Kashmir issue.

India has maintained that the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh "are and always will be integral and inalienable parts of it".Shehbaz was accompanied to the airbase by Deputy Prime Minister Ishaq Dar, Defence Minister Khawaja Asif, Army Chief General Asim Munir, Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Baber Sidhu.

This was the prime minister's second visit to a defence facility following the understanding reached between India and Pakistan India on May 10 to end the conflict after four days of intense cross-border drone and missile strikes. India launched Operation Sindoor on the intervening night of May 6 and 7 to avenge the killings of 26 people in the Pahalgam terror attack.

Indian armed forces targeted nine terror sites in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, killing over 100 terrorists.Pakistan then attempted to attack several Indian military bases on May 8, 9 and 10.The Indian armed forces launched a fierce counter-attack on several Pakistani military installations, including Rafiqui, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukkur and Chunian.On Wednesday, Shehbaz visited Pasrur Cantonment in Sialkot where he interacted with soldiers.

Hezbollah Member Killed In Israeli Strikes On Lebanon

Beirut. A teenage boy was found dead with his throat slit in Delhi's Nizamuddin area after he tried to persuade one of the accused to allow his sister to continue her relationship with the victim's friend, police said on Thursday.Md Saad (18), who was previously involved in two criminal cases, was found dead with a deep cut on his throat, DCP (Southeast) Ravi Singh said.The accused have been identified as Altamash (18), the main assailant and a battery repair worker, Faizan (22), a rickshaw driver and history-sheeter from Kot Mohalla, Dilshad (18), and Abrar (18), who have all been taken into custody, the oBeirut, May 16 (IANS) Israeli drones carried out multiple airstrikes across southern Lebanon, killing a Hezbollah member and destroying several prefabricated structures, Lebanese security and official sources said.

Lebanon's Ministry of Health said on Thursday in a statement that an Israeli drone strike targeting a vehicle on the Arnoun-Yohmor road killed one person, Xinhua news agency reported.

A Lebanese security source identified the victim as Mohammad Ali Marouni, a Hezbollah member from the town of Arnoun in the Nabatieh district, deep in southern Lebanon.aAccording to Lebanese official sources, three Hezbollah members have been killed and a fourth wounded in separate Israeli strikes on southern Lebanon over the past 48 hours.In a related incident, Lebanon's state-run National News Agency reported that an Israeli Apache helicopter carried out three consecutive strikes within half an hour on the village of Houla in southeastern Lebanon, targeting a prefabricated structure belonging to the Wataawano Association.The agency added that at dawn, the Israeli army struck another prefabricated building in the village of Adaisseh.Separately, a drone dropped a stun grenade on a house in Kfar Kila, while another drone dropped a similar device over the ruins of al-Dhahira School in the western sector of southern Lebanon.The cross-border strikes come despite a ceasefire agreement reached on November 27, 2024, intended to halt more than a year of hostilities tied to the war in Gaza.An Israeli drone strike killed a Hezbollah member in southern Lebanon on Wednesday, targetting a vehicle near Qaaqaait al-Jisr in the Wadi al-Hujayr area, Lebanese security and official sources said.Lebanon's state-run National News Agency (NNA) reported on Wednesday that "an enemy drone targeted a car at the entrance of Wadi al-Hujayr near Qaaqaait al-Jisr in the Nabatieh district this morning".According to Lebanese official sources, three Hezbollah members have been killed and a fourth wounded in separate Israeli strikes on southern Lebanon over the past 48 hours.In a related incident, Lebanon's state-run National News Agency reported that an Israeli Apache helicopter carried out three consecutive strikes within half an hour on the village of Houla in southeastern Lebanon, targeting a prefabricated structure belonging to the Wataawano Association.The agency added that at dawn, the Israeli army struck another prefabricated building in the village of Adaisseh.Separately, a drone dropped a stun grenade on a house in Kfar Kila, while another drone dropped a similar device over the ruins of al-Dhahira School in the western sector of southern Lebanon.The cross-border strikes come despite a ceasefire agreement reached on November 27, 2024, intended to halt more than a year of hostilities tied to

West Pitching India, China Against Each Other: Russian Foreign Minister

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov also called for a collective security arrangement in Eurasia.

Moscow.The West is pitching India and China against each other, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said here on Thursday.Lavrov made the remarks at a meeting of the "Culture without Borders: the Role and Development of Cultural Diplomacy" diplomatic club, according to the state-run TASS news agency.

"Take note of the current developments in the Asia-Pacific region, which the West has started calling the Indo-Pacific region to give its policy a clear anti-China orientation — expecting thereby to additionally clash our great friends and neighbours India and China," Lavrov said.

Lavrov, who was a vocal critic of the QUAD grouping comprising India, Australia, Japan and the US to contain China, has muted his criticism after the setting up of AUKUS -- a military alliance of Australia, the UK and the US.The foreign minister said the West is trying to undermine the role of ASEAN in Asia.

"Western colleagues, as in any other part of the world, want to play a major role here, they want to undermine the central role of ASEAN, which suited everyone for many, many decades and was based on the formation of a unifying space by the ASEAN countries and their partners in dialogue both in the field of politics and in the field of military cooperation, in the field of defence," Lavrov was quoted as saying by TASS.The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is a regional grouping of 10 countries in Southeast Asia, aiming to promote economic and security cooperation among its members. The 10 member states are Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei, Myanmar, Cambodia, Laos, and Vietnam.

"The rules of consensus, the search for common ground - all this our Western colleagues are beginning to push aside little by little and are trying to lure some ASEAN members into openly confrontational rather than unifying formats: various troikas, quartets," Lavrov said.

He also called for a collective security arrangement in Eurasia.

"There are no other continents like Eurasia, where so many civilisations coexisted and maintained their identity and relevance in the modern era, and at the same time, Eurasia is the only continent where there is no continent-wide structure. In Eurasia, there is a need for such a unification process so that the interests of many large, truly great powers and civilisations are harmonised," Lavrov said.

New Covid-19 wave spreads in Asia, infections rise in Hong Kong and Singapore

Covid-19 cases are rising sharply in Hong Kong and Singapore, with health officials warning of a new wave across Asia. According to reports, the increase may be a reflexion of declining immunity.

world. Health officials in Hong Kong and Singapore have warned about a sharp rise in Covid-19 cases as a new wave is spreading across many parts of Asia, Bloomberg reported.Albert Au, the head of the Communicable Disease Branch at Hong Kong's Centre for Health Protection, told local media that Covid-19 activity in the city is now "quite high."The number of respiratory samples that proved positive for Covid-19 was at its peak last year. Severe cases and death count reached their peak level, with 31 severe cases noted in the week up to May 3.While this present spike is not as big as the largest outbreaks during the previous two years, other indicators show the virus is spreading. There were more Covid-19 detected in sewage water, and more people are going to hospitals and clinics with symptoms of Covid.

COVID CASES SURGE IN SINGAPORE

Singapore, another crowded city in Asia, is also reporting more cases of Covid. The health ministry of the country reported its first update on cases in nearly a year this May. The cases of Covid increased by 28% to around 14,200 during the week ending May 3 from the previous week. The cases of hospital admissions due to Covid increased by around 30%.Singapore reports case numbers only if there is a definite rise. The health ministry indicated that the increase may be a reflexion of declining immunity in the population but had no evidence that new virus strains are more infectious and lead to more serious illness.

COVID CASES INCREASE IN ASIA

All over Asia, Covid infections have been increasing for months with waves of infection recurring from time to time. Health authorities are reminding everyone to take their vaccinations, particularly for those at increased risk who should receive booster shots.

The recent surge in Covid cases in summer when other viruses typically become weaker shows that Covid will remain contagious even in the summer.

Hong Kong pop star Eason Chan was found to be Covid-positive and had to postpone his Taiwan concerts, said his official social media account on Weibo.

Bloomberg reported that China is also experiencing a new wave of Covid, which is projected to approach last summer's peak. The Covid test positivity rate amongst the people of China has more than doubled over the five weeks through May 4.

Two major Covid outbreaks were reported this year by Thailand's Department of Disease Control, with cases increasing following the Songkran festival last April, which brings people together in crowds.

US and Iran have 'sort of' agreed on nuclear deal terms: Donald Trump

world. In true Trumpian fashion, President Donald Trump declared that the US and Iran had "sort of agreed to the terms" of a potential nuclear deal — minus any of what he dubbed "nuclear dust."Trump, in an exchange with reporters at a business roundtable in Doha, Qatar, described talks between American envoy Steve Witkoff and Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi as "very serious negotiations" for long-term peace and said they were continuing to progress.

"Iran has sort of agreed to the terms: They're not going to make, I call it, in a friendly way, nuclear dust," Trump said at the business event. "We're not going to be making any nuclear dust in Iran."Without offering detail, Trump signaled growing alignment with the terms that he has been seeking.Trump said his demands have been straightforward. "They can't have a nuclear weapon. That's the only thing. It's very simple," Trump said. "It's not like I have to give you 30 pages worth of details. It is only one sentence. They can't have a nuclear weapon."On Wednesday, Ali Shamkhani, a senior adviser to Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, told NBC News that Tehran is willing to eliminate its stockpiles of highly enriched uranium, which can be weaponized, and limit enrichment to lower levels needed for civilian purposes. In return, Iran wants an immediate removal of all economic sanctions.Meanwhile, on Thursday, Araghchi emphasized that Iran's right to enrich uranium remains a non-negotiable stance in nuclear talks. "Defending Iran's nuclear rights, including enrichment, is a fundamental principle," he said. "This is not something we will concede in negotiations or public discussions. It is the right of the Iranian people, and no one can take it away."

Gulf Charm Offensive

Trump on Wednesday suggested he was looking for Tehran to make other concessions as part of a potential agreement. Iran "must stop sponsoring terror, halt its bloody proxy wars and permanently and verifiably cease pursuit of nuclear weapons," Trump said in remarks at a meeting in Saudi Arabia, the first stop on the Mideast trip. "They cannot have a nuclear weapon."Before moving on to the United Arab Emirates from Qatar on Thursday, Trump stopped at a US military installation at the center of American involvement in the Middle East and spoke to US troops. The Republican president has used his visit to Gulf states to reject the "interventionalism" of America's past in the region.Al-Udeid Air Base was a major staging ground during the US wars in Iraq and Afghanistan. The base houses some 8,000 US troops, down from about 10,000 at the height of those wars.Trump told the troops that his "priority is to end conflicts, not start them."But I will never hesitate to wield American power if it's necessary to defend the United States of America or our partners," he said.Trump has held up Gulf nations such as Saudi Arabia and Qatar as models for economic development in a region plagued by conflict. He urged Qatari officials to use their influence to entice Iran to come to terms with his administration on a nuclear deal.

Trump Secures $200 Billion UAE Deals, Burj Khalifa Glows Up In US Flag Colours

Abu Dhabi.US President Trump announced over USD 200 billion in commercial deals between the United States and the United Arab Emirates--bringing the total of investment agreements in the Gulf region to over USD 2 trillion.President Trump arrived in Abu Dhabi on Thursday, following earlier visits to Saudi Arabia and Qatar as part of his tour of the Middle East. He was received at Abu Dhabi International Airport by UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.As per the White House, Boeing and GE Aerospace secured a USD 14.5 billion commitment from Etihad Airways to invest in 28 American-made Boeing 787 and 777X aircraft powered by GE engines. With the inclusion of the next-generation 777X in its fleet plan, the investment deepens the longstanding commercial aviation partnership between the UAE and the United States, fueling American manufacturing, driving exports, and supporting 60,000 US jobs.In Oklahoma, Emirates Global Aluminium will invest to develop a USD 4 billion primary aluminum smelter project, one of the first new aluminum smelters in America in 45 years, that will create a thousand jobs in America, strengthen critical mineral supply chains, and double current US production capacity.

ExxonMobil, Occidental Petroleum, and EOG Resources are partnering with the Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) for expanded oil and natural gas production valued at USD 60 billion that will help lower energy costs and create hundreds of skilled jobs in both countries.Holtec Internationaland IHC Industrial Holding Company (IHC) are entering cooperation to build a fleet of Holtec's SMR-300 small modular reactors, starting at the Palisades site in Michigan. This agreement includes a commitment of $10 billion, and an additional USD 20 billion for fleet projects, helping to revitalize American nuclear energy infrastructure, strengthen domestic energy security, and create high-skilled jobs in engineering, construction, and advanced manufacturing across the United States.

Today's deals strengthen the US-UAE investment and trade relationship and build on the UAE's landmark commitment to a 10-year, USD 1.4 trillion investment framework that will contribute to the US boom in AI infrastructure, semiconductors, energy, quantum computing, biotechnology, and manufacturing.

80 People Killed In Gaza As Israel Intensifies Bombardment

Since Israel resumed large-scale military operations in Gaza, at least 2,876 Palestinians have been killed and more than 7,800 injured, according to health officials in Gaza.

Gaza City. At least 80 Palestinians were killed and dozens of others wounded in Israeli airstrikes across Gaza, said Palestinian medical sources.The Nasser Hospital in Khan Younis reported that 54 people, including women and children, were killed in strikes on the southern city, according to a press statement on Thursday.

According to Gaza-based health authorities, the Gaza European Hospital, the only hospital providing medical follow-up care to cancer patients in the enclave, was out of service due to recent Israeli attacks, Xinhua news agency reported.

The Israeli attacks "caused significant damage to infrastructure, such as sewage lines, damage to internal departments, and destruction of roads leading to the hospital," the authorities said in a press statement.Meanwhile, medical sources told Xinhua news agency that 26 others were killed in Israeli airstrikes on Gaza City and other areas in northern Gaza.

The airstrikes came after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu warned on Tuesday that the Israeli military would enter Gaza "with full force" in the coming days to press forward with efforts to defeat Hamas.Israel resumed large-scale military operations in Gaza on March 18, ending a two-month ceasefire.Since then, 2,876 Palestinians have been killed and more than 7,800 injured, according to health officials in Gaza.The total Palestinian death count since the war erupted on October 7, 2023, has reached 53,010, the officials said on Thursday.Israel is using a policy of "reducing space and emptying populated areas to pressure citizens," Mahmoud Basal, spokesperson for the Civil Defence in Gaza, told Xinhua on Thursday.He also claimed that thousands of people spent the night in the streets amid threats of strikes on schools and shelters housing the displaced, adding that Israeli forces were obstructing emergency teams from reaching victims and systematically destroying Civil Defence infrastructure.

Since October 2023, the Israeli Army has pursued a brutal offensive on the Gaza Strip, killing more than 53,000 Palestinians so far, most of them women and children.

A US-backed humanitarian organisation will start work in Gaza by the end of May under an aid distribution plan, but has asked Israel to let the United Nations and others resume deliveries to Palestinians now until it is set up.No humanitarian assistance has been delivered to Gaza since March 2, and a global hunger monitor has warned that half a million people face starvation in Gaza.

NEWS BOX

Jasprit Bumrah automatic choice as captain, Shubman Gill vice-captain: Wasim Jaffer

New Delhi. Former batter Wasim Jaffer believes Jasprit Bumrah should be an "automatic choice" to lead the Indian Test team following Rohit Sharma's retirement. Rohit stepped away from Test cricket on May 7, concluding an illustrious career that spanned over 11 years, from 2013 to 2025.

With Rohit's departure, India now faces the challenge of appointing a new captain ahead of the five-match Test series against England.

According to a report by Sky Sports, Bumrah had previously withdrawn from captaincy considerations due to workload management, as he may not feature in all five Tests in England.However, sharing his thoughts on social media platform 'X', Jaffer suggested that if Bumrah is ready to take on the role, he should be appointed captain, with Shubman Gill named vice-captain to be groomed for the future."I think Bumrah is an automatic captaincy choice, unless he doesn't want the responsibility. He should be the captain with Gill as VC - stepping in whenever Bumrah needs rest," Jaffer wrote.

"This way Gill could also be groomed without the pressure of being the full time captain," Jaffer added.Bumrah first captained India during the rescheduled fifth Test against England at Edgbaston in Birmingham, a match India lost by seven wickets. However, he redeemed himself as a leader in November last year, guiding India to their biggest Test win in Australia by runs—a commanding 295-run victory at Perth Stadium.

He also stepped in as captain for the fifth and final Test at the Sydney Cricket Ground after Rohit Sharma opted out of the New Year's Test. Bumrah recently returned to competitive cricket after recovering from a back injury that had sidelined him during the Champions Trophy, where India clinched the title with a win over New Zealand in the final.

India's Test series against England starts on June 20 with the series opener at Headingley in Leeds.

Mitchell Johnson asks overseas players to skip IPL: Lives and safety most important

New Delhi. Former Australian fast bowler Mitchell Johnson has advised foreign cricketers against returning to India for the remainder of the Indian Premier League (IPL) in 2025. The tournament was abruptly halted earlier in May due to escalating air raids between India and Pakistan.Following extensive deliberations, the Board of Control for Cricket in India (BCCI) rescheduled the tournament to resume on May 17, with the final set for June 3.

Amongst those opting out is Jake Fraser-McGurk, who has cited personal reasons. As a result, the Delhi Capitals (DC) signed Bangladesh pacer Mustafizur Rahman for Rs 6 crore. Reports also suggest that Mitchell Starc has withdrawn, dealing another significant blow to DC's playoff hopes.

'No from me'

In a statement, Cricket Australia confirmed it will support players in their individual decisions regarding participation in the IPL. Johnson, who featured in 54 IPL matches between 2013 and 2018, emphasised that player safety should take precedence over financial incentives."While Cricket Australia has empowered players to make their own decisions, the weight of those choices can be heavy," Johnson wrote in his column for the West Australian.

"Cricket might involve mega bucks these days, but it is still just a game, and that has been brought sharply into focus after the Indian Premier League's hiatus this week," Johnson said.

"If I had to make a call whether to head back to India and finish the tournament, it would be an easy decision. It's a no from me. Lives and safety are the most important thing, not pay cheques," Johnson added.

Impact on WTC final preparations

He also warned that returning to India for the remainder of the IPL could disrupt the preparations of Australian and South African cricketers ahead of the World Test Championship Final, which begins on June 11 at Lord's Cricket Ground.

DRS: Who should be India's next Test captain after Rohit Sharma's retirement?

Rohit Sharma's retirement from Test cricket has created a significant leadership void in the Indian team. In this edition of the Democratic Review System, we explore the potential captaincy options India can consider ahead of their Test series against England.

New Delhi. India have several key decisions to make before finalising their squad for the upcoming five-match Test series against England. On May 7, Rohit Sharma announced his retirement from Test cricket, bringing an end to a career in the longest format that spanned over 11 years - from 2013 to 2025.Rohit's departure leaves a leadership void, and India must appoint a new captain as they begin their campaign in the 2023-25 World Test Championship cycle. Jasprit Bumrah, who led the team in the Perth and Sydney Tests during the 2024-25 Border-Gavaskar Trophy, was a strong candidate to take over.However, Bumrah has withdrawn from the captaincy race due to workload management, as he may not be available for all five Tests in England. This opens the door for Shubman Gill and Rishabh Pant, who are now the frontrunners for the role.

Gill has experience of leading India in five T20Is and has captained the Gujarat Titans (GT) since the 2024 IPL season. Pant, on the other hand, captained India in five T20Is in 2022 and has also led both the Delhi Capitals (DC) and the Lucknow Super Giants (LSG) in the IPL.In our latest instalment of the Decision Review System, India Today's sports journalists give their take on the issue. Read on.

Nikhil Naz: Ideally, Jasprit Bumrah would be my first choice. But since there are doubts over his participation on a consistent basis in the red-ball format owing to workload management; Rishabh Pant then, for me, would be the ideal candidate to take over the mantle from Rohit Sharma. Despite his meagre returns with the bat in the white-ball format in the recent past, Rishabh still

remains a sure-shot starter in India's red ball format. A proven match winner in tests, coupled with his astute captaincy during the IPL, makes him the perfect candidate for the leadership role. Maybe Bumrah could be vice-captain and the perfect sounding board for Rishabh as he settles into his new job.

Akshay Ramesh: Why are we hyping up Shubman Gill right now? Is he even a certainty in the playing XI at this point? The last time he scored a fifty in SENA countries or the West Indies was back in 2021, during the famous win at the Gabba.

Why add extra pressure on a young batter who is still struggling to cement his place in the Test side?If I were a selector, I'd appoint Jasprit Bumrah as captain and name a strong vice-captain who can step in when Bumrah is unavailable.

And if Bumrah himself isn't keen on taking up the role, why not hand it to Rishabh Pant? The wicketkeeper-batter has arguably been India's best red-ball performer across all conditions. Back Pant for two years - captaincy and responsibility might just bring out the very best in him.Saurabh Kumar: If India need a Test captain, who better than Jasprit Bumrah? He is a national treasure and has already led in two Tests, including one in Australia. If Pat Cummins can captain Australia in both Tests and ODIs despite his history of back stress fractures, why can't Bumrah take on the leadership role for India?However, if Bumrah is not considered due to his fitness concerns, India should seriously consider rewarding Rishabh Pant with the captaincy. Pant may be enduring a rough patch in the IPL, but let's not forget that he is one of India's finest Test batters in overseas conditions. While Shubman Gill is yet to prove his mettle abroad, Pant averages over 42 in Tests and has scored centuries in Australia, England, and South Africa, along with seven scores in the 90s.

IPL 2025: Will Jacks confirms India return with special post as MI get major boost

Will Jacks shared a photo from his flight to Mumbai, confirming his return for the remainder of IPL 2025 and handing Mumbai Indians a timely boost as other overseas stars continue to opt out.

New Delhi. Mumbai Indians have received a timely lift ahead of the IPL 2025 resumption, with England all-rounder Will Jacks confirming his return to India through a special post on social media. Quelling the speculation over his availability, Jacks posted an Instagram story showing himself onboard a flight back to Mumbai, signalling his commitment to rejoin the side for the remainder of the season.Doubt had loomed over the participation of several overseas players following the temporary suspension of the tournament due to heightened military tensions between India and Pakistan. With foreign players being flown back home as a precaution, many franchises were left unsure of their squad strength heading into the final leg.

Jacks' return comes as a welcome sign for MI, who are still in the hunt for a playoff spot, sitting 4th on the points table with 14 points. The England star becomes one of the few overseas cricketers to confirm his return, especially as several Australian and South African players—key contenders for the World Test Championship final beginning on June 11—have already ruled themselves out of the tournament restart.

The decision to halt the IPL mid-season followed an abandoned match between Delhi Capitals and Punjab Kings in Dharamshala, which was called off due to an air strike alert near the venue. In the interest of player safety, the BCCI and IPL governing body swiftly moved to send foreign players back home.The league will resume on 17 May with Royal Challengers Bengaluru taking on Kolkata Knight Riders. However, a number of franchises are still grappling with uncertainty regarding their overseas contingent. Key names like Mitchell Starc and Jake Fraser-McGurk have opted out of returning, and reports suggest the entire South African squad may skip the remaining matches.With playoff places on the line, the return—or absence—of overseas talent will be pivotal. Franchises are now faced with either signing replacements or relying on their existing line-ups to deliver under pressure.Despite not making massive headlines with the bat, Jacks has been a useful asset for Mumbai Indians this season, scoring 195 runs and taking five wickets across 11 appearances. MI are set to face Delhi Capitals and Punjab Kings in their final two league matches, where back-to-back wins will be crucial to secure a place in the top four.

James Anderson returns to competitive cricket, named in Lancashire County squad

New Delhi. James Anderson is all set to make a comeback to competitive cricket since last taking the field in his farewell Test against West Indies back in July 2024 at Lord's Cricket Ground. The 42-year-old speedster has been named in the Lancashire squad for their upcoming County Championship Division 2 match against Derbyshire to start on Friday, May 16 at the Emirates Old Trafford in Manchester.

After bidding goodbye to international cricket, Anderson also worked as the bowling consultant for the England men's team. Last year, he joined Muttiah Muralitharan and Shane Warne in the elite list of bowlers with 700 or more Test wickets.In 188 Tests since his debut in 2023, Anderson has taken 704 wickets at an economy rate of 2.79 with 32 four-wicket hauls, 32 five-wicket hauls and three 10-wicket hauls. Anderson also holds the record for most wickets at a single venue by a fast bowler in Tests. In 29 Tests at Lord's, Anderson picked up 123 wickets at an economy rate of 2.71.

Anderson couldn't play in the first five county matches for Lancashire due to a calf injury. The match against Derbyshire will also be Marcus Harris' first as Lancashire's interim captain. Earlier, Keaton Jennings stepped down following the 70-run defeat to Northamptonshire at the County Ground in Northampton.

Following the defeat, Lancashire's director of cricket performance, Mark Chilton, called the team's form "unacceptable" and said the club would "make the necessary changes" to address the situation.Lancashire have had a disastrous campaign thus far as they are languishing at the bottom of the table with 50 points, having not yet won a single game.

Lancashire squad

Marcus Harris ©, James Anderson, Tom Bailey, George Balderson, George Bell, Josh Bohannon, Tom Hartley, Matty Hurst, Keaton Jennings, Michael Jones, Anderson Phillip, Ollie Sutton, Luke Wells, Will Williams.

Mitchell Starc decides against returning to India for remainder of IPL 2025: Reports

New Delhi. Delhi Capitals and Australia's premier pacer Mitchell Starc has decided against returning to India for the remainder of the IPL 2025 season. His absence delivers a significant blow to DC's bowling attack and forces the franchise into a race against time to either find a replacement or rely on their existing roster to step up.Starc becomes one of the prominent names to opt out of the IPL's resumption on May 17, after the tournament was halted due to rising military tensions between India and Pakistan. The veteran left-arm pacer had been part of the match against Punjab Kings in Dharamshala, which was eventually called off due to air strike alerts in areas near the border.

His decision to skip the remainder of the IPL clears the path for an uninterrupted preparation for the World Test Championship Final, where Australia will face South Africa at Lord's starting June 11.Delhi Capitals have already suffered the loss of Jake Fraser-McGurk, who also decided not to return. The franchise had signed Bangladesh pacer Mustafizur Rahman as a replacement, but his arrival remains uncertain as the Bangladesh Cricket Board is yet to issue him a No Objection Certificate. Bangladesh are currently engaged in a T20I against UAE in Sharjah.The situation remains fluid regarding overseas players returning for the final leg of IPL 2025. While DC await clarity on Faf du Plessis' availability, South African youngster Tristan Stubbs has confirmed his return — but only for the remainder of the league stage, should the team qualify for the playoffs.

Hansi Flick credits Barcelona's LaLiga title to team effort, not Lamine Yamal alone

Hansi Flick has transformed a youthful Barcelona side into LaLiga champions, but he insists their triumph is down to unity, discipline, and teamwork — not just the breakout brilliance of Lamine Yamal.

New Delhi. Barcelona head coach Hansi Flick underlined the importance of collective effort after guiding his side to their 28th LaLiga title, brushing aside suggestions that their triumph hinged solely on the brilliance of teenage sensation Lamine Yamal.

Yamal's decisive strike in the 53rd minute against city rivals Espanyol sealed a 2–0 victory on Thursday night and confirmed Bara as champions of Spain for the 2024–25 season. However, Flick was quick to deflect individual praise, insisting that it was a complete team performance that carried them over the line."It's Barcelona's LaLiga. It's not about one player, of course Lamine has been important, but we are a team and that's the most important thing. The team as a whole," Flick said in a press conference.

"Everyone has done their job very well. We are a team. This is what we wanted. We have given the best version for this club. All the fans can be proud," he added.

Flick's youthful Barcelona side entered the Espanyol clash needing just a single win from their last three fixtures to confirm the LaLiga crown, having edged out Real Madrid in a dramatic 4–3 El Clsico the week prior. Thursday night's derby remained goalless until Lamine Yamal produced a moment of individual brilliance shortly after the break. Fermin Lopez later doubled the advantage in stoppage time, triggering jubilant scenes among the Blaugrana

The result capped a season of domestic supremacy for the Catalan club. Since

suffering their last defeat in Spain late last year, Barcelona have remained unbeaten across domestic competitions. In addition to reclaiming the league title, they lifted the Spanish Super Cup in January and followed that up by defeating Madrid again in the Copa del Rey final.

"I think especially in the second part of the season we have been amazing. We haven't lost a game and that's just great. Congratulations to the team, the club and the fans. We are very happy with what we have achieved," Flick said.

"I don't think I had enough time to explain it throughout the season but I put a lot of value to the culture we have created, this family we have created," he added.Their dominance was most evident in their fierce rivalry with Los Blancos. Across four meetings this season in various competitions, Bara emerged victorious each time — a feat that highlighted not just tactical superiority but also their mental edge in key moments. Yamal, still only 17, played a decisive role in each of those encounters, further validating his rapid rise as one of the continent's most exciting young talents.Flick, who stepped in following Xavi Hernandez departure last year, was handed the responsibility of rejuvenating a transitional squad. In less than a full season, the German tactician has moulded the group into a cohesive and confident title-winning unit — delivering silverware and restoring belief at Camp Nou.

Karisma Kapoor's

Birthday Wish For Madhuri Dixit Came Gift-Wrapped Like This

Bollywood's evergreen dancing queen, Madhuri Dixit, turned 58 today, and wishes are pouring in from fans, friends, and celebrities across the industry. Amid the flood of heartfelt messages, one that especially stood out was from her Dil To Pagal Hai co-star, Karisma Kapoor.Karisma took to her Instagram Stories to post a beautiful throwback picture with Madhuri. In the photo, the two stars are seen sharing a sweet side hug, flashing big smiles at the camera. Both actresses are dressed in elegant sarees— Karisma in a striking red one, while Madhuri stuns in a silver saree with intricate embroidery. Together, they look absolutely gorgeous.Alongside the picture, Karisma wrote, "Happy Birthday MD Ji. Love you always," and added cake and balloon emojis to complete the post.

Take a look at the post here:Karisma and Madhuri shared screen space in the 1997 blockbuster Dil To Pagal Hai, which also starred Shah Rukh Khan in the lead. Directed by Yash Chopra, the romantic drama was a massive success and became the highest-grossing Bollywood film of that year. The film also swept major awards as it won three National Awards and seven Filmfare trophies, along with several other honours.

One of the most iconic moments from the film is the Dance of Envy sequence between Madhuri and Karisma. The intense dance-off filled with powerful moves and stunning choreography is still remembered and praised even today.While both actresses have made a strong mark in the industry over the years, they also have exciting projects lined up.Karisma will soon be seen in a web series titled Brown, where she stars opposite actor Surya Sharma. The series is directed by Abhinay Deo and is based on Abheek Barua's book City of Death."I've had a long career, I've been there, done that, done a variety of roles, but when I read the character Rita Brown, I just felt it, because she was so different, so diverse — she was flawed, but human, super smart, super intelligent, and you can literally see the growth of this woman. For me, as an actress to be stripped down of all the glamour and the glitz, that was extremely interesting for me," Karisma said about her character Rita Brown as quoted by Filmfare.

Madhuri will next be seen in a psychological thriller series called Mrs Deshpande, directed by Nagesh Kukunoor. As per reports, Madhuri will be playing the role of a serial killer in the show.

Raj Nidimoru's Ex-Wife Shhyamali Drops Cryptic Note Amid Samantha Dating Rumours: 'Everyone Who...'

As speculations about Samantha Ruth Prabhu and Raj Nidimoru's rumoured relationship continue to create a stir on social media, the director's former wife, Shhyamali De's, recent Instagram Story has caught everyone's attention. Shhyamali De took to her Instagram Story on Wednesday to share a positive message about love and blessings.The post read, "I send blessings and love to everyone who thinks of me, sees me, hears me, hears of me, speaks to me, speaks of me, reads of me, writes of me and meets me today." While she did not name anyone in the post, the note caught everyone's attention after Samantha Ruth Prabhu posted a cosy aeroplane selfie with Raj Nidimoru on the same day.

The actress' recent Instagram post has caused a frenzy online. In one image, Samantha is seen posing alongside Raj Nidimoru and the rest of the Subham team in front of the film's banner. But it was the second photo, a cosy in-flight selfie with Samantha resting her head on Raj's shoulder, that really got fans talking. While neither of them has confirmed the nature of their relationship, the affectionate snap has led many to wonder if Samantha is subtly making things official.

Who Is Raj Nidimoru's Ex-Wife?

While there is no confirmation on whether Raj is now dating Samantha, these rumours have spotlighted Raj's personal life, especially his ex-wife Shhyamali De. According to reports, Raj and Shhyamali tied the knot in 2015 but separated in 2022. Shhyamali De is a psychology graduate and has worked as an assistant director with Rakeysh Omprakash Mehra and Vishal Bhardwaj.

She is also a scriptwriter and has worked as a creative consultant for films like Rang De Basanti, Omkara, and Ek Nodir Golpo. In an old interview, Raj revealed that his wife has often helped him with casting in his projects. Notedly, Samantha Ruth Prabhu has frequently worked with Raj and DK.

Virat Kohli And Anushka Sharma Jet Out Of The City In Style

Virat Kohli and Anushka Sharma have lately been out and about in the city. Fresh off Virat's announcement of retirement from Test cricket, the couple first visited Vrindavan together and were captured touching down Mumbai after the spiritual outing. On Thursday, fans were treated to more glimpses of the lovebirds as they got spotted again at Mumbai airport. In a video, the lovebirds are seen heading to the terminal to board their flight.The video opens with Virat and Anushka arriving at the airport. While Anushka leads the way, Virat follows her to step out of the luxe vehicle. While en route, he made sure to acknowledge paparazzi, quickly waving hands at them. Anushka, too, turned around to greet the photographers with a smile.

Meanwhile, a rare video emerged online featuring Anushka Sharma and Virat Kohli with their munchkins, Vamika and Akaay. The video has caught attention for all the right reasons as it captured a heartwarming moment with Vamika adoring her baby brother. In the clip that has taken over social media, the couple is seen arriving at a house with their heart chunks. Upon their entrance, they are greeted with open arms by Anushka's mother. Later, she is also seen showering hugs and kisses on baby Akaay, holding him in her arms.

Before this, the actress is seen carrying baby Akaay as Vamika stands beside her, looking at her baby brother. Dressed in a white frock, Vamika looked the prettiest in the video whereas baby Akaay, in white tee and green pants, is cute at its peak. Virat, who also joined the family, exuded laid back charm in a brown T-shirt.

Anushka and Virat got married in 2017 in an intimate ceremony in Italy. The duo tied the knot after dating for several years. Later, the couple embraced parenthood, welcoming daughter Vamika in 2021. Together, they also welcomed their second child, Akaay, in 2024.

Nia Sharma

Flaunts Toned Figure in A Black Swimsuit, Fans Can't Keep Calm

Nia Sharma has once again set the internet on fire with her sizzling vacation photos. The actress shared a series of photos from her tropical getaway, where she flaunted her toned physique in a sleek black swimsuit. The bold look has garnered attention from fans, and the photos have gone viral on social media.Taking to her Instagram handle, Nia shared a series of photos in which she is seen enjoying a boat ride and also taking a dive in the seawater. Her choice of a black cut-out swimsuit accentuated her fit figure, and the images quickly went viral, with fans flooding the comments section with compliments and fire emojis.

Best known for her roles in some of the hit television serials, Nia Sharma is also a fashionista. The actor often takes to her social media to share her refreshing take on all things fashion and beauty. Nia recently shared a series of pictures of herself in a red mini dress, and her fans cannot get enough of this striking look.

Taking to her Instagram, Nia Sharma shared a series of pictures of herself in a red mini dress. She was seen striking some glamorous poses in front of the mirror as she got ready for her appearance. In one of the pictures, she was seen standing in front of the mirror as she touched up her makeup with a brush. Interestingly, the actor did her makeup all by herself. Sharing the pictures, she wrote, "Red hot peppers, flakes, smokes and some pesto sauce..Wild waves, gold chains, roses and my bronzed face."

For her recent look, Nia opted for a sleeveless mini dress. The dress came with a plunging V-neckline. While the overall dress was simple, it was the detailing at the hemline that elevated the overall look. The hemline of the dress was adorned with twisted fabric that resembled a boutique of roses. She paired this fitted mini dress with a pair of red wedge heels by Ferragamo.

For the accessories, Nia opted for a three-layered necklace, a giant hoop earring, dainty gold bracelets, and a set of gold rings. For the glam, she went with a flawlessly matte base. She defined her eyes with a rosy pink shade on her eyelids, eyeliner, and coats of mascara. She added a swipe of coral blush to her cheeks for that youthful glow. She went with a matte finish pink shade on her lips. She styled her hair in voluminous waves and left it open to complete her glamorous look.